सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh

RNI No :- DELHIN/2023/86499
DCP Licensing Number : F.2 (P-2) Press/2023

www.newsparivahan.com

परिवहन विशेष

वर्ष 03, अंक 61, नई दिल्ली, रविवार 11 मई 2025, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

अनुशासन एक ऐसा तरीका है जो उसमें कामयाब हो गया, वो हर कार्य में जीत सकता है।

03 सदर बाजार के पुनर्विकास के लिए CM रेखा गुप्ता ने लिया अहम निर्णय
06 मीडिया की आज़ादी को कृत्रिम बुद्धिमत्ता
08 जंग के बीच बड़ी खबर: सरकार ने राज्य के सभी जिला कलेक्टरों आरडीसी

"परिवहन विशेष हिन्दी दैनिक समाचार पत्र" अपने द्वितीय वार्षिकी समारोह में आपको आमंत्रित करता है

"परिवहन विशेष" हिन्दी दैनिक समाचार पत्र आर.एन.आई. द्वारा मान्यता प्राप्त आपके द्वारा प्राप्त भरपूर सहयोग से निष्पक्ष समाचार प्रदान करते हुए अपने 2 साल पूरे करने में सक्षम रहा। इन दो सालों में समाचार पत्र को निष्पक्ष रूप से चलाने में आप सभी का भरपूर सहयोग रहा जिसके लिए प्रशासनिक विभाग परिवहन विशेष आप सभी का दिल से आभार व्यक्त करता है और आशा करता है की भविष्य में भी आपका सहयोग हमारे साथ ऐसे ही बना रहेगा। इन दो सालों में समाचार पत्र को राष्ट्रीय स्तर पर सभी शहरों और जिलों तक पहुंचाने और वहां की सही और सच्ची खबरें हम तक पहुंचाने वाले रिपोर्टर्स का दिल से धन्यवाद।

---- सम्मान समारोह -----

दिनांक 17 मई 2025,
स्थान :- कंस्टीट्यूशन क्लब आफ इंडिया, रफी मार्ग, नई दिल्ली,
समय :- प्रात 10 बजे से शाम 7 बजे तक,

मुख्य अतिथि ₹श्री शंभू सिंह₹, आई.ए.एस. सचिव शिपिंग भारत सरकार (सेवा निवृत्त) शिपिंग मंत्रालय

आमंत्रित विशेष अतिथि

1. श्री चंद्रमोहन आईएएस सेवा निवृत
2. श्री अमर पाल सिंह जॉइंट कमिश्नर, भारत सरकार
3. श्री आर के भटनागर, आईएएस सेवा निवृत
4. साइकिलिस्ट योगेंद्र सिंह, परामर्शदाता
5. श्री एम के गिरी, अधिकृत वरिष्ठ अधिवक्ता उच्चतम न्यायालय भारत
6. श्री अनिल छिक्कारा, उपायुक्त परिवहन सेवा निवृत, परामर्शदाता
7. श्री महाराज सिंह, मोटर वाहन नियम/अधिनियम परामर्शदाता
8. श्री अजय शाह, सड़क सुरक्षा परामर्शदाता
9. पायलट अनिल शर्मा सड़क सुरक्षा परामर्शदाता
10. श्री प्रशांत चोपड़ा सड़क सुरक्षा परामर्शदाता
11. श्री राजीव शरद सड़क सुरक्षा परामर्शदाता
12. डॉ भरत सिंह, शिक्षाविद् (प्रिंस इंस्टीट्यूट आफ इन्नोवेटिव टेक्नोलॉजी ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश)
13. श्री हेतराम
14. श्री अशोक
15. श्री राहुल गुप्ता
16. श्री ए ई कौशिक
17. श्री अशोक सक्सेना
18. श्री अशोक नारंग
19. श्री बरुड ठाकुर अधिवक्ता उच्चतम न्यायालय भारत
20. श्री नरेन्द्र

के साथ भारत देश में जनहित एवम् कल्याणकारी कार्यों में योगदान प्रदान करने वाले कार्यकर्ताओं/ संस्थाओं / ट्रस्ट को सम्मान प्रदान किया जाएगा।

'परिवहन विशेष हिन्दी दैनिक समाचार पत्र" के द्वितीय वार्षिकी समारोह में मुख्य रूप से

1. सड़को को जाम और दुर्घटनाओं से मुक्त करवाने,
2. दिल्ली को प्रदूषण मुक्त राज्य बनाने,
3. लेन ड्राइविंग कितनी अनिवार्य?"
4. "सड़क दुर्घटना से कैसे हो सकता हैं बचाव ?"
5. "दिल्ली को प्रदूषण मुक्त राज्य कैसे बनाया जा सकता है?"

पर परामर्शदाताओं के विचार आप को प्राप्त होगे। इसके साथ इस समारोह में

1. वक्ताओं को पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा,
2. परिवहन क्षेत्र में अच्छा कार्य करने वाले संगठनों को पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा,
3. सड़क सुरक्षा के प्रति कार्य करने वाले संगठनों के पदाधिकारियों को पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा,
4. परिवहन विशेषज्ञों को पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा,
5. समाचार पत्र से अलग अलग राज्यों से जुड़े श्रेष्ठ एंकर, वीडियोग्राफर, रिपोर्टर्स, लेखक, ज्योतिषाचार्य, कवि एवम् सहायकों को सम्मानित किया जाएगा।

- संजय कुमार बाटला
संपादक

दिल्ली परिवहन आयुक्त द्वारा परिवहन विभाग की एसटीए एवं आपरेशन शाखा की कार्यप्रणाली एवं कार्य प्रक्रिया की समीक्षा के लिए गठित की गई कमिटी

संजय बाटला

नई दिल्ली। अतिरिक्त मुख्य सचिव एवम् आयुक्त परिवहन जिनकी नजर में तकनीकी पदों पर गैर तकनीकी अधिकारियों की कार्यशैली तकनीकी ज्ञान प्राप्त अधिकारियों से बेहतर है और जिनके द्वारा स्वयं तकनीकी पदों पर से तकनीकी अधिकारियों को हटा कर ग़ैर तकनीकी अधिकारियों को नियुक्त कर दिया गया वह भी बेख़ौफ़, माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों को दरकिनार कर।

उनके द्वारा एसटीए एवम् आपरेशन शाखा की कार्यप्रणाली ओर कार्य प्रक्रिया के आकलन के लिए एक कमेटी का गठन करना और उस कमेटी में ऐसे अधिकारियों का नाम प्रस्तुत करना जिनके पास अपने सर्विस के समय में कभी भी एस.टी.ए. के किसी पद पर ना तो कार्यरत रहे और ना ही उन्हें एसटीए के कार्य का अनुभव प्राप्त है और इसी कमेटी में एक ऐसे अधिकारी को नियुक्त करना जो अपने सेवा काल में टर्मिनेट हुआ हो इस बात को सिद्ध करता है की वह अपने पक्ष को सिद्ध करने की कोशिश करने के लिए ही इस कमेटी का गठन कर रहे हैं। क्योंकि इस कमेटी में नियुक्त किए गए तीनों अधिकारी पद पर रहते हुए उनके सबसे करीबी और उनकी हा में हा मिलाने के लिए विख्यात रहे हैं, ऐसे करीबी और अपने विश्वासपात्र अधिकारियों को कमेटी में नियुक्त कर कैसा निर्णय लिया जाएगा इसका अंदाजा आम आदमी लगा सकते हैं।

हम यहां सिर्फ एक प्रश्न अतिरिक्त मुख्य सचिव एवम् आयुक्त परिवहन से पूछना चाहते हैं, क्या वह अपने वाहन को किसी श्रेष्ठ मोची से ठीक करवाना पसंद करेंगे ? अगर उनका जवाब हा है तो जो वह कर रहे हैं सब ठीक है वर्ना आप समझ ही सकते हो की दिल्ली की सड़को पर चलने वाले मुसाफिरों का आने वाले समय मे क्या हाल होने वाला है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
परिवहन विभाग (एसटीए शाखा)
5/9 अंडर हिल रोड, दिल्ली-110054
सं.एफ. सचिव (एसटीए)/टीपीटी/2025/एसटीए/19843, दिनांकः-02-05-202
आदेश

परिवहन विभाग, जीएनसीटीडी में काम करने का व्यापक अनुभव रखने वाले निम्नलिखित सेवानिवृत्त अधिकारियों की एक समिति एसटीए शाखा और ऑपरेशन शाखा में प्रचलित कार्यप्रणाली और कार्य प्रक्रिया की व्यापक समीक्षा और आकलन करने के लिए गठित की जाती हैः

1. श्री अजय सामल, उप. आयुक्त (सेवानिवृत्त)
2. श्री सुभाष चंद, पीसीओ (सेवानिवृत्त)
3. श्री. सुशील अहलूवालिया, डीएएसएस कैडर (सेवानिवृत्त)

संदर्भ की शर्तें

1. समिति राज्य परिवहन प्राधिकरण तथा परिचालन शाखा, परिवहन विभाग द्वारा जारी सभी दिशा-निर्देशों/आदेशों/परिपत्रों की व्यापक समीक्षा करेगी, उनका एक सार-संग्रह तैयार करेगी तथा ऐसे निर्देशों को उपयोगकर्ता अनुकूल बनाने, स्वयं व्यवसाय करने में आसानी लाने के लिए सुझाव देगी तथा बदले हुए आर्थिक परिवेश के अनुरूप आवश्यक नए उपाय सुझाएगी।

2. उपर्युक्त 1 के संदर्भ में, समिति के सदस्य न्यायालय के आदेशों को ध्यान में रखेंगे तथा अन्य राज्यों की सर्वोत्तम प्रथाओं के आधार पर अपने सुझावों की तुलना करेंगे।

3. समिति के सदस्य इस कार्य आदेश जारी होने की तिथि से 45 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे

4. समिति के सदस्यों को उपरोक्त कार्य हेतु एकमुश्त 1 लाख रुपये (प्रत्येक) का भुगतान किया जाएगा।

यह आदेश अतिरिक्त मुख्य सचिव सह आयुक्त, परिवहन विभाग, जीएनसीटीडी के अनुमोदन और वित्त विभाग, जीएनसीटीडी की सहमति से यू.ओ. संख्या 14/एफ.आई.एन./डी.एस.आई./25-26 दिनांक 28-04-25 के तहत जारी किया जा रहा है।

जानकारी के लिए कॉपी :

1. माननीय परिवहन मंत्री, जीएनसीटीडी के निजी सचिव। से 2. अपर मुख्य सचिव सह आयुक्त (परिवहन), जीएनसीटीडी के निजी सचिव।
3. विशेष आयुक्त (संचालन), परिवहन विभाग, जीएनसीटीडी,
4. उप सचिव, राज्य परिवहन विभाग, जीएनसीटीडी।
5. सभी उप आयुक्त, परिवहन विभाग, जीएनसीटीडी।
6. उप लेखा नियंत्रक, परिवहन विभाग, जीएनसीटीडी।
7. वरिष्ठ सिस्टम विश्लेषक, परिवहन विभाग, जीएनसीटीडी।
8. सभी डीटीओएस/पीसीओ/एसओ, परिवहन विभाग, जीएनसीटीडी।
9. सहायक सचिव, राज्य परिवहन विभाग, जीएनसीटीडी।

दिल्ली में धड़ाधड़ कट रहे चालान, 2 महीने में 7000 से ज्यादा वाहनों पर हुई कार्रवाई

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पिछले दो महीनों में 7000 से ज्यादा कमर्शियल वाहनों के चालान काटे गए और 65 गाड़ियां जब्त की गईं। ये वाहन चालक नो एंट्री के समय में फर्जी परमिशन दिखाकर प्रवेश करते थे। पुलिस इस मामले में शामिल गिरोह का पता लगाने में जुटी है।

नई दिल्ली। दिल्ली यातायात पुलिस की ओर से फर्जी नो एंट्री परमिशन (एनईपी) प्रमाणपत्र के साथ अवैध कमर्शियल गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। यातायात पुलिस द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली के विभिन्न प्रमुख स्थानों पर जांच करते हुए पिछले दो महीनों में 7,654 चालान काटे गए और 65 कमर्शियल गाड़ियों को जब्त किया गया। यह गाड़ी चालक नो एंट्री के समय के फर्जी वैध परमिशन प्रमाण पत्र बना एंट्री कर रहे थे।

एडिशनल कमिश्नर (ट्रैफिक) सत्यवीर कटारा के मुताबिक, इसी वर्ष मार्च माह में ट्रैफिक पुलिस ने एक टीम बनाई थी, जिसका नेतृत्व इंस्पेक्टर रवि दत्त कर रहे हैं। 30 अप्रैल को आउटर रिंग रोड (मुकुंदपुर के पास) पर अचानक चेकिंग के दौरान, एएसआई राम अवतार ने एक लाइट गुड्स गाड़ी को रोका।

10 हजार रुपये में खरीदा था फर्जी प्रमाणपत्र

जांच के दौरान, ड्राइवर द्वारा प्रस्तुत एनईपी प्रमाणपत्र फर्जी पाया गया। तब उसे पकड़ जहांगीरपुर पुलिस को सौंप दिया गया। चालक लेख राज ने पूछताछ में बताया कि गाड़ी मालिक मोहम्मद अजीम ने यह फर्जी एनईपी प्रमाणपत्र सब्जी मंडी, आजादपुर में से 10 हजार रुपये में खरीदा था। इसी प्रकार, 7 मई को एसआई सुगन सिंह ने हनुमान मंदिर के पास रिंग रोड पर अचानक चेकिंग के दौरान एक अन्य कमर्शियल गाड़ी को रोका।

इस वाहन की विंडशील्ड पर एक फर्जी एनईपी चिपका हुआ था। उसे भी कश्मीरी गेट पुलिस को सौंप दिया गया। ड्राइवर, कमलेश यादव ने बताया कि उसका गाड़ी मोहम्मद आसिफ ने यह फर्जी प्रमाणपत्र 10 हजार रुपये में खरीदा था। इन दोनों मामलों में ड्राइवरों और गाड़ी मालिकों को गिरफ्तार कर लिया गया है।

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने की ये अपील

फर्जी एनईपी प्रमाणपत्र बनाने और बेचने वाले गिरोह के बारे में पता कर उनकी गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है। एडिशनल कमिश्नर ने बताया कि सभी ऑपरेटरों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जो फर्जी नो एंट्री परमिशन प्रमाणपत्र का इस्तेमाल करते पाए जाएंगे।

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि कमर्शियल गाड़ियों का संचालन कानूनी तरीके से हो। सभी भारी वाहन चालकों से ट्रैफिक पुलिस ने अपील की है वह ट्रैफिक नियमों का पालन करें। इसके साथ ही उन्हें फर्जी एनईपी प्रमाणपत्रों को नहीं खरीदने की अपील की गई है।

मदर्स डे आज

मां और बच्चे का रिश्ता दुनिया में सबसे अनमोल और खास होता है। इस रिश्ते की सबसे खास बात है। कि जन्म से पहले ही बन जाता है और जीवनभर आपके साथ रहता है। मां का रोल हमारे जीवन में बेहद अहम है। कोई भी बच्चा अपने जीवन में पहली सीख मां से ही लेता है। मां की भूमिका, त्याग और समर्पण को सम्मानित करने के लिए हर साल मई महीने के दूसरे रविवार को मदर्स डे मनाया जाता है। इस साल मदर्स डे को 11 मई को मनाया जा रहा है। मां के प्यार और त्याग के बारे में जितना भी कहें कम ही है। अपनी मां को स्पेशल फील करवाने के लिए ये एक अच्छा अवसर है।

मंदिर जाएं दिन की शुरुआत ईश्वर के आशीर्वाद से कर सकते हैं। घर के पास में कोई मंदिर हो तो मां के साथ सुबह मंदिर जाएं, जहां उनके साथ मिलकर पूजा करें। मंदिर आकर मां को सुकून भी मिलेगा और दिन की शुरुआत भगवान के दर्शन व आशीर्वाद से शुरू करने पर आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। अगर आप सुबह मंदिर नहीं जा सकते तो शाम की आरती में शामिल हो। इस समय मंदिर में कुछ वक्त बैठकर भजन या शांति को प्राप्त किया जा सकता है।

मां के साथ शॉपिंग अधिकतर महिलाओं को खरीदारी के लिए बाजार जाना पसंद होता है, खासकर अपने बच्चों के साथ। इस बार आप अपनी मां को किसी मॉल या पास की लोकल मार्केट ले जा सकते हैं। यहां दोनों मिलकर खरीदारी करें। जरूरी नहीं कि खरीदारी ही करें, विंडो शॉपिंग भी मां को उत्साहित कर देगी।

स्पा या पार्लर मां को स्किन केयर या रिलैक्स महसूस कराने के लिए स्पा या पार्लर ले जा सकते हैं। यहां मां के लिए पैकेज बुक करें। मेनिक्योर, पैडिक्योर, मसाज, फेशियल आदि उन्हें कुछ देर के लिए रिलैक्स होने का मौका देगा। साथ ही मां जो घर परिवार की जिम्मेदारी में अक्सर अपना ख्याल रखना भूल जाती हैं, वह यहां पहुंचकर खुश हो जाएंगी।

पिकनिक पर जाएं आप अपनी मां, उनकी मां यानी नानी या दादी को लेकर पिकनिक पर जा सकते हैं। मां की सहेलियों को भी पिकनिक के लिए इनवाइट कर सकते हैं। एक छोटी सी पिकनिक मां को बहुत खुश कर सकती है। गर्मी का मौसम है तो दिन में अगर पिकनिक प्लान नहीं कर सकते हैं तो शाम के वक्त शहर में स्थित किसी हेरिटेज स्थल, वॉटर पार्क या पिकनिक स्पॉट पर मजेदार वक्त बिताने जा सकते हैं।

महाभारत के बर्बरीक से श्रीकृष्ण ने क्यों दान में मांगा था शीश, ऐसे बने कलियुग के खाटू श्याम

हारे का सहारा खाटू श्याम के बारे में तो हम सभी ने सुना होगा। खाटू श्याम को कलियुग का देवता भी कहा जाता है। हालांकि लोगों के मन में यह जरूर उठता है कि इनको हारे का सहारा क्यों कहा जाता है।

हारे का सहारा खाटू श्याम के बारे में तो हम सभी ने सुना होगा। खाटू श्याम को कलियुग का देवता भी कहा जाता है। खाटू श्याम को श्रीकृष्ण का चमत्कारी रूप भी माना जाता है। कहा जाता है कि अगर बाबा के दरबार में भक्त सच्ची मनोकामना के साथ आता है, उसकी हर इच्छा खाटू श्याम जरूर पूरी करता है। हालांकि लोगों के मन में यह जरूर उठता है कि इनको हारे का सहारा क्यों कहा जाता है। ऐसे में आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको आखिर इसके पीछे की क्या कहानी है।

जानिए कौन हैं खाटू श्याम

पौराणिक कथाओं के मुताबिक खाटू श्याम का असली नाम बर्बरीक है। महाभारत में इनके पिता का नाम घटोत्कच और मां का नाम कामकंटकटा था। कुरुक्षेत्र में जब कौरव और पांडवों के बीच युद्ध चल रहा था, तो बर्बरीक भी मैदान में उतर पड़े थे। ऐसे में बर्बरीक ने यह प्रतिज्ञा ली कि जो भी पक्ष कमजोर होने लगेगा, वह उसका साथ देंगे। इसी वजह से उनको हारे का सहारा कहा जाता है। जब यह बात भगवान श्रीकृष्ण को पता चली, तो उनको यह भी पता था कि बर्बरीक को तीन बाणों से किसी भी लड़ाई को जीतने का आशीर्वाद प्राप्त है।

श्रीकृष्ण ने ली थी बर्बरीक की परीक्षा

एक बार श्रीकृष्ण ने बर्बरीक के पास जाकर उनकी परीक्षा ली। तब उन्होंने बर्बरीक से पीपल के पेड़ के सभी पत्तों को बाण से मारने को बोला। जिस पर बर्बरीक ने एक बाच चलाया और पीपल के पत्तों पर छेद हो गया। लेकिन श्रीकृष्ण ने एक पीपल के पत्ते को अपने पैर के नीचे दबा लिया। तब श्रीकृष्ण से बर्बरीक ने पैर हटाने के लिए कहा, जिससे वह उस पत्ते में भी छेद कर सकें। लेकिन श्रीकृष्ण ने पैर नहीं हटाया, जिस पर बर्बरीक ने ऐसा बाण चलाया कि उस आखिरी पत्ते में भी छेद हो गया और भगवान श्रीकृष्ण के पैर पर भी चोट लग गई।

मांग लिया था शीश

यह सब देखने के बाद श्रीकृष्ण हैरान रह गए और उनको पांडवों पर संकट दिखने लगा। तब अगले दिन वह बर्बरीक के पास ब्राह्मण के वेश में पहुंचे और उनसे भिक्षा में सिर मांगा। तब बर्बरीक ने ब्राह्मण से असली पहचान बताने के लिए कहा, तो श्रीकृष्ण ने उनको अपना दिव्य रूप दिखाया। भगवान का रूप देखकर बर्बरीक ने उनको सिर का बलिदान दे दिया। लेकिन श्रीकृष्ण ने उनको आशीर्वाद दिया कि वह कलियुग में श्याम के रूप में पहचाने जाएंगे। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की द्वादश तिथि में बर्बरीक ने सिर का बलिदान दिया था।

खाटू श्याम मंदिर

बताया जाता है कि बर्बरीक का सिर महाभारत युद्ध के बाद नदी में बहकर राजस्थान के सीकर जिले के खाटू शहर में पहुंच गया था। फिर 1027 ई. में राजा रूप सिंह चौहान और उनकी धर्मपत्नी नर्मदा कंवर को बर्बरीक का सिर मिला। जिस तालाब से बर्बरीक की सिर मिला था, उससे कुछ दूरी पर उन्होंने खाटू श्याम मंदिर का निर्माण कराया।

हालांकि मुगल शासक बादशाह औरंगजेब ने अपने शासनकाल में खाटू श्याम के पुराने मंदिर को तुड़वा दिया था और उस स्थान पर मस्जिद खड़ी कर ली थी। लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1720 ई में अभय सिंह ने नया खाटू श्याम मंदिर बनवाया। जहां पर आज भी लोग दर्शन के लिए जाते हैं।

बच्चों के लिए एंटीबायोटिक का इस्तेमाल हो सकता है खतरनाक, जानिए क्या कहते हैं एक्सपर्ट

एंटीबायोटिक दवा बैक्टीरिया से होने वाले संक्रमण हो ठीक करती हैं। लेकिन आज हम आपको 5 ऐसे कारण बताने जा रहे हैं, जिससे आपको यह समझने में आसानी होगी कि बच्चों को एंटीबायोटिक देने से पहले डॉक्टर की सलाह लेना क्यों जरूरी होता है।

आजकल बच्चों को मामूली सी बीमारी में एंटीबायोटिक खिलाना आम बात हो गई है। हालांकि यह चिंता की बात नहीं है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि एंटीबायोटिक दवाओं का अधिक इस्तेमाल या फिर बिना सोच-समझकर देना बच्चों की सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है। भले ही एंटीबायोटिक दवा बैक्टीरिया से होने वाले संक्रमण हो ठीक करती हैं, लेकिन अगर आप बार-बार या फिर गलत तरीके से इसे देते हैं, तो इसका आपके शरीर पर उल्टा असर हो सकता है। इसलिए आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको 5 ऐसे कारण बताने जा रहे हैं, जिससे आपको यह समझने में आसानी होगी कि बच्चों को एंटीबायोटिक देने से पहले डॉक्टर की सलाह लेना क्यों जरूरी होता है।

एंटीबायोटिक दवाएं

जब बच्चे को बार-बार एंटीबायोटिक दी जाती है, तो कुछ बैक्टीरिया इन एंटीबायोटिक से लड़ना सीख जाते हैं। इससे यह दवा काम नहीं करती है और मामूली संक्रमण भी खतरनाक बन जाते हैं।

कम हो जाती है ताकत

अगर हर बार बच्चे को दवा दी जाती है, तो शरीर को बीमारी से खुद लड़ने का मौका नहीं मिल पाता है। इससे भी बच्चे का इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर हो जाता है। इससे बार-बार वह बीमार पड़ने लगते हैं।

खराब पाचन

एंटीबायोटिक दवा सिर्फ बुरे बैक्टीरिया ही नहीं बल्कि अच्छे बैक्टीरिया को भी मार देती है। इसमें वह बैक्टीरिया भी होते हैं, जो पेट को सही रखने में मदद करते हैं। इससे पेट दर्द, अपच और गैस की समस्या हो सकती है।

एलर्जी का खतरा

कुछ बच्चों को एंटीबायोटिक देने से खुजली, रैश या फिर सांस लेने में परेशानी जैसी समस्या हो सकती है। इसलिए बेहतर है कि उनको एंटीबायोटिक न दें और अगर दे रहे हैं, तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें।

वायरल बीमारी

सर्दी-जुकाम या फ्लू जैसे वायरल संक्रमण होने पर एंटीबायोटिक काम नहीं करती है। अगर एंटीबायोटिक दी भी जाती है, तो वह सिर्फ नुकसान करती है। इसलिए बेहतर होगा कि आप बच्चे को दवा न दें।

पेट दर्द जैसे साइड इफेक्ट्स

दवा के कारण बच्चों को उल्टी, मतली, पेट दर्द या फिर चकत्ते जैसे दुष्प्रभाव हो सकते हैं। हालांकि कुछ मामलों में यह लक्षण हल्के होते हैं और खुद से ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर यह लक्षण अधिक बढ़ जाते हैं, तो बच्चे को परेशानी होती है। ऐसी स्थिति में फौरन डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए।

बार-बार होने लगते हैं बीमार

जब दवा की आदत हो जाती है, तो फिर शरीर बिना दवा के ठीक नहीं हो पाता है। वहीं बार-बार संक्रमण होता रहता है। वहीं थोड़ी सी बीमारी में भी बच्चा बिना दवा के ठीक नहीं हो पाता है।

पोषक तत्व

खाने से मिलने वाली विटामिन और मिनरल्स सही से शरीर में नहीं पहुंच पाते हैं, जिससे पेट के अच्छे बैक्टीरिया खत्म होने लगता हैं। इस वजह से बच्चे की ग्रोथ रुक सकती हैं। वहीं पोषक तत्वों की कमी से बच्चे की एनर्जी लेवल, विकास और बढ़त पर असर पड़ सकता है।

कमजोर इम्यून सिस्टम

बता दें कि हर बार दवा देने से बच्चे की इम्यून सिस्टम पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाता है। जिसकी वजह से बड़े होकर भी वह बीमारियों के प्रति कमजोर रह जाते हैं।

फटी एड़ियों (बिवाई) का घरेलु उपचार

फटी एड़ियि बहुत कष्टकारी होती हैं, कई बार तो एड़ियि इतनी फट जाती हैं के इनमे खून तक आने लग जाता हैं, ऐसे में हम तरह तरह के उपाय करते हैं और महंगी क्रीम भी इस्तेमाल करते हैं मगर आराम नहीं मिलता। आज हम आपको बता रहे हैं एक ऐसा घरेलु नुस्खा जिसको अपनाने से आपको पहले दिन से ही आराम मिलना शुरू होगा और थोड़े दिनों में ही आपकी एड़ियि पहले के जैसे हो जाएँगी।

तो क्या हैं ये नुस्खा आइये जाने।

सामग्री

सरसों का तेल 50 मि ली

देशी मोम 25 ग्राम

देशी कपूर 5 ग्राम

बनाने की विधि

सरसों के तेल को गर्म करे, जब ये तेल उबलने लगे, तो इसमें धीरे धीरे मोम मिला दीजिये। जब मोम पूरी तरह घुल कर मिल जाए, तो आग बंद कर दे और बर्तन को आंच से उतार लीजिये अब इसको ठंडा होने दे। जब ये थोड़ा गुनगुना रह जाए तो इसमें कपूर मिला लीजिये। अभी ये बिवाईयों के लिए बहुत बढ़िया मलहम बन गया।

लगाने की विधि रात को पैरो को अच्छी तरह गर्म पानी से धो कर इस मलहम को बिवाईयों में लगाइये, आपको पहले दिन से आराम मिलने लगेगा।

कूलर के ये जुगाड़ करेंगे गर्मी से निजात, अब AC की जरूरत नहीं

कूलर में बर्फ डालने से ठंडक थोड़ी देर के लिए तो बढ़ सकती है, लेकिन बर्फ जल्दी ही पिघल जाती है और ठंडक खत्म हो जाती है। हालांकि, किचन में छुपा हुआ एक हैक है, जिससे आपका कूलर एसी जैसा ठंडा हो सकता है।

गर्मी में कूलर एक सस्ती और प्रभावी ठंडक देने वाला विकल्प बनकर उभरता है, लेकिन अक्सर हम इसका सही तरीके से उपयोग नहीं करते, जिससे कूलर की कूलिंग क्षमता पूरी तरह से नहीं मिल पाती। अगर आप चाहते हैं कि आपका कूलर आपको एसी जैसी ठंडक दे, तो इन आसान हैक्स को अपनाकर आप गर्मी से राहत पा सकते हैं। इन जुगाड़ों से आपका कूलर बिना किसी परेशानी के पूरी गर्मी के मौसम में आपको ठंडी हवा देगा।

1. कूलर में लगाएं मिट्टी का मटका

गर्मी में मिट्टी के बर्तनों का पानी स्वाभाविक रूप से ठंडा रहता है। इसी सिद्धांत का उपयोग करके, आप कूलर के पानी में ठंडक का असर बढ़ा सकते हैं। इसके लिए, एक बड़ा मिट्टी का मटका लें और इसके नीचे छेद करें ताकि कूलर का पंप इसके बीच से होकर पानी खींच सके। यह जुगाड़ कूलर को चिल्ड हवा देने में मदद करेगा, जिससे आपके कमरे की ठंडक काफी बढ़ जाएगी। इस प्रक्रिया के दौरान ध्यान रखें कि कूलर को सीधे धूप से बचाया जाए, और वह खुले स्थान पर रखा हो। ऐसा करने से आपका कूलर शिमला जैसी ठंडी हवा देने लगेगा।

2. कूलर से घास हटाएं और नई तकनीक अपनाएं

अगर आपके कूलर में साधारण घास (कूलर पैड) लगी हुई है, तो यह कूलर की कूलिंग पावर को पूरी तरह से इस्तेमाल करने में सक्षम नहीं हो पाती है। इसके बजाय, हनीकॉम्ब पैड का उपयोग करें। ये पैड कूलिंग को दोगुना करने में मदद करते हैं। साथ ही, कूलर के पानी का स्तर नियमित रूप से मेंटेन करें, ताकि अंदर का तापमान ठंडा बना रहे। यह तरीका अपनाने से आपका कूलर कई घंटों तक ठंडी हवा देगा, जिससे आपको एसी का इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी।

3. ठंडक का राज रसोई में है

कूलर में बर्फ डालने से ठंडक थोड़ी देर के लिए तो बढ़ सकती है, लेकिन बर्फ जल्दी ही पिघल जाती है और ठंडक खत्म हो जाती है। हालांकि, किचन में छुपा हुआ एक हैक है, जिससे आपका कूलर एसी जैसा ठंडा हो सकता है। कूलर के पानी में थोड़ा नमक मिलाने से बर्फ का पिघलने का समय बढ़ जाता है। नमक डालने से पानी की ठंडक लंबे समय तक बनी रहती है। इसके साथ ही, कूलर में 10-20 रुपये की बर्फ डालकर देखिए, इससे आपकी ठंडक दोगुनी हो जाएगी। इसके अलावा, कूलर को ऐसी जगह रखें जहां हवा का प्रवाह हो, जैसे कि क्रॉस वेंटिलेशन वाला स्थान।

4. पर्दे की सफाई से कूलिंग बेहतर करें

कभी-कभी कूलर का पर्दा (कूलर पैड) ठीक से गीला नहीं होता और इससे कूलर की कूलिंग क्षमता घट जाती है। पर्दे पर मिट्टी और गंदगी जमा हो जाने से पानी सही से पैड तक नहीं पहुंच पाता। इसलिए, कूलर के पर्दे पर बने छेदों को किसी नुकीली चीज से खोलें और सुनिश्चित करें कि पर्दा पूरी तरह से गीला हो। इसके बाद आप पाएंगे कि कूलर पहले से ज्यादा ठंडक दे रहा है। यह छोटा सा हैक आपके कूलर को एसी जितना ठंडा बना सकता है।

5. कूलर को सही दिशा में रखें

कूलर की सही दिशा भी ठंडक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कूलर को ऐसी जगह रखें जहां बाहर से ताजगी भरी हवा आ सके। यह क्रॉस वेंटिलेशन कूलर को अधिक प्रभावी बनाता है और ठंडी हवा की सप्लाई को बेहतर करता है। जब कूलर में हवा का सही दिशा में आना होता है, तो यह कमरे के तापमान को तेजी से कम कर देता है और ठंडक का असर बढ़ा देता है।

इन सभी आसान हैक्स को अपनाकर आप अपनी गर्मी की परेशानियों से निजात पा सकते हैं। जुलाई तक आपको रजाई की जरूरत पड़ने लगेगी!

बच्चे को लंच बॉक्स में बनाकर दें लौकी के अप्पे, चट कर जाएंगे पूरा टिफिन

अगर आपका बच्चा भी हरी सब्जियां खाने में आनाकानी करता है और वह हर रोज टिफिन बॉक्स बचाकर ले आता है, तो यह आर्टिकल आपके लिए है। आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपके लिए एक हेल्दी टिफिन बॉक्स रेसिपी लेकर आए हैं।

हर बच्चा खाना खाने में आनाकानी करता है। ऐसे में बच्चे को खाना खिलाना एक बड़ा और मुश्किल टास्क बन जाता है। वहीं बच्चे हरी सब्जियां खाने से भागते हैं। जबकि उनको बाहर का जंक फूड खाना बहुत पसंद होता है। ऐसे में मां के लिए बहुत बड़ी मुश्किल यह होती है कि वह बच्चे को ऐसा क्या बनाकर दें, जोकि खाने में टेस्टी होने के साथ हेल्दी भी हो। क्योंकि यह तो हम सभी जानते हैं कि हरी सब्जियां सेहत के लिए फायदेमंद होती है। फिर चाहे वह बच्चा हो या बड़ा।

बॉडी ग्रोथ से लेकर शरीर में कई तरह के पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के लिए हरी सब्जियां बेहद फायदेमंद होती है। इसलिए इन हरी सब्जियों को किसी न किसी रुप में बच्चे को जरूर खिलाना चाहिए। अगर आपका बच्चा भी हरी सब्जियां खाने में आनाकानी करता है और वह हर रोज टिफिन बॉक्स बचाकर ले आता है, तो यह आर्टिकल आपके लिए है। आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपके लिए एक हेल्दी टिफिन बॉक्स रेसिपी लेकर आए हैं। जिसको आप अपने बच्चे को बनाकर दे सकती हैं। आप अपने बच्चे को टिफिन में लौकी के अप्पे बनाकर दे सकती हैं, यह स्वादिष्ट होने के साथ हेल्दी डिश भी है।

ऐसे बनाएं लौकी के अप्पे

सबसे पहले एक बर्तन में सूजी ले लें।

फिर इसमें खट्टा दही या छाछ डालकर मिक्स करें और थोड़ी देर फूलने के लिए छोड़ दें।

सूजी के फूल जाने के बाद इसमें चने की दाल भूनकर, करी पत्ते, राई और नमक डालकर मिक्स करें।

अब इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स भूनकर डालें और नारियल पाउडर डाल दें।

इसके बाद ऊपर से लौकी का पेस्ट और कद्दूकस की लौकी डालकर थोड़ा सा पानी मिलाकर अच्छे से मिक्स करें।

फिर इसमें बेकिंग सोडा या ईनो डालें।

अब इस मिश्रण को अप्पे पैन में तेल लगाकर डालें।

इन बातों का रखें खास ध्यान

अप्पे का मिश्रण बनाने के दौरान हमेशा खट्टी दही या छाछ का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे अप्पे फूलते हैं।

अप्पे के मिश्रण में थोड़ी सी चने की दाल डालने से इसका टेस्ट बढ़ जाता है।

लौकी के अप्पे बनाने के लिए लौकी को कद्दूकस या फिर पेस्ट दोनों तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं।

लौकी के अप्पे बनाने के लिए सूजी के घोल को थोड़ी देर के लिए फूलने को रख दें।

पराली जलाने पर लगेगी लगाम, हर गांव में खेतों की होगी मैपिंग, निगरानी को तैनात होगा सुरक्षा बल

परिवहन विशेष न्यूज

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने एनसीआर राज्यों को पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए पराली सुरक्षा बल गठित करने का निर्देश दिया है। हर गांव में खेतों की मैपिंग होगी और किसानों के समूह बनाकर नोडल अधिकारी निगरानी करेंगे। रात में पराली जलाने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा।

नई दिल्ली: एनसीआर में अक्टूबर व नवंबर में स्थानीय कारणों के साथ-साथ प्रदूषण का एक बड़ा कारण पराली का धुआं भी होता है। इस वजह से एनसीआर में प्रदूषण का संकट बढ़ जाता है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) शुक्रवार को एनसीआर से संबंधित हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश सरकार को पराली जलाने से रोकने जिला व ब्लाक स्तर पर पराली सुरक्षा बल के गठन का निर्देश दिया।

जिसमें पुलिस अधिकारी, कृषि विभाग के अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, नोडल अधिकारी व अन्य अधिकारी शामिल होंगे। यह पराली सुरक्षा बल पराली जलाने की घटनाओं को रोकेंगे।

हर गांव में हर खेत की मैपिंग भी कराने का निर्देश दिया

साथ ही सीएक्यूएम ने हर गांव में हर खेत की मैपिंग भी कराने का निर्देश दिया है। CAQM ने हर जिले में 50-50 किसानों का समूह बनाकर उसके एक नोडल अधिकारी के साथ टैग करने का निर्देश दिया है।

सभी किसान ऐसे समूह में शामिल किए जाएंगे और नोडल अधिकारी समूह से जुड़े किसानों की निगरानी करेंगे।

इसके अलावा देर शाम व रात के वक्त सतर्कता एजेंसियों भी गश्त करेंगी। सीएक्यूएम ने कहा है कि सेटेलाइट की निगरानी से बचने के लिए रात में पराली जलाने की प्रवृति होती है।

इसलिए सतर्कता एजेंसियां गश्त कर पराली जलने वाले खेत के रिकार्ड में लाल प्रविष्टयां दर्ज करेंगे और पराली जलाने वाले किसानों पर जुर्माने के रूप में पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क भी लगाया जाएगा।

हायरिंग सेंटर में सीआरएम मशीनों की उपलब्धता सुनिश्चित होगी

सीएक्यूएम ने सीआरएम (क्राप रेसिडुअल मैनेजमेंट) मशीनों की उपलब्धता की समीक्षा करने का भी निर्देश दिया है। इसके तहत एनसीआर से संबंधित राज्यों को पराली के प्रबंधन के लिए इस्तेमाल होने वाली पुरानी मशीनों को हटाना होगा।

साथ ही आवश्यकता के अनुसार अगस्त तक नई मशीनों की खरीद सुनिश्चित करनी होगी। इसके अलावा सीएचसी (कस्टम हायरिंग सेंटर) में पर्याप्त सीआरएम मशीनों की उपलब्ध सुनिश्चित करनी होगी।

छोटे और आर्थिक रूप से कमजोर किसानों को यह मशीनें निशुल्क उपलब्ध कराई होगी। इसके अलावा पराली के भूसे के प्रबंधन और भंडारण की व्यवस्था करने का निर्देश भी दिया गया है।

पराली खरीद के लिए एक समान दर निर्धारित करने को कहा

सीएक्यूएम ने कहा है कि हरियाणा की तरह उत्तर प्रदेश व पंजाब में पराली के खरीद के लिए एक समान दर निर्धारित होना चाहिए और पराली के भूसे की खपत के लिए जिला स्तर पर सप्लाई चेन प्रबंधन होना चाहिए।

सीएक्यूएम ने एक आनलाइन प्लेटफार्म बनाकर पराली और सीआरएम मशीनों की उपयोगिता का निगरानी करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा पराली का औद्योगिक इकाइयों में इस्तेमाल बढ़ाने का प्रबंध करने का भी निर्देश दिया है।

दिल्ली का हर बच्चा होगा शिक्षित, सरकार का खास प्लान तैयार; टीचर करेंगे ये काम

दिल्ली सरकार ने वंचित छात्रों को स्कूलों में वापस लाने के लिए एक योजना शुरू की है। शिक्षकों को गलियों और झुग्गियों में भेजकर बच्चों की पहचान कराएगी और उनका दाखिला कराएगी। छह से 18 साल के बच्चों को उनकी उम्र के अनुसार कक्षाओं में प्रवेश मिलेगा भले ही उनके पास दस्तावेज न हों। इसका मुख्य उद्देश्य दिल्ली का हर बच्चा होगा शिक्षित सुनिश्चित करना है।

नई दिल्ली। अब दिल्ली सरकार ने स्कूली शिक्षा से वंचित छात्रों को वापस दिल्ली भर के स्कूलों में शामिल करने की कवायद शुरू कर दी है। इसके तहत दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग के अधीन आने वाली संस्था समग्र शिक्षा ने इन बच्चों की पहचान कर उन्हें फिर से कक्षाओं में दाखिला दिलाने और उन्हें सुचारू रूप से नियमित सरकारी स्कूलों में शामिल करने के लिए एक विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार की है।

निदेशालय के एक अधिकारी ने बताया कि छात्रों की शिक्षा में अंतर को पाटने और उन्हें उनकी उम्र के हिसाब से कक्षा में मुख्यधारा में लाने के लिए यह मसौदा तैयार किया गया है।

ड्राफ्ट के अनुसार, स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर टीचर्स (एसटीसी) द्वारा साल में दो बार यानी गर्मी और सर्दी की छुट्टियों के दौरान नियमित सर्वेक्षण किया जाएगा। हर क्लस्टर में कम से कम एक सर्वेक्षण टीम जाएगी। साथ ही, मंगोलपुरी, जनकपुरी, नांगलोई, वजीरपुर, संगम विहार और उत्तर पूर्वी दिल्ली के इलाकों में भी अधिक टीमें जा सकती हैं। क्योंकि यहां स्कूल न जाने वाले बच्चों के मिलने की संभावना अधिक है।

जिला शिक्षा उपनिदेशक की आवश्यकताओं और आकलन के अनुसार, टीम में एक विशेष शिक्षा शिक्षक होना चाहिए, जो विकलांग बच्चों की पहचान कर सके।

इस उम्र के बच्चों पर सरकार का ध्यान

सर्वेक्षण टीम के सदस्य यह सुनिश्चित करेंगे कि छह से 14 वर्ष की आयु के बीच जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं या स्कूल छोड़ चुके हैं, उनकी पहचान की जाए और उन्हें 18 वर्ष की आयु तक उनकी आयु के अनुसार उपयुक्त कक्षाओं में दाखिला दिया जाए।

साथ ही, जिला शिक्षा उपनिदेशकों (डीडीई) को अपने अधिकार क्षेत्र में ऐसे क्षेत्रों की पहचान करनी होगी, जहां ऐसे बच्चों के होने की अधिक संभावना है, जो स्कूल नहीं जा रहे हैं। इसके लिए निदेशालय ने डीडीई को अनधिकृत कॉलोनियों, औद्योगिक क्षेत्रों, निर्माण स्थलों, रेलवे स्टेशनों पर जाकर ऐसे छात्रों की पहचान करने का निर्देश दिया है। बच्चे की पहचान हो जाने के बाद, सर्वेक्षण टीम के सदस्यों द्वारा माता-पिता या अभिभावकों से सभी प्रासंगिक जानकारी एकत्र की जाएगी। सर्वेक्षण टीम पहचाने गए बच्चों के प्रवेश और शिक्षा के संबंध में अभिभावकों को परामर्श और मार्गदर्शन देगी। इन पहचाने गए बच्चों को आसानी से सरकारी, निगम, एनडीएमसी या दिल्ली छावनी बोर्ड के निकटतम नियमित स्कूल में और बाद में बच्चे की जरूरतों और योग्यता के आधार पर निकटतम विशेष प्रशिक्षण केंद्र में दाखिला दिलाया जाएगा। निदेशालय ने कहा कि यदि किसी स्कूल में एसटीसी नहीं है तो प्रिंसिपल मौजूदा शिक्षण स्टाफ के साथ वैकल्पिक व्यवस्था करके ऐसे विद्यार्थियों की शिक्षा की खाई को पाटेंगे।

अंबेडकर विश्वविद्यालय ने छात्राओं के लिए शुरू की ई-रिक्शा सेवा, यहां देखें टाइमिंग और लोकेशन

डॉ. बीआर अंबेडकर विश्वविद्यालय ने छात्राओं के लिए निशुल्क ई-रिक्शा सेवा शुरू की है। यह सेवा कश्मीरी गेट और करमपुरा परिसर से मेट्रो स्टेशनों तक शाम 5 से 7 बजे तक उपलब्ध होगी। विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्राओं की सुरक्षा और कल्याण को ध्यान में रखते हुए यह पहल की है जो उनके सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। डॉ. बीआर अंबेडकर विश्वविद्यालय, दिल्ली ने विश्वविद्यालय की छात्राओं के लिए एक नई ई-रिक्शा सेवा शुरू की है। इस पहल से छात्राओं को सुरक्षित और सुविधाजनक परिवहन सुविधा मिलेगी।

इस जगह से चलेंगी ई-रिक्शा

यह ई-रिक्शा सेवा कश्मीरी गेट और करमपुरा परिसर से क्रमशः कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन और कीर्ति नगर मेट्रो स्टेशन तक संचालित की जाएगी। छात्राएं शाम पांच बजे से सात बजे तक इस सेवा का निःशुल्क लाभ उठा सकेंगी।

इस अवसर पर कुलपति प्रो. अनु सिंह लाठर ने कहा, ₹हम अपनी छात्राओं की सुरक्षा और कल्याण को सर्वोपरि मानते हैं। यह ई-रिक्शा सेवा हमारी छात्राओं को सुरक्षित और सुविधाजनक परिवहन विकल्प प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।₹

यह कदम छात्राओं के प्रति विश्वविद्यालय प्रशासन की प्रतिबद्धता और सशक्तिकरण की सोच को दर्शाता है।

युद्ध के दौरान फिर अस्तित्व में आएगा 'राष्ट्रीय मजदूर मोर्चा', प्रदर्शन स्थगित करने का निर्देश

भारतीय मजदूर संघ ने युद्ध जैसी स्थिति को देखते हुए राष्ट्रीय मजदूर मोर्चा को पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया है। यह मोर्चा देश भर के मजदूर संगठनों को एक मंच पर लाएगा ताकि युद्ध के समय सामान्य व्यवस्था बनाए रखने में मदद मिल सके। बीएमएस ने सभी राष्ट्रवादी ट्रेड यूनियनों से संपर्क करने का फैसला किया है और देश के वीर सैनिकों के साथ एकजुट रहने का आह्वान किया है।

नई दिल्ली। मजदूर समाज पाकिस्तान से युद्ध की स्थिति में देश के साथ पूरी एकजुटता व मजबूती से खड़ा है। ऐसे में पूर्व के युद्धों की तरह फिर "राष्ट्रीय मजदूर मोर्चा" को अस्तित्व में लाने की दिशा में काम शुरू हो गया है।

मौजूदा हालात को देखते हुए देश के प्रमख मजदूर संगठन भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस) ने इस दिशा में आगे बढ़ने का निर्णय लिया है। इसके लिए विभिन्न स्तरों पर राष्ट्रवादी ट्रेड यूनियनों से संपर्क किया जाएगा। देश में प्रमुख 11 मजदूर संगठन है, जबकि राज्य व स्थानीय स्तर पर इसकी संख्या कई हजार है।

युद्ध के दौरान देश में हो सामान्य व्यवस्था

यह ऐसा मोर्चा होगा, जिसमें देशभर के मजदूर संगठन, क्षेत्र व कार्य क्षेत्र से ऊपर एक मंच पर होंगे तथा युद्ध में देश में सामान्य व्यवस्था बनाए रखने में जोर लगाएंगे। बीएमएस के एक पदाधिकारी के अनुसार, इस संबंध में वाम व कांग्रेस पार्टी के साथ अन्य दलों से जुड़े मजदूर संगठनों से भी संपर्क किया जाएगा।

इसके पूर्व वर्ष 1962, 1965 और 1971 के युद्धों के दौरान भी ऐसा मजदूर मोर्चा अस्तित्व में आया था। युद्ध के समय खासकर रक्षा, रेलवे, नागरिक उड्डयन, दूरसंचार, स्वास्थ्य, बिजली, वैज्ञानिक प्रतिष्ठान, राज्य और केंद्र सरकार के कर्मचारी, अंतरिक्ष कर्मचारी, सड़क परिवहन और अन्य सहित कई विभाग और क्षेत्र निर्णायक स्थिति में होते हैं।

बीएमएस ने यह निर्णय वर्चुअल माध्यम से हुई केंद्रीय कार्य समिति की बैठक में लिया है। संगठन के महासचिव रविंद्र हिमटे ने कहा कि इस महत्वपूर्ण मोड़ पर देश को अपने वीर सैनिकों के साथ एकजुट रहना चाहिए। 1962 से लेकर कारगिल युद्ध तक बीएमएस का यहीं रुख था।

बीएमएस के दिशानिर्देश :-

सभी प्रकार की हड़तालों, आंदोलनों, प्रदर्शनों और अन्य प्रकार की ट्रेड यूनियन कार्रवाइयों को स्थगित करें।

जब तक बहुत जरूरी न हो, छुट्टी न लें। छुट्टी ली हो तो उसे रद्द कर दें और तुरंत अपनी ड्यूटी पर लौट आएं।

आवश्यक हो तो ओवरटाइम काम करें और बिना कोई शुल्क लिए उत्पादकता बढ़ाएं।

युद्ध जैसी परिस्थितियों के दौरान आवश्यक सावधानियों के बारे में श्रमिकों और आम जनता के बीच जागरूकता बढ़ाएं।

भारतीय रक्षा बलों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करें। नागरिक सुरक्षा कार्यों, रक्तदान कार्यक्रमों, स्थानीय परिवहन और अन्य प्रासंगिक पहलों में जिला प्राधिकारियों के साथ सहयोग करें।

जिला और उद्योग स्तर पर भारतीय सशस्त्र बलों को समर्थन देने के लिए एकजुटता कार्यक्रम आयोजित करें।

गुरुग्राम के कैब ड्राइवर को दिल्ली में लूटा, पत्थर फेंककर विंडशील्ड तोड़ी; फिर मोबाइल छीन भागे

दिल्ली के सुभाष प्लेस इलाके में गुरुग्राम के एक कैब ड्राइवर से मारपीट और लूटपाट हुई। दिल्ली हाट के पास बुकिंग का इंतजार कर रहे ड्राइवर की कार पर पत्थर फेंके गए और उसका मोबाइल छीन लिया गया। ड्राइवर ने पीछा करके आरोपियों को पकड़ा तो उनके साथियों ने ड्राइवर के साथ मारपीट की और पर्स लूट लिया जिसमें 11 हज़ार 700 रूपए थे।

दिल्ली। राजधानी के सुभाष प्लेस थाना क्षेत्र में गुरुग्राम (हरियाणा) के कैब ड्राइवर से मारपीट के बाद लूट का मामला सामने आया है। कैब ड्राइवर दिल्ली हाट के सामने बुकिंग का इंतजार कर रहा था, इसी दौरान दो युवकों ने पहले पत्थर फेंक कर उसकी कार की विंडशील्ड तोड़ दी और फिर मोबाइल फोन छीन भागने लगे।

कैब ड्राइवर ने पीछा कर दोनों को रोका और मोबाइल वापस लेने की कोशिश की। इसी दौरान कार में उनके दो साथी और आ गए। इसके बाद मारपीट कर कैब ड्राइवर का पर्स व नगदी छीन कर फरार हो गए। पुलिस ने चारों आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है।

विंडशील्ड और बाईं ओर की खिड़की टूट गई

उत्तर-पश्चिम जिले के सुभाष प्लेस थाना पुलिस को दी शिकायत में पीड़ित तालीम ने बताया कि वह कैब ड्राइवर है और गुरुग्राम में सेक्टर-65 स्थित जेएमडी होटल के पास झुग्गी में रहता है। सात मई को तड़के लगभग 3:30 बजे उसने अपनी कार दिल्ली हाट के सामने खड़ी कर नई बुकिंग का इंतजार कर रहा था। उसी समय दो व्यक्ति स्कूटर पर आए और पीछे बैठे व्यक्ति ने अचानक कार पर पत्थर फेंका, जिससे सामने की विंडशील्ड और बाईं ओर की खिड़की टूट गई।

कोहाट एन्क्लेव मेट्रो स्टेशन के पास रोक लिया

इसके बाद उसका मोबाइल फोन छीन लिया और दोनों मधुबन चौक की ओर भाग गए। तालीम ने बताया कि अपने वाहन से दोनों का पीछा किया और कोहाट एन्क्लेव मेट्रो स्टेशन के पास रोक लिया। फोन वापस मांगा तो उन्होंने उसके साथ मारपीट की और उसकी कार की चाबी छीन ली। इसी दौरान वैगन-आर कार में उनके दो साथी और आ गए, इसके बाद चारों ने हमला किया और उसका पर्स लूट लिया। पर्स में 11 हजार 700 रुपये नकद और उसका ड्राइविंग लाइसेंस था।

सीसीटीवी कैमरे के फुटेज का विश्लेषण किया

उत्तर-पश्चिम जिला पुलिस उपायुक्त भीष्म सिंह ने बताया कि पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज का विश्लेषण किया और अपराधियों के भागने के मार्ग का पता लगाते की कोशिश की। मोटरसाइकिल के आधार पर आरोपित की पहचान की गई। इसके बाद पुलिस ने खुफिया जानकारी के आधार पर छापेमारी की गई, जिससे चार आरोपित को पकड़ा गया।

आरोपित का पता लगाने के लिए आगे की जांच की जारी

आरोपित की पहचान दिल्ली की जैन कालोनी, प्रह्लादपुर बांगर निवासी अंकुश (19), विजय विहार निवासी अमन अक्कू (23), शाहबाद दौलतपुर निवासी मनीष (23) और जहांगीरपुरी निवासी दीपांशु कोहली (22) के रूप में हुई। उन्होंने बताया कि वारदात में शामिल अन्य संभावित आरोपित का पता लगाने के लिए आगे की जांच की जारी रही है। आरोपित अपनी विलासितापूर्ण जीवनशैली को बनाए रखने के लिए अवैध रूप से धन अर्जित करना चाहते थे। उन्होंने बताया कि अपराध में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल बरामद कर ली है।

खाली पदों पर अतिथि शिक्षकों की जगह स्थायी नियुक्ति का निर्देश, अकादमिक परिषद की बैठक में नए पाठ्यक्रमों को भी मंजूरी

दिल्ली विश्वविद्यालय की अकादमिक परिषद की बैठक में कुलपति योगेश सिंह ने कॉलेजों को स्थायी नियुक्ति का निर्देश दिया। यूजीसीएफ 2022 के तहत पाठ्यक्रमों को स्वीकृति मिली और नए कोर्स शुरू करने का प्रस्ताव पारित हुआ जिसमें विदेशी भाषाओं के सर्टिफिकेट कोर्स शामिल हैं। बीएलएड पाठ्यक्रम पर भी चर्चा हुई।

नई दिल्ली: कुलपति प्रो. योगेश सिंह ने दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजों के प्राचार्यों को निर्देश दिया हैं कि वह अतिथि शिक्षक रखने की बजाय खली पदों पर स्थायी नियुक्तियां करें।

डीयू अकादमिक परिषद (एसी) की 1022 वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए कुलपति ने निर्देश दिया कि हर कॉलेज पदों को भरने के लिए साल में दो या कम से कम एक बार भर्ती के लिए विज्ञापन निकालें।

दिल्ली सरकार से पूर्ण वित्त पोषित कॉलेजों में भर्ती प्रक्रिया पर उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार से चर्चा चल रही है। जल्द इसके सकारात्मक परिणाम आएंगे।

फारसी, अरबी और उर्दू के पाठ अंग्रेजी में अनुवाद किए जाएंगे

साथ ही शैक्षणिक मामलों पर एसी की स्थायी समिति की बैठकों में की गई सिफारिशों पर विचार करते हुए यूजीसीएफ 2022 के आधार पर विभिन्न संकाय के पाठ्यक्रमों को भी चर्चा के बाद स्वीकार कर लिया गया।

इसके साथ ही संबंधित विभागों के पाठ्यक्रम में शामिल फारसी, अरबी और उर्दू के पाठ का अंग्रेजी में अनुवाद करने के सुझाव को भी स्वीकृति दी गई।

SEC में शामिल किए जाएंगे रोबोटिक्स और ऑटोमेशन

यूजीसीएफ 2022 पर आधारित कौशल संवर्धन पाठ्यक्रमों (SEC) की सूची में नए पाठ्यक्रमों के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स डोमेन में रोबोटिक्स व ऑटोमेशन तथा इंट्रोडक्शन टू आईओटी यूजिंग आर्डूइनों को शामिल करने को स्वीकृति प्रदान की गई है।

एडल्ट एजुकेशन विभाग में टूरिज्म मैनेजमेंट में एमए कोर्स शुरू करने के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया गया।

शैक्षणिक सत्र 2024-2025 से ओपन लर्निंग डेवलपमेंट सेंटर व ओपन लर्निंग कैंपस के अंतर्गत सीआईएसबीसी में फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, इतालवी और पुर्तगाली में सर्टिफिकेट स्तर के पाठ्यक्रम शुरू होंगे।

दूरस्थ और सतत शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए अनुमोदन के लिए अकादमिक परिषद को भेजने की भी सिफारिश की गई।

रामजस कॉलेज में जापानी भाषा में होगा एडवांस डिप्लोमा

सामाजिक विज्ञान संकाय की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए शैक्षणिक सत्र 2025-2026 से दूरस्थ और सतत शिक्षा विभाग, एसओएल के तहत चीनी, जापानी, कोरियाई भाषाओं में सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा शुरू करेगा।

रामजस कॉलेज में जापानी भाषा में एक वर्षीय एडवांस डिप्लोमा (जेपी-3) शुरू को भी एसी ने स्वीकृति प्रदान कर दी गई।

बीएलएड के संचालन पर एनसीटीई से की जाएगी चर्चा

दिल्ली विश्वविद्यालय के करीब छह कॉलेजों में संचालित बीएलएड पाठ्यक्रम के सुचारू संचालन पर सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है। दो साल पहले शुरू किए गए आईटेप कार्यक्रम को बीएलएड के स्थान पर लाने की चर्चा थी। इसमें प्रवेश प्रक्रिया भी जारी है।

एसी बैठक में कुलपति प्रो. योगेश सिंह ने कहा, वह राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) से चर्चा करेंगे। कोर्स को संचालन होते रहने पर बात करेंगे।

एसी सदस्य ने आपत्ति जताई थी कि बीएलएड यूजीसी से फंडेड कोर्स है और इसकी साख कालेजों में अच्छी है। जबकि आइटेप स्ववित्त पोषित है, इसलिए दोनों कोर्स का संचालन होते रहना चाहिए।

एमसीडी अफसरों पर क्यों भड़कीं दिल्ली CM? कहा- दिखावट के लिए किया काम तो...

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता नगर निगम अफसरों पर कूड़ा निस्तारण की धीमी गति को लेकर नाराज हुईं। उन्होंने अधिकारियों को लैंडफिल साइटों से कूड़ा हटाने के काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने एमसीडी को आवारा पशुओं की समस्या से निपटने के लिए विशेष अभियान चलाने और मेगा सफाई अभियान की दैनिक रिपोर्ट भेजने को भी कहा है।

नई दिल्ली। दिल्ली के कूड़े के पहाड़ (लैंडफिल साइट) ओखला, भलस्वा और गाजीपुर से कूड़ा निस्तारण प्रक्रिया धीमी गति से चलने पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नाराजागी व्यक्त करते हुए कार्य में गति लाने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने दिल्ली सचिवालय में कूड़ा निस्तारण को लेकर निगम अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। जहां एमसीडी के वेस्ट टू एनर्जी प्लांट के विस्तार की प्रगति रिपोर्ट की जानकारी ली। साथ ही बैठक में लैंडफिल साइटों पर कूड़ा निस्तारण के लिए चल रहे कार्यों की जानकारी ली।

समय-सीमा का नहीं हो रहा पालन

सीएम ने निगम अधिकारियों कूड़ा निस्तारण की परियोजनाओं के संचालन में पारदर्शिता के साथ समय-सीमा का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि स्वच्छता दिल्ली सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है, और यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि सफाई अभियान सिर्फ प्रतीकात्मक न रह जाए, बल्कि जमीन पर ठोस और प्रभावी कार्य भी हो। सफाई कार्य की धीमी गति पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताई और एमसीडी को कूड़ा निस्तारण की प्रक्रिया में तेजी लाने के स्पष्ट निर्देश दिए। और साथ ही अधिकारियो को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है कि कोई भी ड्रेन में कूड़ा न फेकें। मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से आवारा पशुओं की समस्या को गंभीरता से लेते हुए एमसीडी को एक विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए।

एच एम के पी ने की न्यायिक फैसलों के साथ विदेशों को पत्र हिंदी में लिखने की मांग

सुनील बाजपेई

कानपुर। हिन्द मजदूर किसान पंचायत हिन्द मजदूर किसान पंचायत जल्द ही एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करके जन आन्दोलन की शुरुआत करेगी ,जिसका एकमात्र उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर और देश से बाहर किये जाने वाले किसी भी पत्र कार्यवाही को हिन्दी में ही प्रेषित करवाना होगा। राष्ट्रीय सचिव व प्रदेश महामंत्री राकेशमणि पाण्डेय ने जल शक्ति मंत्रालय के सचिव श्री देवश्री मुखर्जी द्वारा पाकिस्तान के सचिव सै० अली मुतर्जा को हिंदी के बजाय अंग्रेजी में पत्र लिखने को दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय बताया है। हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी में पत्र भेजे जाने का विरोध करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि लाल फीताशाही जबरदस्ती अंग्रेजी भाषा को भारत सरकार की भाषा बनाने में लगी रहती है। कर्मचारी मजदूरों के वरिष्ठ नेता राकेश मणि पांडे ने यह भी दलील दी कि राज्य अन्तर पत्रों का संचालन अपनी भाषा में कर सकते है। किन्तु देश की भाषा किसी भी रूप में अंग्रेजी स्वीकार नहीं है। चर्चित श्रमिक नेता राकेश मणि पांडे ने यह भी कहा आज इतने वर्ष के बाद भी हम अपनी राष्ट्र भाषा हिन्दी को प्रतिष्ठापित नहीं करा पाये है, जो अत्यन्त ही दुर्भाग्यपूर्ण और निन्दनीय है।हिन्द मजदूर किसान पंचायत के राष्ट्रीय सचिव व प्रदेश महामंत्री राकेशमणि पाण्डेय ने कहा भारत सरकार कम से कम विदेश को जारी किये गये पत्रों को हिन्दी में भेजे जाने का कार्य कर सकती है। न्याय पालिका, मेडिकल शिक्षा और तकनीकी शिक्षा में हिन्दी को अनिवार्य बनाए जाने की भी मांग करते हुए हिन्द मजदूर किसान पंचायत के राष्ट्रीय सचिव व

प्रदेश महामंत्री राकेशमणि पाण्डेय ने कहा कि ऐसा करना देश और समाज के हित में अति आवश्यक है जिसका सरकार को तत्काल ध्यान देना चाहिए। उन्होंने बताया कि हिन्द मजदूर किसान पंचायत जल्द ही एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करके जन आन्दोलन की शुरुआत करेगी ,जिसका एकमात्र उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर और देश से बाहर किये जाने वाले किसी भी पत्र कार्यवाही को हिन्दी में ही प्रेषित करवाना होगा उन्होंने कहा कि इसके लिए तब तक आंदोलन किया जाएगा जब तक हिंदी में लिखने की इसी अनिवार्यता को स्वीकार नहीं कर लिया जाएगा । उन्होंने बताया कि इस आंदोलन के तहत देश के सभी चौराहों स्थलों प्रचार के इरादे से लगाए गए अंग्रेजी बोर्डों में कालिक पोती जायेगी वरिष्ठ श्रमिक नेता राकेश मणि पांडेय ने कहा कि हिन्द मजदूर किसान पंचायत हर हाल में हिन्दी को राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किये जाने के लिए कृत संकल्प है।

मजदूर नेता राकेशमणि पाण्डेय ने भारत सरकार से मांग की कि वह अपने सभी अधिनस्थ अधिकारियों कर्मचारियों को निर्देशित करें कि वह राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अंग्रेजी को त्याग कर हिन्दी में पत्राचार करें। न्यायपालिका के सभी आदेशों और निर्णय को हिंदी में ही लिखे जाने की भी अपील करते हुए चर्चित श्रमिक नेता राकेश मणि पांडे ने कहा कि ऐसा करने से ना केवल देश का गौरव बढ़ेगा। बल्कि स्वालम्बन व स्वाधीनता भी परिलक्षित होगी। कानून की समस्त किताबों की उपलब्धता हिंदी में ही होने के साथ ही चिकित्सीय व तकनीकी शिक्षा में भी हिंदी को अनिवार्य किए जाने की भी मांग करते हुए हिन्द मजदूर किसान पंचायत के राष्ट्रीय सचिव व प्रदेश महामंत्री राकेशमणि पाण्डेय ने कहा कि राज्यों को छूट दी जाये कि वह राज्य में अपनी भाषा लागू करें। किन्तु अंग्रेजी भाषा का उपयोग कदापि मत करें ताकि भारत की संप्रभुता, एकता, अखण्डता और राष्ट्रीयता किसी भी कीमत पर प्रभावित न होने पाए।

सरायकेला में करोड़ों का अवैध बालु कारोबार प्रशासन , खनन सतर्क पर दोषी कौन ?

मुख्यमंत्री हेमंत, परिवहन मंत्री के प्रयास नाकाम । राजनगर , कुकुड़ू, ईचागढ़ से लाखों सिएफटी बालू नित्य चोरी

कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड झारखंड

ईचागढ़ / रांची, विगत कुछ वर्षों से झारखंड में रेत का अवैध कारोबार उत्तरप्रदेश एवं बिहार की तरह हो चला है जहां तस्कर से लेकर माफिया ,पुलिस,नेताओ की अब कर्मभूमि बना हुआ है यह अवैध बालु कारोबार । अब तो कमाई का बड़ा जरिया बन चुका ये अवैध बालू । मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं परिवहन मंत्री दीपक बिरूवा भले ही रोकने की लाख कौशिश करें पर सिंहभूम समेत सरायकेला खरसावां जिला से बालू चोरी आये दिनों आम हो गयी है, जहां परिवहन मंत्री दीपक बिरुवा जैसे साफ सुथरे, सीधे साधे व्यक्ति का परिवहन विभाग में पूर्व से चिपक कर बैठे संदिग्ध कर्मचारी एवं दलाल इस अवैध रेत परिवहन में मुख्य किरदार बने हुए है ।कुछ कि अवैध कमाई का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अब ये कर्मचारी फ्लाईट मे सफर करते दिखाई देते है, लाखों लाख रूपये की जमीनें खरीद रहे हैं । आश्चर्य झारखंड एसीबी एक साधारण लिपिक को महज दस हजार रिश्वत लेते पकड़ कर उसे समाहरणालय में मदारी बन दिखाने में जहां व्यस्त हैं,वहीं करोड़ों का खेल के किरदार निगरानी के विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं ।सरायकेला खरसावां के रविशंकर शुक्ला जैसे ईमानदार उपायुक्त एवं तेज़ तर्रार खनन पदाधिकारी ज्योति शंकर तो है पर पुलिस, परिवहन, राजनीति गलियारे के भ्रष्टाचार प्रोत्साहित कर रहे दलाल कर्मचारी सब इन भारी पड़ रहे है । नतीजतन करोड़ों रूपये का बालू प्रति माह तस्करी की भेंट चढ़ रहा है इसी सरायकेला खरसावां से ।

आज हम आपको इचागढ़ अनुमंडल लिये चलते हैं जहां प्रतिदिन पचास से सौ हाईबा बालु चलता है रात को । बंगाल का बोर्डर है नदी में बालु यत्र तत्र है । अवैध बालू डंप पड़ा है झारखंड सीमाक्षेत्र के झाड़ियों में । बंगाल का चलान लिए चलते कुछ वाहन । कौन कार्यालय उन्हें निर्गत करता , कहां से उठता बालु इस पर आजतक उन इलाकों के थाने मौन क्यों ? तहकीकात करनी चाहिए । उपायुक्त के संज्ञान में जानी चाहिए जिनका धर्म भी राजस्व चोरी रोकना प्रथम उद्देश्य बनता आजके खजाने की हालत देखते हुए ।

महज दो दिन पहले की इस तस्वीर को देखिए । एक बालु से भरा हाईबा चांडिल टोल प्लाजा के निकट खड़ी है । संभवत चक्का खराब हो चुका है ।दिन के 10 बज गये एक दुसरा हाईवा उसमे लदा अवैध बालू को छिपा रहा है । उसका नवंबर प्लेट देखें काला रंग से रंग चुका है । ऐसे अनगिनत हाईवा , ट्रेक्टर चलते यहां रात 11.30 बजे से सुवह 5.00 बजे तक । जब इचागढ़ , चांडिल सो जाती केवल पुलिस की आंखें खुली रहती यह हकीकत है ।

सरायकेला खरसावां परिवहन विभाग का इन वाहनों के साथ चोली दामन का रिश्ता है , अन्यथा कभी यह संभव नहीं होता चालिस पचास हाईबा यहां चले जो विगत कुछ वर्षों से निर्विरोध चलते आ रहे है ।आज यह सवाल आता है आखिर सरायकेला खरसावां का परिवहन विभाग के मालिक कौन ?

युद्ध से युद्धविराम तक

रक्त से लथपथ इतिहास,
धधकते ग़ुस्से की ज्वाला,
सरहदों पर टकराती हैं चीखें,
जिन्हें सुनता कौन भला?

वो शहादतें, वो बारूदी हवाएँ,
टूटते काफिले, बिखरते सपने,
दिल्ली से कराची तक,
हर घर में गूँजती कराहें।

मटमैली लहरों में घुला लाल,
सिंधु का मौन, झेलम की पुकार,
दूर कहीं बंकरों में सुलगते हैं रिश्ते,
धरती माँ की बिंधी मांग की तरह।

लेकिन फिर भी,
आसमान में फड़फड़ाती शांति की सफेद पंखुड़ियाँ,
सियासी चक्रव्यूहों को चीरती,
मौत की चुप्पी को तोड़ती,
एक दिन जरूर आएगी वह सुबह,
जब सरहदें सिर्फ नक्शों में रहेंगी।

नफरत की दीवारें पिघलेंगी,
पुकारेंगी हवाएँ, ₹बस बहुत हुआ!₹
और उस दिन,
युद्ध से युद्धविराम तक की यह तस्वीर,
एक नई इबारत लिखेगी,
रिश्तों की उगती नई कोपलें।

– डॉ सत्यवान सौरभ

11 मई – मदर्स डे पर विशेष
माँ हर हाल में माँ होती है...!

देखिए, माँ तो हर हाल में माँ होती है,
बच्चों के लिए तो सारा जहां होती हैं।
अपने आंचल में सभी गम छुपाती है,
सबके होठों पर मुस्कान ले आती हैं।
बच्चों को पालके सारी नींदे गंवाती हैं,
उसके चेहरे पर शिकन नहीं आती हैं।

देखिए, माँ तो हर हाल में माँ होती है,
बच्चों के लिए तो सारा जहां होती हैं।
वो सभी को भरपेट खाना खिलाती है,
ख़ुद सभी के बाद बचा हुआ खाती हैं।
न कोई शिकवा, शिकायत न फ़रियाद,
दिल से देती हैं दुआ सदा करती याद।

देखिए, माँ तो हर हाल में माँ होती है,
बच्चों के लिए तो सारा जहां होती हैं।

माँ के बिना तो सब कुछ ही अधूरा है,
यह उसकी मोह-माया से हुआ पूरा हैं।
मंदिर की मूरत नहीं ईश्वर से कम नहीं,
हर दर्द की दवा,उसके बिन कुछ नहीं।

संजय एम तराणेकर

भारत-पाकिस्तान जंग की हालातो के बीच,191 सदस्यों वाले इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड (आईएमएफ) की पाक को 2.3 अरब डॉलर (20 हज़ार करोड़) के लोन की मंजूरी?

191 सदस्यों वाले इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड,भारत पाक जंग के हालातो के बीच,इतनी बड़ी लोन राशि को स्वीकार करना कोई साजिश,रणनीति या सिफारिश? **–एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र**

वैश्विक स्तरपर पूरी दुनियाँ की लगातार सटीक नजरें आज 10 मई 2025 को अर्ली मॉर्निंग तक लगी रही कि किस तरह जम्मू कश्मीर, राजस्थान गुजरात से लेकर पंजाब तक के अनेकों शहरों में 26 से अधिक ड्रोन द्वारा हमला किया गया, जिसमें भारत के ड्रोन रडार सिस्टम द्वारा जांबाज़ी से नाकाम कर दिया गया, हालांकि पाक की आर्थिक स्थिति अति नाजुक है, इसलिए ही ड्रोन की जांच पर वह तुर्की में बना हुआ पाया गया, परंतु ताजुब की बात कि 1989 से लेकर 35 वर्षों में पाक को आईएमएफ से 28 वर्षों तक लगातार फंड मिलाहै,2019 से पिछले 5 वर्षों में आईएमएफ द्वारा 4 बार कर्ज दिया गया है, पाक का विदेशी मुद्रा भंडार 10.33 अरब डॉलर है तो भारत का 686 अरब डॉलर है, इसी से भारत पाक की आर्थिक स्थिति का अंधा जल लगाया जा सकता है। आज हम भारत-पाकिस्तान युद्ध के हालातो के बीच आईएमएफ लोन की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दिनांक 9 व 10 मई 2025 की मध्य रात्रि में आईएमएफ ने फिर एक बार पाक को 2.3 अरब डॉलर यानी करीब 20 हज़ार करोड़ का लोन पारित कर दिया गया है, वह भी भारत पाक जंग के मुहाने पर खड़े पाक की नाजुक आर्थिक हालातो पर जबकि आईएमएफ के 191 सदस्य हैं, तथा इतने बड़े मुद्दे पर वोटिंग भी होती है। परंतु बड़े ताजुब की बात है कि भारत के सख्त विरोध व अनेक एविडेंस देने के बाद भी लोन पारित कर दिया गया,व एक अरब डॉलर को तुरंत जारी कर दिया जाएगा। बता दें असल में आईएमएफ के 25 निदेशक होते हैं, जो दुनियाँ भर के देशों का प्रतिनिधित्व करते हैं, यहां फैसला ज्यादातर सहमति या कंसेंसेस से किया जाता है लेकिन अगर वोटिंग की बात आती है तो, या तो समर्थन की इजाजत होती है या फिर अब्सेंट की इजाजत ऐसे में अगर विरोध दिखाना है तो एब्सेंट ही रहा जाता है परंतु भारत द्वारा विरोध दर्ज करते हुए एब्सेंट ही रहा परंतु अपने अरगुमेंट में जबरदस्त विरोध कराया परंतु फिर भी लोन पारित किया गया क्योंकि भारत का आईएफ को कड़ा संदेश, यह पैसा पाक की अर्थव्यवस्था को सुधरेगा नहीं बल्कि टेरर फंडिंग में उपयोग होगा फिर भी 191 सदस्यों वाले इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड द्वारा भारत पाक जंग के हालातो के बीच इतनी बड़ी लोन राशि को स्वीकार करना कोई साजिश, रणनीति या सिफारिश है,इसलिए आज हम मीडिया में उपलब्ध जानकारी के सहयोग से इस आर्टिकल के माध्यम से चर्चा करेंगे, भारत पाकिस्तान जंग के हालातो के बीच, 191 देशों के सदस्यों वाले इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड द्वारा पाक को 2.3 अरब डॉलर लोन की मंजूरी दी।

साथियों बात अगर हम भारत पाक के जंग जैसे हालातो के बीच आईएमएफ द्वारा पाक के लिए 2.3 अरब डॉलर के लोन को सेंशन करने की करें तो, आईएमएफ ने पाकिस्तान को 2.3 अरब डॉलर (20 हजार करोड़ रुपए) के दो पैकेजों को मंजूरी दे दी है ।इस लोन में से 1 अरब डॉलर (8500 करोड़ रुपए) एक्सटेंड फंड फैसेलिटी के तहत तत्काल दिए जाएंगे, जबकि 1.3 अरब डॉलर (11 हजार करोड़ रुपए) का लोन अगले 28 महीने तक किस्तों में दिया जाएगा।

साथियों बात अगर हम आईएमएफ के वोटिंग के आधार और आईडीआर को जानने की करें तो, इधर, जंग के हालात के बीच इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने पाकिस्तान को 2.3 अरब डॉलर (20 हजार करोड़ रुपए) के दो पैकेजों को मंजूरी दे दी है ।इस लोन में से 1 अरब डॉलर (8500 करोड़ रुपए) एक्सटेंड फंड फैसेलिटी के तहत तत्काल दिए जाएंगे, जबकि 1.3 अरब डॉलर (11 हजार करोड़ रुपए) का लोन अगले 28 महीने तक किस्तों में दिया जाएगा। आईएमएफ में 191 देश सदस्य हैं। हर देश के पास एक वोट होता है, लेकिन वोट सिर्फ इससे तय नहीं होता है ।आईएमएफ में कोटे के आधार पर वोटिंग अधिकार तय होता है। यानी जिसका जितना ज्यादा कोटा होगा,आईएमएफ के फैसलों में उसकी उतनी ज्यादा सुनी जाएगी। किस देश का कोटा कितना होगा ये उस देश की आर्थिक ताकत (जैसे जीडीपी), विदेशी मुद्रा भंडार,व्यापार और आर्थिक स्थिरता पर निर्भर करता है। जैसे

अमेरिका का कोटा सबसे ज्यादा 16.5 पेर्सेंट है, इसलिए उसका वोट सबसे ज्यादा मायने रखता है। भारत की वोटिंग पावर 2.75 पेर्सेंट के करीब है। जबकि पाकिस्तान की वोटिंग पावर 0.43 पेर्सेंट के करीब। वोटिंग राइट्स दो आधार पर मिलते हैं,बेसिक वोट्सः हर देश को 250 बेसिक वोट्स मिलते हैं, जो सभी देशों के लिए समान हैं ।कोटा-आधारित वोट्सः कोटा के आधार पर एक्स्ट्रा वोट्स मिलते हैं ।इसके लिए आईएमएफ की स्पेशल करेंसी एसडीआर खरीदनी पड़ती है। 1 लाख एसडीआर पर 1 वोट मिलता है। बेसिक वोट्स और कोटा-आधारित वोट्स को मिलाकर ही कुल वोट्स मिलते हैं ।एसडीआर का पूरा नाम है स्पेशल ड्राइंग राइट्स (विशेष आहरण अधिकार)। ये आईएमएफ का बनाया एक अंतरराष्ट्रीय रिजर्व एसेट है। इसे आईएमएफ की अंतरराष्ट्रीय नकदी' या 'ग्लोबल करेंसी यूनिट' कहा जा सकता है। इसे वित्तीय लेन-देन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि ये असली करेंसी नहीं है ।एसडीआर की कीमत 5 बड़ी अंतरराष्ट्रीय करेंसी पर आधारित होती है (1) अमेरिकी डॉलर (यूएसडी)(2) यूरो (ईयूआर) (3)चीनी युआन (सीएनवाय)(4) जापानी येन (जेपीवाय) (5) ब्रिटिश पाउंड (जीबीपी) आईएमएफ सभी सदस्य देशों को उनके कोटे के हिसाब से एसडीआर अलॉटमेन्ट अमेरिका के पास सबसे ज्यादा 16.5पेर्सेंट वोटिंग राइट्स हैं। कोई फैसला लेने के लिए 85 पेर्सेंट तक वोट की जरूरत होती है। ऐसे में अगर अमेरिका वोट न करे तो बहुमत न मिलने की स्थिति में कोई फैसला पारित नहीं किया जा सकता है ।आईएमएफ में भारत ने आज वोटिंग नहीं की। भारत के विदेश सचिव ने 8 मई को कहा था कि वे पिछले तीन दशकों में आईएम एफ ने पाकिस्तान को कई बड़ी सहायता दी है। उससे चलाए गए कोई भी कार्यक्रम सफल नतीजेतक नहीं पहुंच पाएहैं ।आज वोटिंग से पहले भारत ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई। भारत ने कहा कि अगर ऐसे देश को बार-बार मदद दी जाती है जो सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देता है, तो इससे दुनिया को गलत संदेश जाता है ।इसके बाद भारत ने पाकिस्तान को आईएम एफ का फंड मिलने के मामले पर विरोध में वोटिंग नहीं की। बाकी देशों के वोट की मदद से पाक को ये फंड अप्रूव हो गया।

साथियों बात अगर हम भारत द्वारा आईएमएफ में लोन के खिलाफ ऑब्जेक्शन अरगुमेंट की करें तो बैठक में शुक्रवार को भारत ने पाक को दिए जा रहे कर्ज़ को लेकर गंभीर आपत्ति जताई, भारत ने आईएमएफ के एक्सटेंडेड फण्ड फैसिलिटी के तहत पाकिस्तान को दिए जा रहे 1 अरब डॉलर के कर्ज और रेसीलिन्स एंड सुस्ताइंएबिलिटी फैसिलिटी के तहत प्रस्तावित 1.3 अरब डॉलर के नए कर्ज़ पर सवाल उठाए, भारत ने साफ शब्दों में कहा कि पाकिस्तान के कमजोर रिकॉर्ड और कर्ज़ के दुरुपयोग की आशंका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, खासकर जब ये पैसे आतंकवाद को बढ़ावा देने में उपयोग हो सकते हैं ।भारत ने आईएमएफ को याद दिलाया कि 1989 से लेकर अब तक 35 वर्षों में पाकिस्तान को 28 साल आईएमएफ से वित्तीय मदद मिली है, और पिछले 5 वर्षों में ही चार बेलआउट प्रोग्राम शुरू किए गए हैं, भारत ने कहा कि अगर पूर्ववर्ती प्रोग्राम कारगर होते, तो आज पाकिस्तान को फिर से आईएमएफ के पास आने की ज़रूरत नहीं पड़ती ।भारत ने आई ल एमएफ के इवैल्यूएशन रिपोर्ट ऑन प्रोलोंग्ड यूज़ ऑफ़ आईएमएफ रिसोर्सस का हवाला देते हुए कहा कि पाकिस्तान के मामले में आईएमएफ की निगरानी प्रणाली, कार्यक्रमों की रूपरेखा और उनके कार्यान्वयन की प्रभावशीलता पर गंभीर सवाल उठते हैं. इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान को बार-बार राहत पैकेज देने के पीछे राजनीतिक कारणों की भी व्यापक धारणा रही है,भारत ने यह भी कहा कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में सेना की गहरी दखल अंदाजी नीतिगत अस्थिरता और सुधारों के पलटाव की आशंका को बढ़ा देती है, एक 2021 की संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए भारत ने कहा कि पाकिस्तान की सेना से जुड़ी कंपनियां देश की सबसे बड़ी कारोबारी इकाइयां हैं. हालिया समय में स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल में सेना की भूमिका इस हस्तक्षेप को और पुख्ता करती है,पाकिस्तान फंड का कर रहा दुरुपयोगभारत ने यह आशंका भी जताई कि आईएमएफ जैसे अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से मिलने वाला फंड 'फंगिबल' (अर्थात आसानी से अन्य उद्देश्यों में उपयोग हो सकने वाला) होताहै और इसका उपयोग राज्य प्रायोजित सीमा-पार आतंकवाद के लिए किया जा सकता है, भारत का कहना था कि ऐसे फंड का दुरुपयोग न केवल वैश्विक मूल्यों की अवहेलना है, बल्कि इससे आईएमएफ और अन्य दात्री संस्थाओं की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठता है. अपने कड़े रुख के तहत भारत ने इस मुद्दे पर आईएमएफ की वोटिंग प्रक्रिया से खुद को अलग कर लिया और अन्य सदस्य देशों से भी नैतिक और वैश्विक सुरक्षा के दृष्टिकोण से जिम्मेदार कदम उठाने की अपील की

साथियों बात अगर हम पाक के हालातो की करें तो, पाकिस्तान की कंगाली का हाल भला दुनिया में कौन नहीं जानता। अंतर राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ), विश्व बैंक, एडीबी से लेकर अपने मित्र देशों से भीख मांगने के लिए वह मशहूर रहा है। लेकिन, इस पैसे का इस्तेमाल उसने अपने विकास के बजाय आतंक की फैक्ट्री चलाने में किया। अब भारत पाकिस्तान की टेरर फंडिंग पर ही स्ट्राइक पर स्ट्राइक कर रहा है। इस स्ट्राइक में वह अब तुरुप के इक्के चलने वाला है। पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान पर आर्थिक दबाव बढ़ा दिया है। इसके तहत सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया गया है। पाकिस्तान के साथ व्यापार पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। हवाई क्षेत्र भी बंद कर दिया गया है। ये सारे कदम पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह से नुकसान पहुंचाएंगे। हालांकि, अभी सिलसिला रुका नहीं है। अब भारत पाकिस्तान को आईएमएफ से मिलने वाले 1.3 अरब डॉलर के लोन का भी विरोध कर सकता है। भारत का कहना है कि पाकिस्तान की ओर से इस पैसे का इस्तेमाल आतंकवाद को बढ़ावा देने में करने के आसार हैं।

अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विशेषण करें तो हम पाएंगे कि भारत-पाकिस्तान जंग की हालातो के बीच, 191 सदस्यों वाले इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड (आईएमएफ)की पाक को 2.3 अरब डॉलर (20 हज़ार करोड़) के लोन की मंजूरी ।भारत का आईएम एफ को कड़ा संदेश, यह पैसा पाक की अर्थव्यवस्था को सुधारने नहीं बल्कि टेरर फंडिंग में उपयोग होगा ।191 सदस्यों वाले इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, भारत पाक जंग के हालातो के बीच,इतनी बड़ी लोन राशि को स्वीकार करना कोई साजिश रणनीति या सिफारिश ?

टाटा टिगोर को खरीदना हो गया महंगा, जानें किस वेरिएंट की कीमत में हुई कितनी बढ़ोतरी

परिवहन विशेष न्यूज

भारत की प्रमुख वाहन निर्माता टाटा मोटर्स की ओर से कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से कॉम्पैक्ट सेडान कार के तौर पर Tata Tiaor को ऑफर किया जाता है। अब इस गाड़ी को खरीदना महंगा हो गया है। निर्माता की ओर से इसके कई वेरिएंट की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। किस वेरिएंट में कितनी बढ़ोतरी हुई है। आइए जानते हैं।

नई दिल्ली। भारत की प्रमुख वाहन निर्माता टाटा मोटर्स की ओर से कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से कॉम्पैक्ट सेडान कार के तौर पर ऑफर की जाने वाली Tata Tigor की कीमतों को बढ़ा दिया गया है। टाटा की ओर से इसके किन वेरिएंट्स की कीमत में बढ़ोतरी (Tata Tigor price hike) हुई है। अब किस कीमत पर इस गाड़ी को खरीदा जा सकेगा। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

महंगी हुई Tata Tigor

टाटा मोटर्स की ओर से कॉम्पैक्ट सेडान कार सेगमेंट में ऑफर की जाने वाली Tata Tigor को खरीदना अब महंगा हो गया है। निर्माता की ओर से इसकी कीमतों में 10 हजार रुपये तक की बढ़ोतरी की गई है। जिसे लागू भी कर दिया गया है और बढ़ी हुई कीमत को वेबसाइट पर भी अपडेट कर दिया गया है।

किन वेरिएंट्स की बढ़ी कीमत

निर्माता की ओर से बेस वेरिएंट (Tigor variant-wise increase) की कीमत में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। इसके सेकेंड बेस वेरिएंट से कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। XE वेरिएंट और XZ Plus Lux की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है। वहीं XM, XZ, XZ Plus की कीमत में 10 हजार रुपये बढ़ाए गए हैं। ऑटोमैटिक और सीएनजी में भी सभी वेरिएंट्स की कीमत अपडेट की गई है। सीएनजी में सिर्फ XZ Plus Lux की कीमत में बदलाव नहीं हुआ है।

कितनी हुई कीमत

Tata Tigor XE वेरिएंट की एक्स शोरूम कीमत (Tata Tigor updated prices) छह लाख रुपये ही रखी गई है। इसके बाद XM की नई कीमत 6.80 लाख रुपये, XZ की नई कीमत 7.40, XZ Plus की नई कीमत आठ लाख रुपये रखी गई है। इसके ऑटोमैटिक वेरिएंट्स की एक्स शोरूम कीमत 7.35 लाख रुपये से 8.55 लाख रुपये रखी गई है। सीएनजी में इसकी एक्स शोरूम कीमत 7.80 लाख रुपये से 9.55 लाख रुपये के बीच रखी गई है।

किनसे है मुकाबला

टाटा की ओर से टिगोर को कॉम्पैक्ट सेडान कार सेगमेंट में ऑफर किया जाता है। इस सेगमेंट में इसका सीधा मुकाबला Maruti Suzuki Dzire, Honda Amaze, Hyundai Aura के साथ होता है। वहीं कीमत के मामले में इसे कई Maruti Suzuki, Hyundai और Toyota की हैचबैक और Maruti Suzuki, Hyundai, Mahindra, Kia, Skoda, Toyota की कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट की कारों से भी चुनौती मिलती है।

2025 होंडा सीबी650आर बाइक भारतीय बाजार में हुई लॉन्च, सुपरबाइक में मिला ई क्लच फीचर, जानें कितनी है कीमत

परिवहन विशेष न्यूज

होंडा CB650R 2025 लॉन्च जापानी दो पहिया निर्माता होंडा की ओर से चुपचाप 650 सीसी सेगमेंट में Honda CB650R बाइक को लॉन्च कर दिया गया है। इसमें किस तरह की खासियत को दिया गया है। कितना दमदार इंजन दिया गया है। किस कीमत पर इसे खरीदा जा सकता है। बाजार में इसका किन बाइक्स से मुकाबला होगा। आइए जानते हैं।

नई दिल्ली। जापानी दोपहिया वाहन निर्माता Honda की ओर से कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से सुपरबाइक सेगमेंट में नई बाइक के तौर पर 2025

लॉन्च हुई Honda की नई बाइक

होंडा मोटरसाइकिल और स्कूटर इंडिया की ओर से भारतीय बाजार में नई बाइक को लॉन्च कर दिया गया है। नई बाइक को 650 सीसी सेगमेंट में लॉन्च किया गया है। साथ ही इसमें खास तकनीक वाले क्लच का उपयोग भी किया गया है।

कैसे हैं फीचर्स

निर्माता की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक नई बाइक में कई बेहतरीन फीचर्स को ऑफर किया गया है। इसमें सबसे नई तकनीक E-Clutch को भी ऑफर किया गया है। इसके अलावा इसमें एलईडी हेडलाइट, 41 एमएम सेपरेट फंक्शन फोर्क बिग पिस्टन, मोनोशॉक सस्पेंशन, पांच इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, नेविगेशन, आगे ड्यूल और पीछे सिंगल डिस्क ब्रेक, क्रोमोस्फीयर रेड और मैट गनपाउडर ब्लैक मेटेलिक जैसे रंगों का विकल्प भी दिया गया है।

क्या है E-Clutch तकनीक

ई-क्लच तकनीक के साथ होंडा की पहली बाइक सीबी650आर को लॉन्च किया गया है। इस तकनीक के बाद बाइक चलाते हुए मैनुअल तरीके से गियर बदलने जरुरत को खत्म कर दिया गया है। इसका सबसे ज्यादा फायदा सड़क पर ट्रैफिक के बीच होता है, जहां पर बार बार गियर नहीं बदलने होते बल्कि बाइक खुद ही गियर बदलती रहती है। जिससे ज्यादा स्पोर्टी और बेहतर कंट्रोल के साथ राइड की जा सकती है।

कितना दमदार इंजन

होंडा की नई बाइक में 649 सीसी की क्षमता का लिक्विड कूल्ड इनलाइन फोर सिलेंडर इंजन दिया गया है। जिससे इसे 12 हजार आरपीएम पर 70 किलोवाट की पावर और 63 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। इसमें छह स्पीड गियरबॉक्स दिया गया है। जिसके साथ ई-क्लच को दिया गया है।

कितनी है कीमत

निर्माता की ओर से इसे दो वेरिएंट में लॉन्च किया गया है। जिसमें Honda CB650R और Honda CBR650R शामिल हैं। Honda CB650R की एक्स शोरूम कीमत 9.60 लाख रुपये है और Honda CBR650R की एक्स शोरूम कीमत 10.40 लाख रुपये रखी गई है। दोनों ही वेरिएंट्स के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन बुकिंग करवाई जा सकती है। होंडा के मुताबिक इनकी डिलीवरी भी मई 2025 के आखिर तक शुरू की जाएंगी।

किनसे है मुकाबला

होंडा की इस बाइक को 650 सीसी सेगमेंट में लॉन्च किया गया है। इस सेगमेंट में इसका सीधा मुकाबला Kawasaki, Triumph, Aprilia जैसी निर्माताओं की बाइक्स के साथ होगा। इसके अलावा इसे Royal Enfield और BSA Glodstar जैसी निर्माताओं से भी चुनौती मिल सकती है।

टेस्ला कार के वायरल वीडियो ने खोल दी आंखें! जानें कैसे AI जैसी नई तकनीक पर आंखें मूंद कर भरोसा करने से हो सकता है बड़ा खतरा

एआई भरोसे के मुद्दे दुनियाभर में वाहन निर्माताओं की ओर से कारों को लगातार नई नई तकनीक के साथ ऑफर किया जा रहा है। इनमें ADAS AI जैसे कई फीचर्स हैं जिनसे कार चलाते समय लापरवाही की कई वीडियो सामने आती हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर हाल में एक ऐसा वीडियो पोस्ट किया गया है जिसमें एआई जैसी तकनीक पर भरोसा करना कितना खतरनाक हो सकता है। आइए जानते हैं।

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। भारत के साथ ही दुनियाभर में कई वाहन निर्माता लगातार नई तकनीक को कारों में ऑफर किया जा रहा है। लेकिन इस तरह की तकनीक पर पूरी तरह से भरोसा करना कितना खतरनाक साबित हो सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

कारों में लगातार मिल रही नई तकनीक

पिछले कुछ सालों में भारत ही नहीं दुनियाभर में कारों की तकनीक में काफी बदलाव हुआ है। कुछ सालों में ही कारों में ऐसी तकनीक ऑफर की जा रही हैं जिनको पहले सोचा भी नहीं जा सकता था। ADAS, AI, क्रूज कंट्रोल जैसी ऐसी कुछ तकनीक हैं जिनके कारण कार चलाने का अनुभव पूरी तरह से बदल रहा है।

तकनीक पर पूरा भरोसा है खतरनाक

भले ही कारों में नई नई तकनीक को दिया जा रहा है। जिससे कार चलाने का अनुभव आसान होने के साथ ही बदल रहा है। लेकिन ऐसी तकनीकों पर पूरी तरह से भरोसा करना काफी ज्यादा खतरनाक भी हो सकता है। ऐसा ही एक उदाहरण सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है।

सोशल मीडिया पर जारी वीडियो

सोशल मीडिया पर हाल में ही एक वीडियो वायरल हो रहा है। जिसमें एक टेस्ला की कार को सेल्फ ड्राइविंग तकनीक के साथ चलाते हुए देखा जा सकता है। इस वीडियो में टेस्ला की कार दूसरी कार को जब ओवरटेक करती है तो दूसरी कार सेल्फ ड्राइविंग टेस्ला के पास आ जाती है और कार की AI जैसी तकनीक इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाती।

ड्राइवर ने दिखाई समझदारी

कार को भले ही सेल्फ ड्राइविंग और एआई तकनीक की मदद से चलाया जा रहा था। लेकिन ड्राइवर ने भी समझदारी दिखाते हुए स्टेयरिंग पर तुरंत कंट्रोल किया जिससे हादसा होने से बच गया।

वीडियो में उठा सवाल

जिस सोशल मीडिया हैंडल पर यह पोस्ट किया गया है वहां एक सवाल भी पूछा गया है कि इससे एक बड़ा सवाल उठता है: क्या हम ऐसा भविष्य चाहते हैं जहाँ इस तरह के निर्णय पूरी तरह से AI पर छोड़ दिए जाएँ? या फिर मानवीय प्रवृत्ति को हमेशा ही लूप का हिस्सा बनना होगा?

मिल रही प्रतिक्रिया

सोशल मीडिया पर वीडियो को पोस्ट करने के बाद कई तरह की प्रतिक्रिया मिल रही है। कोई व्यक्ति इसे टेस्ला की तकनीक की गलती बता रहा है तो कोई दूसरी कार के ड्राइवर की गलती बता रहा है। वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि बस अपनी कार ड्राइव करो परेशानी खत्म हो जाएगी।

किआ कैरेंस एमपीवी के कई वेरिएंट्स को बंद किया गया, अब मिलेगा सिर्फ सात सीटों वाला प्रीमियम ओ का विकल्प

परिवहन विशेष न्यूज

किआ कैरेंस अपडेट साउथ कोरियाई वाहन निर्माता किआ की ओर से कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। किआ की ओर से ऑफर की जाने वाली बजट एमपीवी कैरेंस के सभी वेरिएंट्स को डिस्कंटीन्यू कर दिया गया है। अब सिर्फ एक ही वेरिएंट में इस एमपीवी को ऑफर किया जाएगा। यह वेरिएंट कौन सा है और किस कीमत पर ऑफर किया जाएगा। आइए जानते हैं।

नई दिल्ली। भारतीय बाजार में कई सेगमेंट में वाहनों को ऑफर करने वाली साउथ कोरियाई निर्माता Kia की ओर से बजट एमपीवी के तौर पर Kia Carens को ऑफर किया जाता है। निर्माता की ओर से इस एमपीवी के सभी वेरिएंट्स को बंद कर दिया है और अब सिर्फ एक ही विकल्प में इसे ऑफर किया जाएगा। ऐसा क्यों किया गया है। किस वेरिएंट को ऑफर किया जा रहा है। किस कीमत पर इसे खरीदा जा सकेगा। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

बंद हुए Kia Carens के कई वेरिएंट

किआ की ओर से कैरेंस एमपीवी के कई वेरिएंट्स को बंद कर दिया है। निर्माता की ओर से इसकी जानकारी अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर भी अपडेट कर दिया गया है।

क्या है कारण

किआ की ओर से आठ मई 2025 को ही नई एमपीवी के तौर पर Kia Carens Clavis को पेश किया है। इस एमपीवी को औपचारिक तौर पर 23 मई 2025 को लॉन्च कर दिया जाएगा। इसके ऑफर किए जाने के बाद ही कैरेंस के कई वेरिएंट्स को बाजार से हटा दिया (Kia Carens discontinued variants) गया है।

किस वेरिएंट की होगी बिक्री

निर्माता की ओर से अब सिर्फ एक ही वेरिएंट के साथ कैरेंस की बिक्री की जाएगी। वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक कैरेंस को अब सिर्फ Premium (O) वेरिएंट (7-seater Premium O Carens) को ही ऑफर किया गया है। जिसमें सात सीटों का विकल्प दिया जाएगा।

कितने इंजन के मिलेंगे विकल्प

निर्माता की ओर से वेबसाइट पर जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक कैरेंस के एक ही वेरिएंट में तीन इंजन के विकल्प दिए जाएंगे। इसमें Smartstream G1.5 T-GDi 6iMT, Smartstream G1.5 6MT और 1.5L CRDi VGT 6MT वेरिएंट के ही विकल्प मिलेंगे।

कैसे हैं फीचर्स

Kia Carens Pemium (O) 7 str वेरिएंट में कई बेहतरीन फीचर्स को दिया गया है। इसमें 15 और 16 इंच टायर, हेलोजन लैंप, हेलोजन टेल लैंप, शार्क फिन एंटीना, टिल्ट स्टेयरिंग, पावर विंडो, रियर व्यू कैमरा, 12.5 इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, आठ इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम, एंड्राइड ऑटो, एपल कार प्ले, सेमी लेदरेट सीट्स, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट, की-लैस एंट्री, सात रंगों के विकल्प सहित कई फीचर्स मिलेंगे।

कितनी होगी सुरक्षित

निर्माता की ओर से कैरेंस एमपीवी में एबीएस, ईबीडी, ईएससी, एचएसी, वीएसएम, डीबीसी, छह एयरबैग, रियर पार्किंग सेंसर, चारों पहियों में डिस्क ब्रेक, आइसोफिक्स चाइल्ड एंकरेज, स्पीड सेंसिंग डोर लॉक जैसे सेफ्टी फीचर्स मिलेंगे।

टाटा कर्व डीजल के बेस वेरिएंट को है घर लाना, दो लाख रुपये की अग्रिम भुगतान के बाद हर महीने कितनी बनेगी ईएमआई

परिवहन विशेष न्यूज

टाटा कर्व फाइनेंस प्लान अगर आप भी टाटा की कूप एसयूवी के तौर पर ऑफर की जाने वाली Tata Curvv के डीजल बेस वेरिएंट को खरीदने का मन बना रहे हैं। दो लाख रुपये की Down Payment करने के बाद खरीदना चाहते हैं तो हर महीने कितने रुपये की EMI देकर एसयूवी को घर लाया जा सकता है। आइए जानते हैं।

नई दिल्ली। भारतीय बाजार में Tata की ओर से Coupe SUV सेगमेंट में Tata Curvv को बिक्री के लिए उपलब्ध करवाया जाता है। कंपनी की ओर से इसके डीजल में बेस वेरिएंट के तौर पर Smart Diesel को ऑफर किया जाता है। अगर आप भी इस एसयूवी के बेस वेरिएंट को खरीदने का मन बना रहे हैं और सिर्फ दो लाख रुपये की Down Payment करने के बाद गाड़ी को घर लाना चाहते हैं, तो हर महीने कितने रुपये की EMI देनी होगी। हम इसकी जानकारी आपको इस खबर में दे रहे हैं।

Tata Curvv के टॉप वेरिएंट Smart Diesel की कितनी है कीमत

Tata की ओर से Curvv के डीजल के बेस वेरिएंट को बिक्री के लिए ऑफर किया जाता है। इसको 11.50 लाख रुपये की एक्स शोरूम कीमत पर भारतीय बाजार में उपलब्ध करवाया जाता है। इस गाड़ी को अगर दिल्ली में खरीदा जाता है तो करीब 1.18 लाख रुपये का रोड टैक्स और करीब 51 हजार रुपये का इंश्योरेंस देना होगा। इसके अलावा टीसीएस चार्ज के तौर पर 11499 रुपये देने होंगे। जिसके बाद Tata Curvv डीजल के बेस वेरिएंट की ऑन रोड कीमत करीब 13.30 लाख रुपये के आस-पास हो जाती है।

दो लाख Down Payment के बाद रुपये की EMI

अगर आप इस गाड़ी के बेस वेरिएंट स्मार्ट डीजल को खरीदते हैं, तो बैंक की ओर से एक्स शोरूम कीमत पर ही फाइनेंस किया जाएगा। ऐसे में दो लाख रुपये की डाउन पमेंट करने के बाद आपको करीब 11.30 लाख रुपये को बैंक से फाइनेंस करवाना होगा। बैंक की ओर से अगर आपको नौ फीसदी ब्याज के साथ सात साल के लिए 11.30 लाख रुपये दिए जाते हैं, तो हर महीने 18188 रुपये हर महीने की EMI आपको अगले सात साल के लिए देनी होगी।

कितनी महंगी पड़ेगी Tata Curvv

अगर आप नौ फीसदी की ब्याज दर के साथ सात साल के लिए 11.30 लाख रुपये का बैंक से Car Loan लेते हैं, तो आपको सात साल तक 18188 रुपये की EMI हर महीने देनी होगी। ऐसे में सात साल में आप Tata की इस SUV के लिए करीब 3.97 लाख रुपये बतौर ब्याज देंगे। जिसके बाद आपकी कार की कुल कीमत एक्स शोरूम, ऑन रोड और ब्याज मिलाकर करीब 17.27 लाख रुपये हो जाएगी।

किनसे है मुकाबला

Tata Curvv को कूप एसयूवी के तौर पर भारतीय बाजार में लाया गया है। इस एसयूवी का वैसे तो Citroen Basalt के साथ मुकाबला होता है, लेकिन इसके अलावा भी इसे Maruti Grand Vitara, Toyota Urban Cruiser Hyryder, Mahindra XUV 700, MG Hector जैसी एसयूवी से चुनौती मिलती है।

भारत का आतंक पर कभी न भूलने वाला प्रहार

योगेश कुमार गोयल

सिंदूर ऑपरेशन में केवल आतंकी ठिकानों को ही नहीं, उन ठिकानों को भी निशाना बनाया गया, जहां से उन्हें रसद, हथियार और प्रशिक्षण दिया जाता था। यह केवल आतंकियों के खिलाफ नहीं बल्कि आतंक को संरक्षण देने वाली पूरी पाकिस्तानी सैन्य और खुफिया संरचना के खिलाफ कार्रवाई थी।

'ऑपरेशन सिंदूर' के जरिये भारत ने साबित कर दिया है कि वह अब केवल प्रतिक्रिया देने वाला देश नहीं बल्कि आतंक के स्त्रोतों पर निर्णायक और सर्जिकल प्रहार करने वाला राष्ट्र बन चुका है। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद जिस तरह भारत ने सीमा पार स्थित आतंकी ठिकानों पर निशाना साधते हुए 'ऑपरेशन सिंदूर' को अंजाम दिया, उसने न केवल पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई बल्कि भारत की नई सैन्य नीति को भी स्पष्ट कर दिया कि अब हम चुप नहीं बैठेंगे बल्कि हम आतंक के जन्मस्थल तक जाएंगे और वहां आग लगाएंगे। यह ऑपरेशन केवल एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, यह उस बदले हुए भारत की घोषणा थी, जो अब बातों से नहीं, बमों से जवाब देता है, जो कूटनीति की किताब बंद करके अब अपने लड़ाकू विमानों और मिसाइलों की बोली में संवाद करता है। भारतीय वायुसेना ने जब पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में घुसकर आतंकियों के अड्डों पर सर्जिकल स्ट्राइक की तो यह महज जवाबी हमला नहीं था, यह स्पष्ट संदेश था कि भारत अब किसी आतंकी की मांद को भी सुरक्षित नहीं छोड़ेगा, चाहे वह सरहद के इस पार हो या उस पार।

ऑपरेशन सिंदूर का उद्देश्य स्पष्ट था, उन स्थानों को ध्वस्त करना, जहां से भारत में आतंक का बीज बोया जाता है। पहलगाम हमला, जिसमें हमारे निर्दोष पर्यटकों को निशाना बनाया गया, उसकी साजिश कहीं और नहीं, पाकिस्तान की फौज, आईएसआई और लश्कर-ए-तैयबा जैसों की सांठगांठ से ही तैयार की गई थी। भारत ने न केवल इस साजिश को समझा बल्कि उसे जड़ से उखाड़ने की भी ठान ली है। इस ऑपरेशन में भारतीय वायुसेना ने जिस साहस, रणनीति और सटीकता का परिचय दिया, वह दुनिया के किसी भी शीर्ष सैन्य बल को चुनौती देने के लिए पर्याप्त है। पाकिस्तान हमेशा से ही दोहरी भूमिका निभाता रहा है, एक ओर वह अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर शांति और वार्ता की बात करता है तो दूसरी ओर अपने क्षेत्र को आतंकियों के प्रशिक्षण केंद्र के रूप में प्रयोग करता है। भारत ने अब उस नकाब को पूरी तरह नोच फेंका है। ऑपरेशन सिंदूर ने बता दिया कि भारत अब उन भाषणों या प्रस्तावों से संतुष्ट नहीं होगा, जो संयुक्त राष्ट्र में दिए जाते हैं बल्कि उन बंकरों को नेस्तनाबूद करेगा, जहां से ये षड्यंत्र जन्म लेते हैं।

भारत द्वारा यह कार्रवाई अचानक नहीं की गई बल्कि पहले खुफिया एजेंसियों के माध्यम से आतंकियों की गतिविधियों की पूरी जानकारी जुटाई गई। सैटेलाइट इमेजिंग, मानव खुफिया नेटवर्क और तकनीकी निगरानी के जरिये भारत को यह स्पष्ट हो गया था कि पाक अधिकृत कश्मीर में कुछ स्थान आतंकियों के लांच पैड के रूप में कार्य कर रहे हैं। यह भी सामने आया कि हालिया पहलगाम हमले की योजना भी यहीं से बनाई गई थी। भारत की यह नीति अब 'हिट ऐंड होल्ड' की है कि हमला करो, कब्जा करो और दबाव बनाए रखो। इस ऑपरेशन में सबसे प्रभावशाली बात यह रही कि भारतीय लड़ाकू विमानों ने रात के अंधेरे में बेहद सटीकता से अपने लक्ष्य साधे और सीमित समय में वहां से निकल आए। यह 'नो वॉर्निंग, नो वॉर' रणनीति का आदर्श उदाहरण था। पाकिस्तान के वायु रक्षा तंत्र को भनक तक नहीं लगी और जब तक वहां के सैन्य प्रतिष्ठान कुछ समझ पाते, तब तक भारत अपना काम करके वापस लौट चुका था।

इस ऑपरेशन में केवल आतंकी ठिकानों को ही नहीं, उन ठिकानों को भी निशाना बनाया गया, जहां से उन्हें रसद, हथियार और प्रशिक्षण दिया जाता था। यह केवल आतंकियों के खिलाफ नहीं बल्कि आतंक को संरक्षण देने वाली पूरी पाकिस्तानी सैन्य और खुफिया संरचना के खिलाफ कार्रवाई थी। यही कारण है कि पाकिस्तान के राजनीतिक और सैन्य गलियारों में इस ऑपरेशन के बाद सन्नाटा छा गया। हालांकि पाकिस्तान की प्रतिक्रिया पूर्वानुमेय थी, पहले इन्कार, फिर विक्टिम कार्ड खेलना और अंत में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से गुहार लगाना लेकिन अब वैश्विक परिदृश्य बदल चुका है। अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अन्य लोकतांत्रिक देश भारत के साथ खड़े हैं। आतंक के प्रति उनकी नीति अब स्पष्ट है कि जो आतंक को शरण देगा, वह खुद सुरक्षित नहीं रहेगा। इसीलिए, भारत द्वारा किए गए इस ऑपरेशन को विश्वभर में नैतिक समर्थन और वैधता प्राप्त हुई है।

यह भी ध्यान देने योग्य है कि ऑपरेशन सिंदूर का सैन्य पक्ष जितना शक्तिशाली था, उतनी ही मजबूत उसकी कूटनीतिक तैयारी भी थी। भारत ने पहले ही अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान के आतंक समर्थक चेहरे को उजागर कर दिया था। एफएटीएफ जैसे मंचों पर पाकिस्तान की असफलताएं जगजाहिर हैं। ऐसे में भारत का यह सैन्य कदम उस लंबे कूटनीतिक संघर्ष का परिणामी वार था, जिसे वर्षों से संजोया जा रहा था। ऑपरेशन सिंदूर ने यह भी दिखा दिया कि भारत अब केवल एलओसी तक सीमित नहीं है। यदि आवश्यक हुआ तो भारत नियंत्रण रेखा पार करके भी अपने हितों की रक्षा कर सकता है। यह नीति पाकिस्तान के लिए स्पष्ट चेतावनी है कि यदि उसने अब भी अपने घर में पल रहे आतंकी सांपों को दूध पिलाना बंद नहीं किया तो अगली बार भारत उनके बिलों तक पहुंचेगा और उन्हें वहीं खत्म करेगा। यह भी उल्लेखनीय है कि भारत की सैन्य क्षमता अब केवल परंपरागत युद्धों तक सीमित नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर में जिन हथियारों और तकनीकों का उपयोग किया गया, उनमें राफेल जैसे अत्याधुनिक लड़ाकू विमान, ड्रोन निगरानी, रियल टाइम सैटेलाइट डेटा और बंकर भेदी बम शामिल थे। यह सब कुछ दर्शाता है कि भारत अब एक आधुनिक, आक्रामक और निर्णायक सैन्य शक्ति बन चुका है।

पाकिस्तान की अब तक की रणनीति यही रही है कि वह भारत के धैर्य की परीक्षा लेता रहे और भारत केवल विरोध या चेतावनी तक सीमित रहे लेकिन अब वह दौर समाप्त हो गया है। भारत ने बता दिया है कि वह न केवल जवाब देगा बल्कि ऐसा जवाब देगा, जो 'आतंकिस्तान' को अगली साजिश रचने से पहले सौ बार सोचने पर विवश करेगा। आतंक को बढ़ावा देना अब पाकिस्तान के लिए केवल एक रणनीति नहीं, आत्मघाती कदम बन चुका है। भारत ने साबित कर दिया है कि अब न केवल सीमा की सुरक्षा करेगा बल्कि आवश्यकता पड़ी तो आतंकी नेटवर्क की जड़ों तक जाकर प्रहार करेगा। यह केवल सैन्य नीति नहीं बल्कि नई भारतीय आत्मा की आवाज है, जो शांति तो चाहती है लेकिन डरती नहीं, जो प्रेम में तो विश्वास करती है लेकिन पराजय में नहीं।

ऑपरेशन सिंदूर अब एक ऐसा उदाहरण बन गया है, जो यह बताता है कि आतंक से अब डायलॉग से नहीं, डायनामाइट से निपटना है। भारत ने यह प्रमाणित कर दिया है कि वह किसी भी कीमत पर अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा, चाहे उसके लिए कितनी भी बड़ी कार्रवाई क्यों न करनी पड़े। आज भारत के पास रक्षात्मक नहीं, आक्रामक कूटनीति है। अब हम इंतजार नहीं करते कि दुश्मन कब वार करे बल्कि अब हम तय करते हैं कि कब, कहां और कैसे प्रहार करना है। यह बदलाव केवल सरकार की नीति में ही नहीं, देश की चेतना में भी है और यही चेतना ऑपरेशन सिंदूर की असली ताकत है। अब यदि पाकिस्तान यह सोचता है कि वह फिर किसी नए हमले की योजना बनाकर भारत को अस्थिर कर देगा तो उसे भली-भांति समझ लेना चाहिए कि 'ऑपरेशन सिंदूर' तो केवल शुरुआत है, अब हर आतंकी ठिकाने के लिए भारत के पास ऐसा जवाब है, जो न केवल आतंकियों के ठिकानों बल्कि समूचे पाकिस्तान का नाम ही विश्व के मानचित्र से गायब कर सकता है।

गरीब की दवा : विजय गर्ग

कई बार समाचार सुनने-पढ़ने को मिलते हैं कि परिजनों के गंभीर व असाध्य रोगों के महंगे इलाज की वजह से लाखों लोग गरीबी की दलदल में डूब गए। कोरोना संकट के दौरान भी लोगों द्वारा घर, जमीन व जेवर बेचकर अपनों की जान बचाने की कोशिश की खबरें मीडिया में तैरती रही। लेकिन सामान्य दिनों में दवा कंपनियों की मिलीभगत व दबाव में लिखी जाने वाली महंगी दवाइयां भी गरीबों को टीस दे जाती हैं। इसके बावजूद कि बाजार में उसी साल्ट वाली गुणवत्ता की जेनेरिक दवा सहज उपलब्ध है। कुछ समय पहले केंद्र सरकार की ओर से जेनेरिक दवाइयां लिखने की अनिवार्यता के निर्देश का अच्छा-खासा विरोध हुआ, जिसके चलते निर्णय वापस लेना पड़ा था। अब इसी चिंता को देश की शीर्ष अदालत ने अभिव्यक्त किया है। दरअसल, बीते शुक्रवार को दवा कंपनियों की मुनाफाखोरी के कारोबार से बढ़ती दवाओं की कीमतों के बाबत एक मामले में सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि यदि डॉक्टर केवल जेनेरिक दवाइयां ही लिखना प्रारंभ कर दें, तो दवा कंपनियों व चिकित्सकों के अपवित्र गठबंधन को तोड़ा जा सकता है। निस्संदेह, तरह-तरह के प्रलोभन व परोक्ष-अपरोक्ष लाभ देकर दवा कंपनियां चिकित्सकों पर महंगी दवा लिखने का दबाव बनाती हैं। जिसकी कीमत उन लोगों को चुकानी पड़ती है, जो महंगी दवा खरीदने की क्षमता नहीं रखते। ऐसे में वे कर्ज लेकर या अपने रिश्तेदारों से मदद लेकर किसी तरह गंभीर रोगों से ग्रस्त मरीजों का इलाज कराते हैं। इस खर्च के दबाव के चलते परिजनों को भी तमाम कष्ट उठाने पड़ते हैं। गाहे-बगाहे सरकारों ने दवा कंपनियों की बेलगाम मुनाफाखोरी रोकने को कदम उठाने की घोषणाएं तो कीं, लेकिन समस्या का सार्थक समाधान नहीं निकल पाया। चिकित्सा बिरादरी की तरफ से भी यदि इस दिशा में सहयोग मिलने लगे तो इस समस्या का समाधान किसी सीमा तक संभव हो सकता है। लेकिन विडंबना है कि ऐसा हो नहीं पा रहा है। एक संकट यह भी है कि दवा कंपनियों द्वारा प्रचार किया जाता है कि जेनेरिक दवाइयां रोग के उपचार में पर्याप्त रूप से सक्षम नहीं होती।

निस्संदेह, सरकारों को इस दिशा में गंभीरता से सोचना होगा कि जेनेरिक दवाइयों को प्रोत्साहन देने के उसके प्रयास क्यों सिरे नहीं चढ़ते। एक वजह यह भी है कि दवा कंपनियों की लॉबी खासी ताकतवर होती है और साम-दाम-दंड-भेद की नीति का उपयोग करके अपने उत्पादों का विपणन करने में सफल हो जाती है। ऐसे आक्षेपों से चिकित्सा बिरादरी भी दोषमुक्त नहीं हो सकती, जो दवा कंपनियों के लोभसंवरण से मुक्त नहीं हो पाती। सरकारों को देखना चाहिए कि दवा कंपनियों द्वारा पोषित कदाचार पर नियंत्रण के प्रयास जमीनी हकीकत क्यों नहीं बन पाते। यदि ये कदम सख्ती से उठाए जाएं तो गरीब मरीज गंभीर रोगों का उपचार करने में सक्षम हो पाएंगे। फिर उनके अपनों का इलाज उनकी क्षमता के अनुरूप हो सकेगा। निस्संदेह, लंबे उपचार व असाध्य रोगों के इलाज में दवाओं की कीमत एक प्रमुख घटक होता है। यदि दवा नियंत्रित दामों में मिल सके तो उनकी बड़ी चिंता खत्म हो सकती है। निस्संदेह, दवाओं की कीमत हमारी चिकित्सा सेवाओं के लिये एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। सरकार को चाहिए कि गांव से लेकर शहरों तक जेनेरिक दवाओं के मेडिकल स्टोर बड़ी संख्या में खोले जाएं। मरीजों के तिमारदार उन तक आसानी से पहुंच सकें। इस काम में स्वयं सेवा समूहों की मदद ली जा सकती है ताकि गरीब-अनपढ़ मरीजों को जागरूक करके जेनेरिक दवाइयों के उपयोग को प्रोत्साहित किया जा सके। मरीजों के परिजनों को विश्वास दिलाया जाना चाहिए कि जेनेरिक दवाइयां भी उसी साल्ट से बनी होती हैं, जिससे महंगी ब्रांडेड दवाइयां बनी होती हैं। निश्चित रूप से चिकित्सा बिरादरी का भी फर्ज बनता है कि वे अपने ऋषिकर्म का दायित्व निभाते हुए गरीब मरीजों को अधिक से अधिक जेनेरिक दवाइयां लिखना शुरू करें। यह उनके लिये भी पुण्य के काम जैसा होगा। लेकिन एक बात तो तय है कि सरकार असरकारी व समान गुणवत्ता की जेनेरिक दवाओं की बिक्री व सहज उपलब्धता के लिये युद्धस्तर पर प्रयास करे। साथ ही सूचना माध्यमों व स्वयं सेवी संस्थाओं की मदद से जागरूकता अभियान भी चलाए।

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को निभानी होगी जिम्मेदार मीडिया की भूमिका

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद शर्मा।

एक समय था जब आकाशवाणी की अपनी विश्वसनीयता रही। सरकारी प्रसारण होने के बावजूद घड़ी का समय मिलाने से लेकर नियतकालीन न्यूज प्रसारण समय पर लोग सब कुछ काम छोड़कर या फिर चौराहे की पान-चाय की दुकान पर जम जाते थे।

सच ही कहा है कि अति उत्साह में कभी भी संयम नहीं खोना चाहिए। ऑपरेशन सिन्दूर और उसके बाद की हालातों को जिस तरह से टीवी चैनलों द्वारा सनसनीखेज बनाकर प्रस्तुत किया जा रहा है भले ही इससे इन चैनलों की टीआरपी में बढ़ोतरी हो जाए पर यह किसी भी हालत में एक जिम्मेदार मीडिया की भूमिका नहीं हो सकती। आज देशवासी सही तस्वीर देखने को तरस गए हैं। कोई चैनल पाकिस्तान के किसी स्थान पर कब्जे की बात करता है तो कोई चैनल पाकिस्तान की सीमाओं में भारतीय सेना के प्रवेश की बात करता है। कोई चैनल कुछ और सनसनीखेज तस्वीर बताता है। यह सब ऑपरेशन सिन्दूर के अगले दिन रात के प्रसारणों से खासतौर से देखने को मिला। ठीक है देशभक्ति का जज्बा है और ऑपरेशन सिन्दूर से प्रत्येक देशवासी अपने आप को गर्वान्वित महसूस कर रहा है। हमारी सेना, हमारे सैनिकों और राजनीतिक नेतृत्व को लेकर प्रत्येक देशवासी में अति उत्साह और लबालब विश्वास है। इसमें कोई दो राय नहीं कि इस दौर में देश के प्रिन्ट मीडिया ने अपनी भूमिका सही तरीके से निभाई है। सवाल यही है कि क्या चैनलों या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का एकमात्र उद्देश्य गंभीर से गंभीर मुद्दे को सनसनीखेज ही बनाना है। गंभीरता को इसी से समझा जा सकता है कि केन्द्र सरकार को बार बार एडवाइजरी जारी करनी पड़ रही है तो आमजन समझ ही नहीं पा रहे कि वास्तविकता क्या है?

एक समय था जब आकाशवाणी की अपनी विश्वसनीयता रही। सरकारी प्रसारण होने के बावजूद घड़ी का समय मिलाने से लेकर नियतकालीन न्यूज प्रसारण समय पर लोग सब कुछ काम छोड़कर या फिर चौराहे की पान-चाय की दुकान पर जम जाते थे। प्रातः 8 बजे, रात पौने नो बजे व स्थानीय समाचारों के लिए निर्धारित समय पर लोग समाचार सुनने का बेसब्री से इंतजार करते थे। विश्वसनीयता यह कि सरकार विरोधी आंदोलनकारी भी सरकारी आकाशवाणी केन्द्रों से प्रसारित समाचारों पर पूरा पूरा विश्वास करते थे। यही कारण था कि समाचारों की विश्वसनीयता होती थी। दूरदर्शन का आंरभिक दौर भी इसी तरह का रहा है। आकाशवाणी और दूरदर्शन समाचारों की वह गौरवशाली परंपरा इतिहास की बात हो गई है। 1956, 1962 या 1971 का युद्ध हो सभी की निगाहें समाचार बुलेटिनों पर रहती थी तो समय की मांग को देखते हुए देशभक्ति पूर्ण गीतों, कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाता था। समय का बदलाव देखिये कि टीवी चैनलों की टीआरपी दौड़ सत्य दिखाने के स्थान पर भ्रम का जाल बुनने लगती है। सोशियल मीडिया पर यह आरोप आम है पर समाचार टीवी चैनल तो दो कदम आगे हो गए हैं।

समूचे देश के लिए गर्व की बात है कि आज सरहद के मोर्चे पर हो या कूटनीतिक मोर्चे पर हमारी रणनीति पूरी तरह से सफल है। हमारी सेना और सैनिक पाकिस्तान के हर कूटरचित कदमों को विफल करने में सफल हो रही है। पाकिस्तान द्वारा सीमावर्ती इलाकों और नागरिक क्षेत्रों में की जा रही सैन्य गतिविधियों को अंजाम देने के कुत्सित प्रयासों को पूरी तरह से विफल किया जा रहा है वही लगभग सभी द्रोण हमलों को विफल किया जा रहा है। पाकिस्तान अब पूरी तरह कुंठित देश हो गया है और आज तुर्की और चीन को छोड़कर कोई देश पाकिस्तान के पक्ष में आने को तैयार नहीं है। पहलगाम की घटना के बाद से पाकिस्तान एक के बाद एक गलतियां कर रहा है और आतंकवादी के जनाजे में सैनिकों द्वारा शामिल होना उसके आतंकवादियों से जुड़ाव को स्पष्ट कर देता है। अब पाकिस्तान ने अपनी तरफ से इकतरफा भारत के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी गई है अपितु परमाणु बम विस्फोट की धमकी दी जा रही है। पर जिस संयमित तरीके से भारत द्वारा पाकिस्तान के हर आक्रमण और कदम को विफल किया जा रहा है वह देश के लिए गर्व की बात है। आज पाकिस्तान का हर कदम उसके लिए आत्मघाती होता जा रहा है। बलूचियों को अलग अवसर मिल गया है तो पीओके में पाकिस्तान के विरोध को भी मुखर होने का अवसर मिल गया है।

पाकिस्तान को अपने नागरिकों के हित में अपनी भारत विरोधी नीति को छोड़ना ही होगा

प्रह्लाद सबनानी

भारत में केंद्र सरकार का वित्तीय बजट प्रतिवर्ष लगभग 50 लाख करोड़ रुपए से अधिक का रहता है जबकि पाकिस्तान का वित्तीय बजट केवल 5.65 लाख करोड़ भारतीय रुपए (पाकिस्तानी रुपए में 18.9 लाख करोड़ रुपए) का ही रहता है।

पाकिस्तान के जन्म के साथ ही वहां के राष्ट्रीय दलों एवं नेताओं ने भारत विरोध को अपनी अधिकारिक नीति बना लिया था। पाकिस्तान के आर्थिक विकास पर ध्यान नहीं देते हुए, किसी भी प्रकार भारत के हितों को क्षति पहुंचाई जाए, इस बात पर अधिक ध्यान दिया गया। भारत को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से पाकिस्तान द्वारा कई आतंकवादी संगठन खड़े किए जाते रहे एवं इन संगठनों के आतंकवादी सदस्यों को भारत भेजा जाता रहा। भारत, हालांकि पाकिस्तान द्वारा भारत में भेजे गए इन आतंकवादीयों को मौत के घाट उतारने में लगातार सफल होता रहा, परंतु, कुछ अवसरों पर इन आतंकवादीयों को भी भारत में अप्रिय घटनाओं को अंजाम देने में सफलता हासिल होती रही। वैश्विक मंचों पर भी पाकिस्तान भारत पर निराधार आरोप लगाकर भारत को बदनाम करने के लगातार प्रयास करता रहा है। भारत के इस अंधे विरोध के चलते पाकिस्तान की आर्थिक प्रगति पूर्णतः बाधित हुई है। भारत और पाकिस्तान वर्ष 1947 में एक साथ राजनैतिक स्वतंत्रता प्राप्त करते हुए आगे बढ़े थे। परंतु, आज पूरे विश्व में भारत एक महाशक्ति बन गया है जबकि पाकिस्तान लगातार केवल आतंकवादी संगठनों की स्थापना करते हुए आज विश्व में आतंकवादी पैदा करने की सबसे बड़ी फैक्टरी बन गया है तथा आर्थिक प्रगति के मामले में तो एकदम पिछड़ गया है।

आज भारत का सकल घरेलू उत्पाद 4.19 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है और भारत आज विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है जबकि पाकिस्तान का सकल घरेलू उत्पाद केवल 37,900 करोड़ रुपए का ही है। भारत में प्रति व्यक्ति आय 11,110 अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष है जबकि पाकिस्तान में प्रति व्यक्ति आय 6,720 अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष है, अर्थात भारत की तुलना में लगभग आधी, जबकि भारत की जनसंख्या 140 करोड़ से अधिक है तो वहीं पाकिस्तान की जनसंख्या केवल लगभग 25 करोड़ ही है। इसी प्रकार, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 68,800 करोड़ अमेरिकी डॉलर के स्तर को पार कर गया है, जो कि संभवतः इस वर्ष एक लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर को भी पार कर सकता है। वहीं, पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार केवल 1,500 करोड़ अमेरिकी डॉलर का ही है। पाकिस्तान पूरे विश्व में विभिन्न वित्तीय संस्थानों एवं देशों से सबसे अधिक बार ऋण लाने वाले एवं आर्थिक सहायता प्राप्त करने वाले देशों की सूची में प्रथम स्थान पर काबिज है। अभी भी, पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय मोनेटरी फंड से 700 करोड़ अमेरिकी डॉलर का ऋण लेने का प्रयास कर रहा है। जबकि भारत अन्य देशों को ऋण प्रदान करने की स्थिति में पहुंच गया है।

वित्तीय वर्ष 2022 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर 9.7 प्रतिशत एवं वित्तीय वर्ष 2023 में 7.6 प्रतिशत, वित्तीय वर्ष 2024 में 9.2 प्रतिशत एवं वित्तीय वर्ष 2025 में 6.5 प्रतिशत की रही है। इसके विपरीत पाकिस्तान के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर वित्तीय वर्ष 2022 में 6.2 प्रतिशत, वित्तीय वर्ष 2023 में ऋणात्मक 0.2 प्रतिशत, वित्तीय वर्ष 2024 में 2.5 प्रतिशत एवं वित्तीय वर्ष 2025 में 2.6 प्रतिशत की वृद्धि दर रही है। जबकि, भारत के सकल घरेलू उत्पाद का आकार पाकिस्तान के सकल घरेलू उत्पाद के आकार का 11 गुणा से भी अधिक है। भारत के बड़े आकार के सकल घरेलू उत्पाद पर वृद्धि दर भी अधिक है और पाकिस्तान के छोटे आकार के सकल घरेलू उत्पाद पर वृद्धि दर भी कम है। इससे तो भविष्य में पाकिस्तान, भारत की तुलना में और अधिक पिछड़ता जाएगा।

भारत में केंद्र सरकार का वित्तीय बजट प्रतिवर्ष लगभग 50 लाख करोड़ रुपए से अधिक का रहता है जबकि पाकिस्तान का वित्तीय बजट केवल 5.65 लाख करोड़ भारतीय रुपए (पाकिस्तानी रुपए में 18.9 लाख करोड़ रुपए) का ही रहता है। भारत का वार्षिक वित्तीय बजट पाकिस्तान के वार्षिक वित्तीय बजट से लगभग 10 गुणा है। पाकिस्तान के वार्षिक बजट के आकार से अधिक आकार का बजट तो भारत में अकेले उत्तर प्रदेश राज्य का ही है। भारत में केंद्र सरकार के उपक्रम एवं अन्य उपक्रम केंद्र सरकार को लाखों करोड़ रुपए की राशि डिवीडेंड के रूप में उपलब्ध करा रहे हैं। इस वर्ष, अकेले भारतीय रिजर्व बैंक ही 2.5 से 3 लाख करोड़ रुपए की राशि का लाभांश केंद्र सरकार को उपलब्ध कराने जा रहा है। अकेले वस्तु एवं सेवा कर संग्रहण ही लगभग 2.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक प्रति माह के स्तर पर पहुंच गया है। भारत में अप्रेल 2025 माह में 2.37 लाख करोड़ रुपए का वस्तु एवं सेवा कर संग्रहण हुआ है।

मीडिया की आज़ादी को कृत्रिम बुद्धिमत्ता की चुनौती

विजय गर्ग

किसी भी देश अथवा समाज में स्वतंत्र मीडिया के बिना स्वस्थ लोकतंत्र को सुनिश्चित कर पाना संभव नहीं हो सकता, क्योंकि मीडिया वास्तव में लोकतंत्र का प्रहरी होता है। लोकतंत्र का ही क्यों, मीडिया तो राष्ट्र, मानवीय सभ्यता और संस्कृति, यहां तक कि मानवता का भी रक्षक होता है। आश्चर्य नहीं कि समय-समय पर भारत एवं दुनिया भर में मीडिया ने अपनी भागीदारी एवं भूमिकाओं से इसे सही साबित भी किया है। यही कारण है कि मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। समय बीतने के साथ-साथ मीडिया ने अपने पिछले अनुभवों के आधार पर अपनी भागीदारी एवं भूमिकाओं में अपेक्षित परिवर्तनों के साथ विस्तार दिया है।

मीडिया के कार्य करने का मुख्य आधार 'जनपक्षधरता' और इसका प्रधान उद्देश्य 'जनता में जागृति' लाना होता है और इन्हीं दोनों कारणों से मीडियाकर्मियों यानी पत्रकारों के लिए बिना रोक-टोक, विरोध और अड़चन के अपने कार्यों का निष्पादन कर पाना कभी भी सहज नहीं रहा है। दरअसल, जनपक्षधरता और जनता में जागृति लाने का कार्य अत्यंत जोखिम भरा होता है। इसीलिए दुनिया भर में प्रायः पत्रकारिता को बेहद जोखिम भरा कार्य माना जाता है।

दुर्भाग्य से, दिनोंदिन जोखिम बढ़ने के कारण विश्व भर के लोकतांत्रिक देशों में पत्रकारों के लिए निष्पक्ष रहकर कार्य कर पाना लगातार मुश्किल और जोखिम भरा होता जा रहा है। कई बार अपने कार्यों का निष्पादन करते हुए पत्रकारों को अपनी जान भी गंवानी पड़ती है। अब तक विश्व भर से ऐसे कई उदाहरण सामने आ भी चुके हैं। यूनेस्को की एक रिपोर्ट के अनुसार, 2006 से 2020 के बीच दुनिया भर में 1,200 से अधिक मीडिया पेशेवरों की हत्या कर दी गई। इनमें से 90 प्रतिशत मामलों में उनके हत्यारे दंडित नहीं किए जा सके।

इसके बावजूद, पत्रकारिता के मानदंडों पर खरे उतरते हुए पत्रकार सत्य को उजागर करने की अपनी जिम्मेदारी निभाने को लेकर अपनी जान को जोखिम में डालने से भी नहीं हिचकते। अपनी जिंदगी को खतरे में डालकर कार्य करने वाले पत्रकारों की आवाज को कोई भी ताकत दबा न सके और उनके निष्पक्ष और सशक्त अभियानों पर कोई भी व्यक्ति, संस्थान या सरकार अंकुश न लगा सके, इसके लिए उनकी स्वतंत्रता बहुत जरूरी और अहम है। जाहिर है कि यदि वे स्वतंत्र नहीं रहेंगे तो अपने कार्यों को निष्पक्ष रहते हुए अच्छे ढंग से नहीं कर पाएंगे।

इसी बात को ध्यान में रखते हुए प्रेस की स्वतंत्रता के मूलभूत सिद्धांतों का पालन करने तथा पत्रकारों की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 3 मई को 'विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस' मनाया जाता है। यह दिन उन पत्रकारों को स्मरण और सम्मानित करने तथा श्रद्धांजलि देने के लिए भी मनाया जाता है, जिन्होंने सत्य को उजागर करने की कीमत अपनी जान देकर चुकाई है अथवा जिन्होंने देश-दुनिया में अपनी पत्रकारिता के दम पर अपना नाम बनाया और एक मुकाम हासिल किया है।

प्रतिवर्ष रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स (आरएसएफ) द्वारा प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक नामक एक वैश्विक सूची प्रकाशित की जाती है। इस सूची में विश्वभर के पत्रकारों को कार्य करने की उपलब्ध स्वतंत्रता के आधार पर देशों की रैंकिंग प्रस्तुत की जाती है। बता दें कि प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक रिपोर्ट 2024 में भारतीय पत्रकारों को लेकर चिंताजनक रुझान दिखाई दिए हैं। दरअसल, 2024 के इस सूचकांक में भारत विश्व भर के 180 देशों में 159वें स्थान पर मौजूद है, जो पिछली रिपोर्ट से भी नीचे है। रिपोर्ट में मीडिया स्वामित्व संकेन्द्रण, पत्रकारों का उत्पीड़न और इंटरनेट शटडाउन जैसे मुद्दों पर प्रकाश डाला गया है।

गौरतलब है कि 'विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस' मनाने के लिए यूनेस्को की ओर से प्रत्येक वर्ष एक वैश्विक सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। इस वैश्विक सम्मेलन में सामान्यतः पत्रकारों, मीडिया नेताओं, नीति निर्माताओं, शिक्षाविदों और गैर सरकारी संगठनों की भागीदारी होती है। बता दें कि 2025 में यह सम्मेलन 5 से 7 मई तक ब्रूसेल्स में आयोजित होने वाला है, जिसमें पत्रकारिता में एआई की परिवर्तनकारी भूमिका और मीडिया स्वतंत्रता के लिए इसके निहितार्थों पर ध्यान केंद्रित किया जाना है।

यूनेस्को द्वारा वर्ष 2025 के लिए विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की थीम 'रिपोर्टिंग इन द ब्रेव न्यू वर्ल्ड - द इम्पैक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन प्रेस फ्रीडम एंड द मीडिया' घोषित की गई है। इस थीम का उद्देश्य आधुनिक पत्रकारिता में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के बढ़ते प्रभाव पर प्रकाश डालना है। गौरतलब है कि इस थीम के माध्यम से विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2025 के अवसर पर तेजी से एआई-विनियमित डिजिटल वातावरण के भीतर मानव अधिकारों की रक्षा करने की तत्काल आवश्यकताओं पर जोर दिये जाने की संभावना है।

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब

“युद्ध से युद्धविराम तकः भारत-पाक रिश्तों की बदलती तस्वीर”

10 मई 2025 को, भारत और पाकिस्तान ने एक पूर्ण और तत्काल युद्धविराम पर सहमति व्यक्त की, जो हाल के वर्षों में सबसे गंभीर संघर्ष के बाद हुआ। 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद सैन्य तनाव बढ़ा था। अमेरिकी राष्ट्रपति की मध्यस्थता में हुई वार्ता के बाद, दोनों देशों ने इस संघर्ष को समाप्त करने का निर्णय लिया। हालांकि, सीमा पर स्थायी शांति अभी भी एक बड़ी चुनौती है। सच्ची शांति तब तक संभव नहीं है जब तक कि दोनों देश आपसी विश्वास, संवाद और सहयोग को प्राथमिकता न दें। युद्धविराम केवल एक कदम है, पर स्थायी शांति की दिशा में कई और कदम बढ़ाने की जरूरत है।

प्रियंका सौरभ

भारत और पाकिस्तान के बीच के संबंध हमेशा से तनावपूर्ण रहे हैं। दोनों देशों के बीच की सीमाएं न केवल भौगोलिक हैं, बल्कि राजनीतिक और सांस्कृतिक विभाजन भी हैं, जो 1947 में विभाजन के समय से आज तक खिंची हुई हैं। इस तनाव का सबसे बड़ा कारण जम्मू-कश्मीर का मुद्दा रहा है, जो आज भी विवाद का मुख्य बिंदु है।

1947-48: पहला युद्ध और पहला युद्धविराम

भारत और पाकिस्तान के बीच पहला युद्ध 1947-48 में हुआ, जिसे कश्मीर युद्ध के नाम से जाना जाता है। यह संघर्ष तब शुरू हुआ जब पाकिस्तान समर्थित कबायली लड़ाकों ने कश्मीर पर हमला किया। भारतीय सेना ने महाराजा हरि सिंह की सहायता के लिए कश्मीर में प्रवेश किया, जिसके बाद संघर्ष बढ़ता गया। इस युद्ध का अंत 1 जनवरी 1949 को संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेप के बाद हुआ, जिसने युद्धविराम की घोषणा की और दोनों देशों के बीच नियंत्रण रेखा (LoC) स्थापित की। यह युद्धविराम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 47 के तहत हुआ था, जिसमें कश्मीर में जनमत संग्रह की बात कही गई थी, जो आज तक पूरा नहीं हो पाया।

1965 का युद्ध और ताशकंद समझौता

1965 में, कश्मीर मुद्दे पर फिर से संघर्ष भड़क उठा। इस बार पाकिस्तान ने 'ऑपरेशन जिब्राल्टर' शुरू किया, जिसमें पाकिस्तानी सेना ने कश्मीर में घुसपैठ की। भारत ने इसका कड़ा जवाब दिया और युद्ध पंजाब, राजस्थान और कश्मीर में फैल गया। इस युद्ध का अंत 23 सितंबर 1965 को हुआ, जब संयुक्त राष्ट्र और सोवियत संघ के मध्यस्थता के बाद ताशकंद समझौता हुआ। इस समझौते पर 10 जनवरी 1966 को भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर

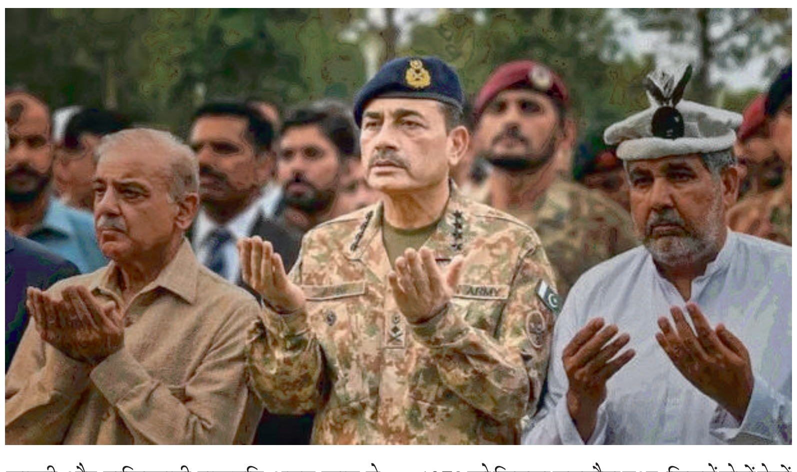

शास्त्री और पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयूब खान ने हस्ताक्षर किए।

1971 का युद्ध और शिमला समझौता

1971 का युद्ध मुख्य रूप से बांग्लादेश की स्वतंत्रता के मुद्दे पर हुआ था। पाकिस्तान में पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों के बीच तनाव बढ़ता गया और पूर्वी पाकिस्तान (आज का बांग्लादेश) में स्वतंत्रता की मांग ने युद्ध का रूप ले लिया। भारत ने बांग्लादेश की स्वतंत्रता संग्राम का समर्थन किया और 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान को निर्णायक हार का सामना करना पड़ा। इस युद्ध के बाद 2 जुलाई 1972 को शिमला समझौता हुआ, जिसमें दोनों देशों ने सभी विवाद शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने का वादा किया और नियंत्रण रेखा (LoC) की स्थापना की गई।

1999 का कारगिल युद्ध

कारगिल युद्ध 1999 में हुआ, जब पाकिस्तानी सैनिकों ने कारगिल-ड्रास सेक्टर में भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की। इस संघर्ष में दोनों देशों के बीच भीषण लड़ाई हुई और कई सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति दी। यह युद्धविराम 26 जुलाई 1999 को समाप्त हुआ, जब भारत ने अपने क्षेत्र को पुनः प्राप्त कर लिया।

2003 का स्थायी युद्धविराम

नवंबर 2003 में, दोनों देशों ने नियंत्रण रेखा पर स्थायी युद्धविराम की घोषणा की, जो एक महत्वपूर्ण कदम था। इस पहल ने सीमा पर हिंसा में कमी लाई और कश्मीर में सामान्य जनजीवन को स्थिर किया। हालांकि, इस युद्धविराम का पालन समय-समय पर उल्लंघन का शिकार होता रहा है।

हालिया प्रयास और चुनौतियाँ

2021 में, भारत और पाकिस्तान ने फिर से युद्धविराम का पालन करने की सहमति जताई, जिसे 2003 के समझौते का नवीनीकरण कहा जा सकता है। यह निर्णय दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों के बीच हुई एक गुप्त वार्ता का नतीजा था।

हालांकि, सीमा पर होने वाली घटनाएं और कश्मीर में बढ़ता तनाव इन प्रयासों को कमजोर करते हैं। दोनों देशों के बीच विश्वास की कमी और आतंकवाद के मुद्दे पर मतभेद इन समझौतों को पूरी तरह से सफल नहीं होने देते।

2025: नवीनतम युद्धविराम और वर्तमान स्थिति

10 मई 2025 को, भारत और पाकिस्तान ने एक पूर्ण और तत्काल युद्धविराम पर सहमति व्यक्त की, जो हाल के वर्षों में सबसे गंभीर संघर्ष के बाद हुआ। यह संघर्ष 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए एक आतंकवादी हमले के बाद शुरू हुआ, जिसमें 26 लोग मारे गए थे। इस हमले के बाद दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई, जिसमें मिसाइल और ड्रोन हमले शामिल थे।

संयुक्त राज्य अमेरिका की मध्यस्थता में हुई वार्ता के बाद, दोनों देशों ने युद्धविराम पर सहमति जताई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस समझौते की घोषणा करते हुए दोनों देशों की सराहना की।

हालांकि, इस युद्धविराम के बावजूद, भारत और पाकिस्तान के बीच कई मुद्दे अभी भी अनसुलझे हैं, जैसे कि सिंधु जल संधि का निलंबन और सीमा पर तनाव। दोनों देशों ने आगे की वार्ता के लिए सहमति जताई है, लेकिन विश्वास की कमी और पिछले अनुभवों के कारण स्थिति अभी भी नाजुक बनी हुई है।

भारत और पाकिस्तान के बीच युद्धविराम की यह यात्रा संघर्ष, रक्तपात और राजनैतिक बदलावों से भरी रही है। आज, इन दोनों परमाणु संपन्न देशों के बीच स्थायी शांति स्थापित करना न केवल दक्षिण एशिया बल्कि पूरे विश्व के लिए महत्वपूर्ण है। एक स्थायी समाधान के बिना, युद्धविराम केवल एक अस्थायी राहत बना रहेगा। सच्ची शांति तब तक संभव नहीं है जब तक कि दोनों देश आपसी विश्वास, संवाद और सहयोग को प्राथमिकता न दें। युद्धविराम केवल एक कदम है, पर स्थायी शांति की दिशा में कई और कदम बढ़ाने की जरूरत है।

कर्नल सोफिया और विंग कमांडर व्योमिका ने महिलाओं में जगाई उम्मीद की किरण

योगेंद्र योगी

पुणे में साल 2016 में आसियान प्लस देशों का बहुराष्ट्रीय फील्ड प्रशिक्षण अभ्यास फोर्स 18 में 40 सैनिकों की भारतीय सेना की टुकड़ी का नेतृत्व सिग्नल कोर की महिला अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया कुरैशी ने किया था।

पहलगाम में पर्यटकों की नृशंस हत्या करने के बदले में भारत की पाकिस्तान पर स्ट्राइक की सफलता की जानकारी देने वाली भारतीय सुरक्षा बलों की दो महिला सैन्य अधिकारियों ने देश में महिलाओं के विपरीत हालात के बीच महिला सशिक्तकरण का सशक्त उदाहरण पेश किया है। देश भर में चर्चित लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया कुरैशी और वायु सेना में विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने साबित कर दिया कि महिलाएं अदम्य साहस के साथ किसी भी चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। निश्चित तौर पर युद्ध जैसी स्थिति के दौरान इन दोनों सैन्य अधिकारियों ने जिस शानदार तरीके से स्ट्राइक का विवरण पेश किया, उससे न सिर्फ महिलाओं में उत्साह का संचार होगा बल्कि हर मुश्किल हालात से निपटने के लिए साहस का उद्गम होगा।

पुणे में साल 2016 में आसियान प्लस देशों का बहुराष्ट्रीय फील्ड प्रशिक्षण अभ्यास फोर्स 18 में 40 सैनिकों की भारतीय सेना की टुकड़ी का नेतृत्व सिग्नल कोर की महिला अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया कुरैशी ने किया था। कुरैशी को बहुराष्ट्रीय अभ्यास में भारतीय सेना के प्रशिक्षण दल का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी बनने का दुर्लभ गौरव हासिल हुआ। गुजरात निवासी सैन्य परिवार से आने वाली सोफिया कुरैशी साल 1999 में 17 साल की उम्र में शॉर्ट सर्विस कमीशन के ज़रिए भारतीय सेना में आई थीं। उन्होंने छह साल तक संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना में भी काम किया। इसमें साल 2006 में कॉन्गो में एक उल्लेखनीय कार्यकाल शामिल है। उस वक्त उनकी प्रमुख भूमिका शांति अभियान में ट्रेनिंग संबंधित योगदान देने की थी। सोफिया कुरैशी के अलावा ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी की ब्रीफिंग देने वाली विंग कमांडर व्योमिका सिंह दूसरी चर्चित अधिकारी थीं। व्योमिका सिंह भारतीय वायु सेना में हेलीकॉप्टर पायलट हैं। उनके नाम का मतलब ही आसमान से जोडऩे वाला है। नेशनल कैडेट कोर (एनसीसी) की कैडेट रही व्योमिका सिंह ने इंजीनियरिंग की। उन्हें साल 2019 में भारतीय वायुसेना के फ्लाइंग ब्रांच में पायलट के तौर पर परमानेंट कमीशन मिला। व्योमिका सिंह ने 2500 घंटों से ज्यादा उड़ान भरी है। उन्होंने जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर भारत में मुश्किल हालात में चेतक और चीता जैसे हेलीकॉप्टर उड़ाए हैं। उन्होंने कई बचाव अभियान में भी अहम भूमिका निभाई है। इनमें से एक ऑपरेशन अरुणाचल प्रदेश में नवंबर 2020 हुआ था। इन दोनों महिला सैन्य अधिकारियों ने जिस आत्मविश्वास और दृढ़ता से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की गाथा पेश कि वह न सिर्फ देशवासियों के दिल-दिमाग में अमिट रहेगी बल्कि तमाम बाधाओं के बावजूद महिलाओं में आगे बढऩे की ललक कायम रखेगी। इनके जज्बे ने साबित कर दिया कि महिलाऐं देश में हर क्षेत्र में तरक्की का परचम लहरा रही हैं, चाहे वह क्षेत्र सैन्य जैसा चुनौतीपूर्ण और साहसिक क्षेत्र ही क्यों न हो। देश में महिला सशिक्तकरण की दिशा में इन दोनों महिलाओं का प्रदर्शन महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। महिलाओं के सपने पूरा करने में मदद करेगा। देश के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं का अग्रणी प्रदर्शन विकसित बनने की दिशा में अग्रसर भारत की नई तस्वीर पेश करता है।

सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह जैसी देश का प्रतिनिधित्व करने वाली महिलओं की सफलता की प्रेरणा के बावजूद देश की आम महिलाओं के लिए अभी भी मंजिल आसान नहीं हैं। भारत में पितृसत्तात्मक मानसिकता और लैंगिक असमानता के चलते महिलाओं को विरोधाभासी भूमिकाएँ निभाने के लिए मजबूर किया जाता है। महिलाओं की ताकत को यह सुनिश्चित करने के लिए उभारा जाता है कि वे बेटियों, माताओं, पत्नियों और बहू के रूप में पालन-पोषण करने वाली अपनी पारंपरिक भूमिकाएँ प्रभावी ढंग से निभाएँ। दूसरी ओर, एक ₹कमज़ोर और असहाय महिला₹ की रूढ़िवादिता को बढ़ावा दिया जाता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे अपने पुरुष समकक्ष पर पूरी तरह से निर्भर हैं।

भारत में लैंगिक असमानता महिलाओं की वर्तमान स्थिति प्रगति और चल रही चुनौतियों के जटिल अंतर्संबंध से जुड़ी है। लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण की दिशा में कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हासिल की गई हैं। हालाँकि, गहराई से जड़ जमाए हुए सामाजिक मानदंड, आर्थिक असमानताएँ और राजनीतिक चुनौतियाँ यह दर्शाती हैं कि भारत में लैंगिक असमानता अभी भी मौजूद है। विडंबना यह है कि हमारे भारतीय समाज में जहाँ महिलाओं को देवी के रूप में पूजा जाता है, महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है और उन्हें समान अवसर से वंचित रखा जाता है।

भारत में लैंगिक असमानता अंतर रिपोर्ट, 2023 के अनुसार, लिंग समानता के मामले में भारत 146 देशों में से 127वें स्थान पर है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस-5, 2019-21) के अनुसार, भारत में कुल लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 1020 महिलाएँ हैं। हालाँकि, जन्म के समय लिंग अनुपात 929 पर कम बना हुआ है, जो जन्म के समय लिंग चयन जारी रहने का संकेत देता है। भारत के रजिस्ट्रार जनरल मातृ मृत्यु दर रिपोर्ट (एमएमआर) के अनुसार, 2018-20 की अवधि के लिए भारत की एमएमआर 97 प्रति लाख जीवित जन्म है। एनएफएचएस-5 के अनुसार 15-49 वर्ष की आयु की 18.7 प्रतिशत महिलाएँ कम वजन की हैं। 15-49 वर्ष की आयु की 21.2 प्रतिशत महिलाएँ अविकसित हैं और 15-49 वर्ष की आयु की लगभग 53 प्रतिशत महिलाएँ एनीमिया से पीड़ित हैं। इसी रिपोर्ट के अनुसार 20-24 वर्ष की आयु की 23.3 प्रतिशत महिलाएं 18 वर्ष की आयु से पहले विवाहित या विवाहित थीं। एनएफएचएस-5 (2019-21) की रिपोर्ट के अनुसार, पुरुषों की साक्षरता दर 84.7 प्रतिशत की तुलना में महिलाओं की साक्षरता दर 70.3 प्रतिशत है। नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो की लिंग आधारित हिंसा ₹भारत में अपराध₹ 2021 की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के खिलाफ अपराध के 4 लाख से अधिक मामले दर्ज किए गए। भारत में लिंगों के बीच वेतन अंतर दुनिया में सबसे ज़्यादा है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 के अनुसार, भारत में महिलाओं को औसतन पुरुषों की तुलना में 21 प्रतिशत वेतन मिलता है। पीएलएफएस रिपोर्ट के अनुसार 2021-22 में कामकाजी आयु (15 वर्ष और उससे अधिक) की केवल 32.8 प्रतिशत महिलाएं ही श्रम बल में थीं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार भारत में महिलाओं का 81.8 प्रतिशत रोजगार अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में केंद्रित है। यह दर्शाता है कि भारत में अधिकांश महिला श्रमिक उच्च वेतन वाली नौकरियों में नहीं आ पाती हैं।

भारत के चुनाव आयोग के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, दिसंबर 2023 तक राज्य विधानसभाओं में कुल औसत महिला प्रतिनिधित्व सिर्फ 13.9 प्रतिशत है। अप्रैल 2023 के पंचायती राज मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पंचायतों में निर्वाचित प्रतिनिधियों में लगभग 46.94 प्रतिशत महिलाएँ हैं। हालाँकि सरपंच-पति संस्कृति के प्रचलन का मतलब है कि यह आँकड़ा प्रभावी रूप से बहुत कम है। यह निश्चित है कि महिलाओं के उत्थान संबंधी आंकड़े कोई उत्साहवद्र्धक तस्वीर पेश नहीं करते हैं, किन्तु सैन्य अधिकारी सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह जैसी महिलाओं की लिखी सफलता की नई इबारत मौजूदा हालात के बीच तरक्की से वंचित महिलाओं के लिए एक उम्मीद की किरण है।

भारत ने हमला नहीं, जवाबी कार्रवाई की है

उमेश चतुर्वेदी

भारत ने काफी सावधानी से इन स्थलों को चुना और मिसाइल एवं ड्रोन के जरिए निशाना बनाया। भारत की कोशिश यह रही कि उसकी कार्रवाई की जद में सामान्य नागरिक ना आएं। लेकिन पाकिस्तान ने इसे खुद पर हमला माना।

चाहे दुश्मन की हों, या अपनी, सेनाएं हमेशा चौकस रहती हैं। ऐसे में छह और सात मई की दरमियानी रात भारतीय सेनाएं जिस तरह पाकिस्तान और उसके कब्जे वाले कश्मीर की नौ जगहों पर सफल निशाना साधने में कामयाब रहीं, उससे पाकिस्तान की सेना, उसकी चौकसी और चीन से खरीदे उसके चौकसी वाले तंत्र पर सवाल उठता है। भारत ने यह कार्रवाई पहलगाम में 22 अप्रैल को बहे बेगुनाह खूनों के जवाब में किया। भारत के खबरिया टीवी चैनल अक्सर ही जल्दबाजी में रहते हैं। उनके यहां सोच-विचार की प्रक्रिया की गुंजाइश कम है। शायद यही वजह है कि भारतीय कार्रवाई को उन्होंने पाकिस्तान पर हमला बताने में देर नहीं लगाई। लेकिन यह ध्यान रखने की बात है कि हमला एक तरह से युद्ध की शुरुआत होता। इस लिहाज से देखें तो भारत ने जवाबी कार्रवाई की है, हमला नहीं। क्योंकि भारत ने अपनी तरफ से शुरूआत नहीं की है।

इसमें दो राय नहीं कि पहलगाम में बहाए गए बेगुनाह खूनों के चलते देश में गुस्से की लहर थी। पहलगाम में आतंकियों ने जिन 26 बेगुनाह लोगों का खून बहाया, उनमें एक नेपाली नागरिक भी था। हैरत की बात यह है कि इन बेगुनाहों खून बहाते वक्त आतंकियों ने बाकायदा उनसे नाम पूछा, उन्हें कुरान की आयत और कलमा पढ़ने को बोला। यहां तक कि उनके वस्त्र उतारकर उनके अंदरूनी अंगों को देखा और हिंदू होने की तसल्ली होते ही बिना वजह गोलियों सो उड़ा दिया। उसमें दो ऐसी महिलाएं विधवा हुईं, जिनके माथे पर कुछ ही दिनों पहले सिंदूर का तेज शामिल हुआ था। आतंकियों ने धर्म के नाम पर इन महिलाओं का सुहाग उजाड़कर सिर्फ इन महिलाओं और उनके परिवारों को सूना ही नहीं किया, बल्कि भारतीय सहनशक्ति को चुनौती दे दी। भारत में गुस्से की लहर उड़ना स्वाभाविक था। बिहार के मधुबनी में एक सभा में प्रधानमंत्री मोदी का कहना कि सुहाग उजाड़ने वाले आतंकियों का पीछा करके उन्हें खोजकर मिट्टी में मिला दिया जाएगा, उस गुस्से की ही अभिव्यक्ति थी। उसी अभिव्यक्ति को भारतीय सेनाओं ने बीती छह और सात मई की आधी रात को एक बजकर पांच मिनट से डेढ़ बजे के बीच जमीनी हकीकत बना दिया। इस हमले में पाकिस्तान के बहावलपुर स्थित मौलाना मसूद अजहर का केंद्र भी रहा, जिसने थोक के भाव से आतंकियों को पैदा किया और भारत निर्यात किया है। जिसमें 26 नवंबर 2008 को मुंबई को खून से लाल कर देने वाले अजमल कसाब और उसका षडयंत्र रचने वाले रिचर्ड हेडली भी शामिल थे।

भारत ने काफी सावधानी से इन स्थलों को चुना और मिसाइल एवं ड्रोन के जरिए निशाना बनाया। भारत की कोशिश यह रही कि उसकी कार्रवाई की जद में सामान्य नागरिक ना आएं। लेकिन पाकिस्तान ने इसे खुद पर हमला माना। दिलचस्प यह है कि उसने आतंकी ठिकानों को नागरिक ठिकाने बताना शुरू किया। इसके साथ ही उसने अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सामने यह भी बताना तेज कर दिया कि भारत ने मासूमों को निशाना बनाया है। फिर उसने आतंकवादी कार्रवाई पर साझा जांच का प्रस्ताव रखा। लेकिन अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने इसे स्वीकार नहीं किया है।

पाकिस्तान एक तरफ जहां खुद को प्रताड़ित बता रहा है, वहीं वह सात-आठ मई की रात से लगातार भारतीय क्षेत्रों में हमला कर रहा है। दुखद बात यह है कि वह खुद भारतीय क्षेत्र में नागरिक ठिकानों और घरों को निशाना बना रहा है। कश्मीर सीमा पर पुंछ में उसने एक गुरूद्वारे पर हमला किया, जिसमें रागी समेत चार लोगों की मौत हो गई। पाकिस्तान लगातार भारत के सैनिक ठिकानो पर हमला कर रहा है। इन पंक्तियों के लिखे जाने तक वह तकरीबन पूरी पश्चिमी सीमा पर मिसाइल, मोर्टार, ड्रोन और हवाई हमले कर चुका है। उसने चंडीगढ़, जैसलमेर, बाड़मेर, उरी, अखनूर, पहलगाम, जम्मू, लेह, सर क्रीक, भुज समेत तमाम सैनिक ठिकानों पर निशाना साधने की कोशिश कर चुका है। यह बात और है कि भारत की जवाबी कार्रवाई में उसके तकरीबन सभी प्रयास नाकाम कर दिए गए। दिलचस्प यह है कि पाकिस्तान के इन हमलों को निष्फल करने वाली आकाश मिसाइल को भारत की अपनी स्वदेशी कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने बनाया है। भारत ने उनके तीन सैनिक ठिकाने जहां तबाह किए हैं, वहीं उसको लगातार जवाब दिया जा रहा है।

भारत को अपने षडयंत्र का निशाना बनाने वाले भारतीय मूल के आसिफ मुनीर लगातार हालात को बिगाड़ने की कोशिश में लगे हैं। सुनने में भले ही अजूबा लगे, भारत के खिलाफ आतंकी युद्ध के पीछे भारत से पाकिस्तान गए लोगों का ही हाथ रहा...ठीक 26 साल पहले पाकिस्तान ने सियाचिन इलाके में घुसपैठ के जरिए हम पर करगिल का युद्ध थोप दिया था.. उस युद्ध के पीछे जनरल परवेज मुशर्रफ का हाथ था..पाकिस्तान जाने से पहले परवेज का परिवार दिल्ली के चांदनी चौक में रहता था..पहलगाम की नृशंस आतंकी कार्रवाई का षडयंत्र किस्तान के जनरल आसिफ मुनीर ने रचा। यहां जानना जरूरी है कि आसिफ का परिवार भी भारत से पाकिस्तान गया था..बंटवारे से पहले आसिफ का परिवार जालंधर में रहता था..

भारत की जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तान लगातार मुंह की खा रहा है। इसके बावजूद वह दुष्प्रचार के जरिए अपनी डींगे हांक रहा है। पाकिस्तान अपने लोगों को लगातार बता रहा है कि उसकी सेनाओं ने भारत की सेना या वायुसेना को इतना नुकसान पहुंचाया। जबकि उसके ये दावे कोरे झूठ हैं। इस लिहाज से देखें तो भारत दो मोर्चों पर जूझ रहा है..पहला मोर्चा जहां सैनिक है, वहीं दूसरा मोर्चा सूचनाओं का है..अरब क्रांति के दौरान देवता के रूप में उभरा सोशल मीडिया अब देवता और दैत्य-दोनों ही भूमिकाओं में है..पाकिस्तान इन दिनों सोशल मीडिया की दैत्य वाली भूमिका का खूब उपयोग करते हुए भारत के बारे में लगातार गलत सूचनाएं दे रहा है..अपनी सेनाओं की झूठी कामयाबियों को इसी के जरिए वह फैला रहा है। भारत पर आरोप लगा रहा है कि भारतीय सेनाएं रिहायशी इलाकों और धार्मिक स्थानों पर हमला कर रही हैं.लेकिन यह गलत है और भारत का सार्वजनिक सूचना तंत्र और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय लगातार इन भ्रामक सूचनाओं को तथ्यों के साथ खारिज कर रहे हैं और पाकिस्तान के झूठ को बेपर्दा कर रहे हैं। वैसे यह दुनिया का जाना-पहचाना तथ्य है कि सीधी लड़ाई में नाकाम रहने वाले ही फर्जी खबरों का सहारा लेते हैं। सीधा युद्ध जो नहीं कर सकता, वही शेखी भी बघारता है। पाकिस्तान के दुष्प्रचार को इसी नजरिए से देखा जाना चाहिए।

सच्चाई तो यह है कि भारत ने ज्यादातर पाकिस्तानी आतंकी उत्पाद केंद्रों और रक्षा केंद्रों को निशाना बनाया है। एक तरह से देखें तो भारत इस बार आतंक की फैक्ट्रियों के खात्मे को लेकर दृढ़ संकल्प नजर आ रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान ड्रोन और मिसाइलों से हमला कर रहा है और फिर उससे इनकार भी कर रहा है। इससे उसका डर भी जाहिर हो रहा है। भारत में यह मानने वालों की संख्या कम नहीं है कि पाकिस्तान का यह डर और बढ़ाया जाना चाहिए। पता नहीं यही वजह है या नहीं, लेकिन भारत की जवाबी कार्रवाई एक तरह से उसके डर को ही बढ़ाने की कोशिश कर रही है।

'मां' मुझे चट्टान सा मजबूत करतीं है। (अंतरराष्ट्रीय मातृ दिवस विशेष आलेख)

11 मई 2025 को हम सभी अंतरराष्ट्रीय मातृ दिवस मनाने जा रहें है। सर्वप्रथम सभी माताओं को इस लेखक का कोटिशः नमन। 'मां' एक शब्द मात्र नहीं है, अपितु यह इससे भी कहीं अधिक बढ़कर है। 'मां' विधाता की इस धरती पर बहुत बड़ी देन है। ईश्वर के बाद यदि कोई सबसे बड़ी पालनहार है तो वह 'मां' ही तो है।सच तो यह है कि माँ हर किसी के लिए इस प्रकट दुनिया से जुड़ने का पहला ज़रिया है।हम अपनी माँ के ज़रिए इस दुनिया में आए, और बेशक़ अपने पिता के ज़रिए भी। हम सभी में कहीं न कहीं मातृत्व है, मातृत्व की भावना है। मातृत्व का मतलब है-' दूसरों के लिए सबसे अच्छा चाहना और बदले में कुछ भी उम्मीद न करना।' 'मां' को हम किसी दिन विशेष में नहीं समेट सकते हैं। सच तो यह है कि हर दिन 'मां का दिन' है। कहना ग़लत नहीं होगा कि अपनी माँ के प्रति हमारे अंदर असीम प्रेम होता है, क्योंकि हमने अपने अस्तित्व की शुरुआत उसी के एक अंश के रूप में की थी। 'मां' प्रेम है, शुद्ध प्रेम, बिना शर्त वाला प्रेम। यह 'मां' ही है जो अपने बच्चों को 'बिना शर्त प्रेम' करती है, दुनिया में 'मां' जैसा कोई नहीं। मां पर लिखने के लिए हरेक दिन है, हर समय है, हर पल है, हर क्षण है। 'मां' को कोई भी व्यक्ति मात्र शब्दों में नहीं समेट सकता, उसे परिभाषित नहीं कर सकता, क्यों कि इतनी क्षमता शायद किसी भी में नहीं है कि वो 'मां' को शब्दों के जाल से परिभाषित कर दे। 'मां' संपूर्ण सृष्टि है। वह सृजन है। सच तो यह है कि 'मां' से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए आज मन किया कि 'मां' पर लिखूं। यह 'मां' का ही आशीर्वाद है, सानिध्य, मंगलकामनाएं है कि आज मैं 'मां' पर चंद शब्द लिख पा रहा हूं, क्यों कि 'मां' ने ही मुझे अस्तित्व में लाकर सबकुछ सिखाया है। मां के नाम से ही मैं हमेशा बहुत भावुक हो जाता हूँ। ईश्वर की नैमत्त जो है ‘मां’। अभी हाल फिलहाल, घर पर नहीं हूँ, ड्यूटी पर हूँ। अपने गांव-घर से बहुत दूर, हिमालय की वादियों के बीच, सीमा पर; लेकिन यहां बहने वाली ठंडी बयारों में, यहां की वनस्पतियों में, यहां की नदियों की कल-कल में, यहां के पक्षियों की चहचहाहट में, मैं हर क्षण हर पल 'मां' को महसूस करता हूं। मैं एक फौजी हूं और हरेक फ़ौजी की एक नहीं बल्कि दो 'मां' होतीं हैं। एक जन्म देने वाली 'मां' और दूसरी 'धरती मां।' मैं उन खुशनसीब और अति भाग्यशाली लोगों की सूची में शुमार हूँ, जिन्हें एक नहीं अपितु दो दो माताओं का सानिध्य प्राप्त है और आज मैं इस माँ (धरती मां) और उस मां (जन्म देने वाली 'मां') दोनों के कारण ही यहां पर हूं। हाल फिलहाल, मैं मेरी जन्म देने वाली 'मां' के पास नहीं हूँ, लेकिन 'मां' का सानिध्य हमेशा मेरे साथ है। बहरहाल, काफी समय पहले मैंने 'मां' के बारे में एक शेर पढ़ा था।आज काफी समय बाद घिर-घिर कर वह शेर यहां याद आ रहा है। शेर है - 'मैंने कल शब चाहतों की सब किताबें फाड़ दी, सिर्फ एक कागज़ पे लिक्खा शब्द माँ रहने दिया !'यह प्रसिद्ध शेर मुनव्वर राणा जी का है। वाह ! मां के बारे में उन्होंने क्या शानदार अभिव्यक्ति दी है। वास्तव में, 'मां' होती ही ऐसी हैं। 'मां' तो 'मां' है। 'मां' आचमन है। ईश्वर जिसमें छुपकर बैठा प्रकृति का वो आभार है 'माँ'। ''मां' ममता, त्याग, वात्सल्य, प्यार, करूणा, दया, तप, तपस्या की प्रतिमूर्ति है। उसकी गोद में स्नेह है, वह फूलों की क्यारी है, ममत्व की मिसाल है। उसकी छांव में शीतलता का अहसास है। वह विश्वास है, वह हिम्मत है, वह आत्मविश्वास है। उसके आंचल में

ठंडी 'लोरी' का अहसास है। वह धरती पर ईश्वर का प्रतिबिंब है। 'मां' धरती है, 'मां' आकाश है, 'मां' ब्रहांड है। 'मां' समन्दर है। 'मां' सृजन है।'मां' लहरें है। 'मां' डगर है। 'मां' रास्ता है, 'मां' मंजिल है। 'मां' संबल है। 'मां' असीम आनंद है, 'मां' सकारात्मकता है। 'मां' शांत, सुंदर, निर्मल मंद मंद बहती बयार है। 'मां' नथुनों में रमी बसी सुरभि है। 'मां' चंदन है, 'मां' वंदन है, 'मां' अभिनंदन है, 'मां' जीवन ज्योति है। 'मां' दीपक है, 'मां' उज्ज्वल निरंतर बहता प्रकाश है। 'मां' निर्मल कोई झरना है। वह क्या नहीं है ? अर्थात 'मां' सबकुछ है। 'मां' है, तो इस जग में सबकुछ संभव है, 'मां' है तो ये जीवन सुख का सागर है, 'मां' गागर है। 'मां' की महिमा अपरंपार है। ग्यारह मई या मई का दूसरा रविवार ही नहीं, सारे ही दिन 'मां' के होते हैं। पिछले पांच महीनों से त्योहार पर भी घर नहीं आ पाया, कोई ग़म नहीं है, क्यों कि यहां भी तो मेरे पास मेरी धरती 'मां' है, जन्म देने वाली 'मां' का साया हरदम, हरपल मेरी सांसों में समाया है, जो मुझे प्रेरणा देती है, मेरी रगो में हरदम साहस और सकारात्मकता भरती है। हिमालय की इन वादियों के बीच सीमा पर तैनात अपनी ड्यूटी पर तैनात होते हुए भी अपनी दोनों मांओं के किरदार को हर पल, हर क्षण जीता हूँ। हर दौर में वे मेरे साथ हैं। मेरी ' मां' (जन्म देने वाली मां) और मेरी मातृभूमि जो मेरी 'मां' हैं, मेरी चुनौती भरी राहों में मुझमें खुशी, उमंग व उल्लास भरती है। फिर भी 'मैं' भी अन्य लोगों की तरह एक इंसान हूं, कोई 'दैव' या 'दैविक शक्ति' नहीं।फौज में, घर से दूर होने के कारण बच्चों के साथ परिवार की भी चिंता होने लगती है, आम इंसान की तरह मुझे भी यह महसूस होता है कि घर पर सभी कैसे व किस हाल में होंगे, पिताजी को कोई दिक्कत तो नहीं है, छोटे भाई को स्वास्थ्य की थोड़ी समस्या है, बच्चों की पढ़ाई, उनके स्वास्थ्य की चिंता मुझे भी रहती है, लेकिन ऐसी परिस्थितियों में मेरी 'मां' ही मुझे फोन पर सभी चिंताओं से मुक्त करती है, मेरी रगों में विश्वास की लहरें भरती हैं। 'मां' से दूरभाष पर मन की बातें करके हल्का हो जाता हूँ। कभी किसी समस्या या परेशानी से आहत होकर अंदर से जब टूटने लगता हूँ, तो 'मां' मुझे चट्टान सा मजबूत करतीं है। 'मां' मुझे सहलाती है, दुलारती है, प्यार करती है। मुझे मेरी 'मां' पर गर्व है। मैं हर 'मां' को बारंबार नमन करता हूँ। अंत में, 'मां' पर एक कविता यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ-

'जिसकी गोदी में खेले है
आज क्यों पराई ₹मां₹ ?
सर्वस्व त्याग दिया जिसने
वृदाश्रम में क्यों आई ‘मां’ ?
उंगली पकड़कर सीखा चलना
रोटी खातिर आज पराई ‘मां’
खुद सोती थी गीले में, हमें सूखे में सदा सुलाया
तार तार वसन, कतरन हाथ आई ‘मां’
आशीर्वाद हाथ सदा धरे
जख्म.आज क्यों खाई ‘मां’ ?
याद है चूल्हे की रोटी, निवाले हाथ से खिलाये
रूखी सूखी खाकर भी, मुस्कान चेहरे पर लाई ‘मां’
डांट में भी प्यार छुपा है
करूणा से आंखे छलछलाई ‘मां’
घर के टुकड़े होने से जोडे.
दुख सहकर भी खिलखिलाई ‘मां’
जीतने का साहस भरे रगो में
कुर्सी पाकर न याद आई ‘मां’
चोट पर मरहम पट्टी
सहलाती, दुख मनाती, हल्के हाथों से लगाती दवाई ‘मां’
धरती पर स्वर्ग है, वात्सल्य की देवी है
आज क्यों जग हंसाई ₹मां₹ ?
सत्य पथ पर चलना सिखाया, मशाल बनी थी
लबों पर क्यों न आई ‘मां’ ?
बहुरानी जब घर में आई
लगने लगी पराई ‘मां’
हिमालय सी अटल, जमाना जिसने देखा
आज क्यों डरी सहमी, घबराई ‘मां’
खाली हाथ लौट आये हम
जब छोटे थे, बाजार से खिलौने लाई ‘मां’
फब्तियां कसते, दो रोटी को तरसती
बढ़ गई यकायक मंहगाई ‘मां’
दवा दारू करते नहीं
फट गई आज बिवाई ₹मां₹
पढी लिखी नहीं, गवार है (हमने समझा)
तभी स्टेज पर शायद, न छा पाई ‘मां’
हमने पाई पाई छिपाई
हाथ दमडी.न आई ‘मां’
नजर न लग जाये, माथे टीका लगाया
टीकिया बिंदिया (के लिए) तरसाई ‘मां’
पानी को भी आज तरसती
समन्दर सी गहराई ‘मां’
मेरा बच्चा, मेरा बच्चा कहकर
जय जय कार सदा लगाई ‘मां’
जीना दुश्वार किया हमनें
नीची क्यों दिखाई ‘मां’ ?
रहमत पर हम उसकी आज भी जिंदा हैं,
नहीं जरा.भी शर्मिंदा है
तू उसकी है, तू उसकी है, हिस्से की बंटाई (आज) ‘मां’
जग में ‘मां’ सा कोई नहीं, ‘मां’ तारणहार
धूप छांव, सुख दुख में सदा भलाई ‘मां’

सुनील कुमार महला, फ्रीलांस राइटर, कालमिस्ट व युवा साहित्यकार, उत्तराखंड।

"संकट का व्यापार: महंगाई, मुनाफाखोरी और सरकारी चेतावनी"

राशन कालाबाजारी पर सरकारी सख्ती: जमीनी हकीकत और खोखले वादे

राशन की कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई के दावे एक बार फिर सुर्खियों में हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये आदेश सिर्फ कागजों तक सीमित रहेंगे या जमीनी स्तर पर भी असर दिखाएंगे? इतिहास गवाह है कि संकट के समय महंगाई, जमाखोरी और भ्रष्टाचार बढ़ जाते हैं, और प्रशासनिक उदासीनता से हालात और बिगड़ते हैं। असली सुधार के लिए पारदर्शी वितरण, तकनीकी निगरानी और सख्त दंड जरूरी हैं, वरना यह भी महज एक खोखला नारा बनकर रह जाएगा।

डॉ सत्यवान सौरभ

जब भी किसी देश में संकट का साया मंडराता है, सबसे पहले आम जनता पर इसका असर पड़ता है। यह एक कड़वी सच्चाई है कि संकट के दौर में महंगाई, कालाबाजारी और जमाखोरी जैसी समस्याएं आम हो जाती हैं। हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के मद्देनजर देशभर में खाद्य पदार्थ, पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कालाबाजारी की खबरें सुर्खियों में हैं। इन मुश्किल हालातों के बीच सरकार ने जमाखोरों और कालाबाजारी करने वालों पर सख्त कार्रवाई का ऐलान किया है। सवाल यह है कि क्या इन घोषणाओं से वास्तव में कोई फर्क पड़ेगा या फिर यह भी अन्य सरकारी वादों की तरह सिर्फ कागज़ी सख्ती बनकर रह जाएगी?

इतिहास गवाह है कि जब-जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा है, तब-तब न केवल सीमावर्ती इलाकों में, बल्कि पूरे देश में खाद्य पदार्थों और ईंधन की किल्लत का माहौल पैदा हुआ है। यह समस्या केवल आर्थिक नहीं, बल्कि राजनीतिक भी है। राजनीतिक लाभ के लिए कई बार जमाखोरी और कालाबाजारी को न केवल नजरअंदाज किया जाता है, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से प्रोत्साहित भी किया जाता है। सरकारें अक्सर महंगाई और किल्लत को 'राष्ट्रीय सुरक्षा' के नाम पर सही ठहराती रही हैं। यह एक प्रचलित नीति है कि संकट के समय लोगों का ध्यान भटकाने के लिए देशभक्ति की भावना को उभारा जाता है, लेकिन इसका खामियाजा आम नागरिक को भुगतना पड़ता है।

सरकार द्वारा जारी सख्त निर्देशों के बावजूद, जमीनी स्तर पर इनका क्रियान्वयन हमेशा से एक बड़ी चुनौती रहा है। आमतौर पर, प्रशासनिक अधिकारी इन्हें गंभीरता से नहीं लेते या फिर स्थानीय व्यापारियों और नेताओं के दबाव में आंखें मूंद लेते हैं। यह एक खुला राज है कि कालाबाजारी करने वाले अक्सर राजनीतिक संरक्षण में फलते-फूलते हैं। ऐसे में यह सवाल उठता है कि क्या सिर्फ आदेश जारी कर देने से समस्या का समाधान हो जाएगा? क्या प्रशासनिक मशीनरी अपने काम में पारदर्शिता और ईमानदारी से कार्य करेगी या फिर यह भी केवल फाइलों में बंद होकर रह जाएगा?

जब जमाखोरी होती है, तो इसका सबसे बुरा असर आम जनता पर पड़ता है। महंगाई आसमान छूने लगती है, जरूरी वस्तुएं बाजार से गायब हो जाती हैं, और लोगों को मजबूरी में अधिक कीमत चुकानी पड़ती है। सरकारें राहत पैकेज और सस्ते राशन की योजनाएं तो बनाती हैं, लेकिन उनका लाभ ज़रूरतमंदों तक पहुंचना अक्सर एक चुनौती बन जाता है। इसके पीछे केवल भ्रष्टाचार ही नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर जागरूकता की कमी भी एक बड़ी समस्या है। गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों को इसका सबसे अधिक खामियाजा उठाना पड़ता है।

सरकार ने साफ कर दिया है कि जमाखोरी और कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई होगी, लेकिन क्या यह वादा हकीकत में बदल पाएगा? क्या सरकारी तंत्र इस बार वाकई में सख्त रुख अपनाएगा या फिर यह भी अन्य सरकारी निर्देशों की तरह समय के साथ फीका पड़ जाएगा? वास्तविक सुधार तभी संभव है जब सरकार अपने सख्त निर्देशों को जमीनी हकीकत में बदलने के लिए ठोस कदम उठाए।

हर जिले में वस्तुओं की उपलब्धता और वितरण की पारदर्शी जानकारी दी जाए। इससे आम जनता को वस्तुओं की वास्तविक स्थिति का पता चल सके और अफवाहों का अंत हो।डिजिटल प्लेटफॉर्म और ट्रैकिंग सिस्टम का उपयोग कर स्टॉक और मूल्य में पारदर्शिता लाई जाए। तकनीकी साधनों का उपयोग करके जमाखोरी और कालाबाजारी की निगरानी करना आज के डिजिटल युग में आसान हो सकता है।

दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई के साथ-साथ सार्वजनिक रूप से नाम उजागर किया जाए ताकि लोग इस तरह की गतिविधियों से दूर रहें। जनता को इस लड़ाई में भागीदार बनाया जाए ताकि कालाबाजारी करने वालों की पहचान आसानी से हो सके। सामुदायिक सतर्कता समूहों का गठन किया जाए जो नियमित रूप से बाजार की स्थिति पर नजर रखें। संकट के समय गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों को आर्थिक सहायता और सब्सिडी के माध्यम से राहत दी जाए।

सिर्फ घोषणाओं से समस्याएं खत्म नहीं होतीं, बल्कि ठोस और ईमानदार क्रियान्वयन से ही सुधार संभव है। अगर सरकार वास्तव में कालाबाजारी पर नकेल कसना चाहती है, तो उसे अपनी नीतियों और प्रशासनिक ढांचे में बदलाव करना होगा। वरना, यह सख्ती भी महज एक 'खोखला नारा' बनकर रह जाएगी। जनता को भी सतर्क रहना होगा, ताकि कोई जमाखोर उनका हक न छीन सके।

केवल आदेश और घोषणाओं से समस्याएं समाप्त नहीं होतीं, बल्कि ठोस और ईमानदार क्रियान्वयन से ही सुधार संभव है। सरकार को यह समझना होगा कि महंगाई और कालाबाजारी का मुद्दा केवल आर्थिक नहीं, बल्कि एक नैतिक और राजनीतिक चुनौती भी है। जब तक प्रशासनिक तंत्र में पारदर्शिता, जवाबदेही और इच्छाशक्ति नहीं होगी, तब तक जमीनी सुधार की उम्मीद बेमानी है। सरकारी नीतियों का केवल कागजी सख्ती तक सीमित रह जाना न केवल जनता के साथ विश्वासघात है, बल्कि एक लोकतांत्रिक देश के मूल सिद्धांतों का भी अपमान है।

इसके अलावा, आम जनता को भी अपनी भूमिका निभानी होगी। जमाखोरों और कालाबाजारी करने वालों की पहचान में सहयोग करना, जरूरतमंदों की मदद करना और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहना समय की मांग है। सिर्फ आलोचना से समस्या का हल नहीं होगा, बल्कि सामूहिक प्रयास से ही एक स्वस्थ और समतामूलक समाज का निर्माण हो सकता है। वरना यह सख्ती भी महज एक 'खोखला नारा' बनकर रह जाएगी, और आम आदमी का संघर्ष कभी खत्म नहीं होगा।

जंग के बीच बड़ी खबर : सरकार ने राज्य के सभी जिला कलेक्टरों आरडीसी और आईपिस की छुट्टियां रद्द की

मनोरंजन सासमल, स्टेट हेड ओड़िशा

भुबनेश्वरः भारत-पाकिस्तान तनाव के बीच बड़ी खबर। राज्य के सभी जिला कलेक्टरों और आरडीसी की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। राज्य सरकार ने छुट्टियां रद्द कर दी हैं। देश के पश्चिमी भाग में युद्ध जैसे हालात के चलते छुट्टी पर गए जिला कलेक्टर और आरडीसी को तुरंत मुख्यालय लौटकर काम पर लौटने को कहा गया है।इस समय कोई छुट्टी नहीं दी जाएगी। इस संबंध में लोक प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है।

इसी तरह सभी आईपीएस अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। गृह विभाग के अपर सचिव ने इस संबंध में पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखा है। सीमा पर युद्ध जारी रहने के दौरान कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसे ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है।

संकट का व्यापार

संकट की आहट से, बाजार थरथराए,
महंगाई की लहर से, घर-घर हिल जाए।
कागजी हुक्मनामा, सख्ती के सुर गाए,
पर हकीकत की धरती, झूठ की चादर फैलाए।

राशन के थैले, खालीपन से भरे,
कालाबाजारी की चालों में, सपने टूटे, बिके, मरे।
नेताओं की घोषणाएं, जश्न की तरह गूंजती हैं,
पर दुकानों की अलमारियाँ, भूख की चीख से घबराती हैं।

जनता को बंधी पगडंडियों पर दौड़ाया जाता है,
हर बार नया नारा, हर बार नया वादा रचाया जाता है।
पर कालाबाजारी की हवाओं में, सच का दम घुट जाता है,
कानून की स्याही, मुनाफाखोरी की चालों से बिखर जाता है।

सरकारी आदेशों की तलवारें, कागज पर तेज़ होती हैं,
पर जमीनी हकीकत, इनसे आँखें चुराती हैं।
कौन पूछेगा, कौन रोकेगा, जब खुद रक्षक ही भक्षक बन जाएं,
जब सत्ता के गलियारों में, मुनाफाखोर गीत गाएं।

यह वक्त है, जब जनता को जागना होगा,
अपने हक की लड़ाई में, खुद को परखना होगा।
सिर्फ आदेशों से नहीं, इरादों से बदलाव आएगा,
वरना यह सख्ती भी, महज एक 'खोखला नारा' बनकर रह जाएगा।

– प्रियंका सौरभ

ओड़िशा की नयागढ़ जिले के रणपुर में ड्रोन उड़ने से लोग घबरा गए, पुलिस को सूचना दी

मनोरंजन सासमल, स्टेट हेड ओड़िशा ओड़िशा

भूबनेश्वर : भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई है। भारत ने पाकिस्तान में आतंकवादी अड्डे पर हमला कर उसे नष्ट कर दिया है। भारत भी पाकिस्तान के जवाबी हमले पर सिर हिला रहा है। इस युद्ध की स्थिति के बीच, कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने शुक्रवार रात ओड़िशा की नयागढ़ जिले के रणपुर ब्लॉक क्षेत्र के आसमान में एक ड्रोन उड़ते हुए देखने की सूचना दी।शुक्रवार शाम गौरांगपुर पंचायत के बिलगड़िया गांव के ऊपर एक बड़ा ड्रोन उड़ता देख लोग घबरा गए। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि यह ड्रोन शादी-ब्याह व अन्य समारोहों में इस्तेमाल होने वाले ड्रोन से बड़ा था और इसका आकार छत के पंखे जैसा था। शाम को ड्रोन देखा गया, लेकिन रात 10 बजे भी यह उड़ रहा था, जिससे लोगों में दहशत फैल गई और लोगों ने इसकी सूचना रानपुर थाने में दी। पुलिस ने बताया है कि इस संबंध में जांच चल रही है।

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत ईमेल के माध्यम से भी मांगी जा सकती है सूचनाएं

CWP-36226-2018 1

IN THE HIGH COURT OF PUNJAB AND HARYANA
AT CHANDIGARH

(300-4) CWP-36226-2018
Date of Decision : February 19, 2025

Dr. Sandeep Kumar Gupta ... Petitioner

Versus

State Information Commission, Haryana and others ... Respondents

CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE HARSIMRAN SINGH SETHI

Present: Mr. Sandevinder Goyal, Advocate, for the petitioner.
Mr. Gaurav Jindal, Addl. A.G., Haryana, for respondent No.1.
Mr. Puneet Gupta, Advocate, for respondents No. 2 and 3.

HARSIMRAN SINGH SETHI J. (ORAL)

1. In the present writ petition, the grievance being raised by the petitioner is that the petitioner had sought information through e-mail by depositing the required fees in the bank account of respondent public authority but the said information has not been supplied to him on the ground that the petitioner has not submitted a written application appending his signatures.

2. Learned counsel for the petitioner submits that even the Information Commission has not accepted the said form of demand of information though the same is covered under Section 6 of the Right to

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट चंडीगढ़ ने डॉक्टर संदीप कुमार गुप्ता बनाम राज्य सूचना आयोग हरियाणा और अन्य के मामले में किया स्पष्ट।

चण्डीगढ़: माननीय जस्टिस हरसिमरन सिंह सेठी याचिका संख्या सीडब्ल्यूपी-36226-2018 दिनांक 19 फरवरी 2025 को ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए यह स्पष्ट कर दिया कि आरटीआई के लिए लिखित आवेदन और हस्ताक्षर के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। सूचना ईमेल के माध्यम से भी फीस भरकर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 की उपधारा 1 के तहत मांगी की जा सकती है।

माननीय पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने एक हम फैसले में यह साबित कर दिया कि आरटीआई के लिखित आवेदन और हस्ताक्षर के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। ईमेल के माध्यम से फीस भरकर सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जानकारी मांगी जा सकती है। इस मामले में डॉक्टर संदीप कुमार गुप्ता द्वारा ईमेल के माध्यम से आवश्यक शुल्क जमा करवाकर हिसार विश्वविद्यालय प्रशासन से जानकारी मांगी गई थी। विश्वविद्यालय द्वारा लिखित हस्ताक्षरित आवेदन की मांग करते हुए जानकारी देने से साफ मना कर दिया था।

माननीय जस्टिस हरसिमरन सिंह सेठी की अध्यक्षता में सुनवाई के दौरान माननीय अदालत ने स्पष्ट किया की सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 की उपधारा 1 के तहत ईमेल के माध्यम से सूचना मांगने का भी प्रावधान है। जब आवेदक अपनी पहचान सत्यापित कर चुका है तो लिखित हस्ताक्षरित आवेदन की मांग गैर जरूरी है।

माननीय अदालत ने विश्वविद्यालय को निर्देश दिया की याचिकाकर्ता को उनकी मांगी गई जानकारी 30 दिनों के अंदर मुहैया करवाई जाए, यह फैसला पारदर्शिता और सूचना के अधिकार के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है।

माननीय अदालत ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा कि आरटीआई आवेदन दाखिल करते समय हस्ताक्षर अनिवार्य नहीं है, केवल आवेदक को अपनी पहचान साबित करनी होगी।

यह आदेश हरियाणा सूचना का अधिकार (संशोधन) नियम 2021 को प्रभावित करते हैं जो आरटीआई आवेदन दाखिल करने वालों को अपनी पहचान का प्रमाण प्रस्तुत करना अनिवार्य करता है।

आदेश में कहा गया कि आवेदक अपनी पहचान पासपोर्ट, मतदाता कार्ड, पैन कार्ड, पीपीआईडी, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस, परिचालक लाइसेंस या सरकार द्वारा जारी किसी ने पहचान पत्र से साबित कर सकता है।

यह ध्यान रखना अनिवार्य है कि आरटीआई आवेदन में हस्ताक्षर की आवश्यकता पहले थी लेकिन अब माननीय अदालत ने इसे अनिवार्य नहीं माना है।

यह आदेश आरटीआई आवेदनों के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव है क्योंकि यह उन्हें आवेदन दाखिल करने में अधिक लचीलापन प्रदान करता है।

ममता की मूरत मां

' ममता की छांव में वह वास्लय व स्नेह को सदैव देने वाली कोई और नहीं मां ही है। मातृत्व के उस रिश्ते के नाम अब ना जाने क्या क्या हो गया है। अम्मा का शब्द जब हम बोलते थे, तो हमें हमारी और वह चुंबकीय तरंगों सा हमें खिंचता था। समय बदलता चला गया माता श्री, मां की वह कोमलता में अपनापन जुड़ गया और माता श्री से अम्मा उसके बाद मां का संसार रंग-बिरंगा हो गया। जहां मां है वह खुशियों का असमान भरा हुआ है। हर एक दौर में हर एक जिम्मेदारी लेने वाली वह मां ही होती है। अपने बच्चों के लिए उसका फ़र्ज़ हमेशा सर्वोपरि रहता है। हर एक मां सर्वप्रथम अपनी संतान का ही पक्ष रखती है। चाहे वह लायक़ हो या नालायक उसके लिए मां का ह्रदय समान्य ही रहता है। अपने बच्चों को वह भर पेट भोजन करतीं हैं चाहे वह खुद भूखे रह जाएं। मां तो भगवान की भी प्रिय होती है, चाहे राम हो या कृष्ण ममता का वह स्नेह व वात्सल्य सभी ने महसूस किया है। उसकी ममता का सुख उन्होंने भी पाया है, क्योंकि मां तो मां होती है। आज के दौर में मां से मम्मी और मम्मी से मॉम बन गई। आधुनिकता की के साये में आज भी वह ढाल बनकर मॉम हमें अपने हाथों से भोजन करतीं हैं। उसकी चुस्ती-फुर्ती अच्छे-अच्छे को दांतों तले उंगली दबा लेने पर मजबूर कर देते हैं। ममता के हर एक रंग में वहीं लाड़-प्यार व भोजन में मीठास रहती है जो सालों से हम खाते आ रहे हैं। तभी तो मॉम के हाथों कोई दुसरा स्वाद नहीं वहीं है। नाम भले कितने बदल जाएं वह अपनेपन का लगाव कभी भी खत्म नहीं होता और बच्चे कितने भी बड़े हो जाएं मां के लिए वह हमेशा छोटे ही होते हैं। जबकि दादी नानी बनने के बाद भी मां के व्यवहार में कोई भी बदलाव नहीं आता। वह आशीष देते हुए दोनों हाथों में प्यार दुलार करती है। यह हम बच्चों के लिए बहुत बड़ी बात होती है। तभी तो मां हमेशा से ममता की मूरत है। वह संवेदनाओं की सीढ़ी है हमारे लिए और वह सच्ची दोस्त वह हमारी प्यारी मां है। माता पिता का इतिहास जब भी लिखा जाएगा मां का नाम सबसे ऊपर होगा, मां शिल्पकार है जो अपने हाथों से अपने बालक को निखारती व संवरती है। मां ऐसी प्रेरणास्रोत हैं जो हम राह भटके हुए बच्चों को सही व सच्ची राह दिखाती है। मेने तुम्हे नहीं देखा मां, तेरी सूरत क्या होगी, तेरी सूरत से अलग भगवान की मूरत क्या होगी। हे मां पूजनीय आप कहीं भी हो चाहे आसमान में पर आप का आशीष हमारे लिए दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि मां ममता की मूरत है।

मां ममता की छांव है
मां स्नेह दुलार प्यार की परछाई है
मां रिश्तों में मजबूती
मां भरोसे में विश्वास
मां हम बच्चों की सबसे पहली जरूरत पर आज मेरी मां नहीं है ?
उनका आशीर्वाद जरूर हमारी रक्षा कर रहा है
क्योंकि मां एक अनमोल उपहार है
हम बच्चों का प्यार है, मां नहीं रहती तों यह संसार अधुरा क्योंकि मां तो मां होती है...।।

हरिहर सिंह चौहान

देशविरोधी कुचक्रिय तत्व : लगे हाथ एक गणना इनकी भी हो जाए'

सुशील कुमार 'नवीन'

पहलगाम हादसे के बाद भारत-पाकिस्तान के बीच अघोषित युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। इसका परिणाम क्या रहेगा? यह अभी भविष्य के गर्भ में है। इस गंभीर माहौल की जहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक चिंतन हो रहा है वहीं कुछ कुचक्रिय तत्व अभी भी सक्रिय है। जातीय जनगणना तो जब होगी सो होगी, इससे पहले ऐसे लोगों की गणना बहुत जरूरी है। जो भारत में रहते हैं और भारतीय नहीं है। जो इसी मिट्टी में जन्मे हैं और इसी के विखंडन का स्वप्न देखते हैं। जो यही कमाते हैं और इसका प्रयोग इसी के खिलाफ करते हैं। युद्ध अपने तरीके से चलता रहेगा, युद्ध के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे लोगों की पहचान आज इस घड़ी में करना बेहद जरूरी है। जयचंदों की फौज जिस तरह से बढ़ रही है वो भविष्य के लिए अच्छा संकेत नहीं है। चाणक्य नीति में साफ लिखा गया है कि -

परोक्षे कार्यहन्तारं प्रत्यक्षे प्रियवादिनम्।
वर्जयेत्तादृशं मित्रं विषकुम्भं पयोमुखम्॥

इसका सीधा सा भाव है कि पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाले और सामने मीठा बोलने वालों को उसी प्रकार त्याग देना चाहिए, जिस प्रकार मुख पर दूध तथा भीतर विष से भरे घड़े को त्याग दिया जाता है।

एक सच्चे देशभक्त का इस समय कर्तव्य बनता है कि आपदा आने के समय वो आपसी गिले शिकवे भूल एकमत से राष्ट्रहित में ली गई प्रत्येक कार्रवाई का समर्थन करे। उसमें यथोचित सहयोग करें, उसका संबल बनें। किसी तरफ की छींटाकशी, मीनमेख निकाल दूसरे पक्ष के लिए उदाहरण बनना राष्ट्रविरोधी से कमतर नहीं है। देश आज जिस संकट से गुजर रहा है वह हमारे द्वारा पैदा नहीं किया गया है। गीता का प्रसिद्ध श्लोक यहां सार्थक सिद्ध है। इसके अनुसार कहा गया है -

कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।
मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि॥

युद्ध से इनकार किए जाने पर श्रीमद्भगवद्गीता में भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन से कहते हैं - तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करना है। कर्म के फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। इसलिए तुम केवल निरन्तर कर्म करो। कर्म के फल पर मनन मत करो और अकर्मण्य भी मत बनो।

संसार का कोई भी ऐसा देश नहीं है। जहां राष्ट्रविरोधी ताकतें मुंह बाए न खड़ी हो। दुश्मन राष्ट्र से ज्यादा खतरा राष्ट्र के अंदर छिपी पड़ी इन कुचक्रियों से होता है। वक्त बेवक्त इनका सिर्फ एक उद्देश्य होता है कि किसी भी तरह से अपनी विचारधारा को ज्यादा से ज्यादा प्रसारित किया जाए। इन्हें इस बात से मतलब नहीं कि देश किस स्थिति से गुजर रहा है। उन्हें सिर्फ अपनी विचारधारा को अग्रसर रखना होता है, चाहे वो विचारधारा राष्ट्रविरोधी ही क्यों न हो।

आज के समय को ही ले लीजिए। पक्ष-विपक्ष आज सरकार के साथ खड़ा है। फिर भी कुछ लोगों की जुबान नहीं रुक रही है। इसी का फायदा सोशल मीडिया के माध्यम से पाकिस्तान द्वारा उठाया गया है हमारे ही लोगों द्वारा की गई बयानबाजी का प्रयोग हमारे ही खिलाफ उनके द्वारा खूब किया गया है। कन्हैयालाल मिस्र का एक निबंध मै और मेरा देश पढ़ा हो तो उसकी एक पंक्ति आज के समय में अपनी सार्थकता को पूर्ण सिद्ध करती है कि युद्ध में जय बोलने वालों का बड़ा महत्व है। भाव यह है कि युद्ध करना हर किसी के सामर्थ्य में नहीं है। लेकिन अपने साथियों का उत्साह बढ़ाना तो हमारे हाथ में है। लेकिन हम है कि अभी भी बाज नहीं आ रहे। आलोचना या समीक्षा का अभी वक्त थोड़े ही है। अभी तो जो हो रहा है उसे होने दें। वो चाहे अच्छा है या बुरा। हमारा पहला फर्ज बनता है कि उसमें सहयोग करें। लोकतंत्र में सबको बोलने का अधिकार है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। एक छोटी सी चिनगारी की उपेक्षा से दावानल की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

प्राचीन भारत के महान अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और दार्शनिक आचार्य चाणक्य के विचार आज भी प्रासंगिक हैं। उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए जीवन सिद्धांत और रणनीतियां न केवल राजनीति, बल्कि व्यक्तिगत जीवन में भी सफलता प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करने का कार्य करते हैं। उनके द्वारा बताये गए नियमों में जीवन की कठिनाइयों का सामना करने और सही दिशा में आगे बढ़ने के उपाय दिए गए हैं। ये न केवल आत्मनिर्भर बनाते हैं, बल्कि जीवन में बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भी प्रेरित करते हैं।

आचार्य चाणक्य के अनुसार यदि आपका कोई शत्रु है तो कमजोरियों का पता लगाकर कमजोर करो। शत्रु को नष्ट करने से पहले उसे हराना बहुत जरूरी है। चाणक्य का कहना था कि सच्चाई अक्सर कड़वी होती है, लेकिन यह हमेशा सही होती है, यदि हम सच्चाई को अपनाते हैं, तो जीवन में हमें कोई पछतावा नहीं होगा। आचार्य चाणक्य राष्ट्र शब्द को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि राष्ट्र केवल किसी भूखंड मात्र नहीं होता। राष्ट्र संस्कृति, सभ्यता, परंपरा, भाषा, इतिहास इन पांचों विषयों का बोध होता है। उनके अनुसार देश में जन्मे प्रत्येक व्यक्ति को राष्ट्र निर्माण के प्रति समर्पण का भाव रखना ही सच्ची राष्ट्र सेवा है। अपने नीति सूत्रों के माध्यम से आचार्य चाणक्य ने तत्कालीन सुप्त जनमानस के पटल पर राष्ट्रीय स्वाभिमान एवं आत्मगौरव की भावना को जाग्रत किया। देश के आत्मगौरव और आत्मस्वाभिमान को सुदृढ़ एवं अखंड रखने के लिए अनिवार्य है राष्ट्र की एकता एवं संगठन। चाणक्य का विचार था कि 'राष्ट्रीय एकता राष्ट्र रूपी शरीर में आत्मा के समान है। जिस प्रकार आत्मा से हीन शरीर प्रयोजनहीन हो जाता है, उसी प्रकार राष्ट्र भी एकता एवं संगठन के अभाव में टूट जाता है।

ऐसे में आज हम सब का भी दायित्व बनता है कि समाज एवं राष्ट्र स्तर पर कहीं भी कुछ ऐसा घटित हो रहा है जो राष्ट्रहित में नहीं है तो एक सजग भारतीय की तरह उस पर मुखर हो। गलत देखकर चुप रह जाना भी किसी अपराध से कम नहीं होता। राष्ट्र-विरोध की स्थितियों से संघर्ष करना समय की जरूरत है। उनसे पलायन करने से राष्ट्रीयता सशक्त मजबूत नहीं हो सकती। महाभारत के शान्तिपर्व में लिखा गया है -

दुर्जनः परिहर्तव्यः विध्ययालंकृतोऽपि सन्।
मणिना भूषितः सर्पः किमसो न भयंकरः॥

दुर्जन व्यक्ति यदि विद्या से भी अलंकृत हो फ़रि भी उसका छोड़ देना चाहिए। मणि से भूषित सांप क्या भयंकर नही होते?

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095. newstransportvishesh@gmail.com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। RNI No :- DELHIN/2023/86499. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023